चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 07 नवंबर– 13 नवंबर 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

कश्मीर दर्द से

चीख़ रहा है

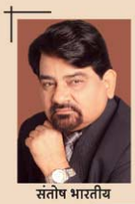

संतोष भारतीय

मैं बैठा सोच रहा था कि कश्मीर में क्या हो रहा होगा? मैं अपने दो पत्रकार मित्रों अशोक वानखेड़े और अभय दुबे के साथ, जब 11 से 13 सितंबर को श्रीनगर में था, तो श्रीनगर की वो तस्वीर सामने आई, जिसका दिल्ली में बैठ कर एहसास ही नहीं हो सकता. तब लगा कि जो लखनऊ, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरू या चेन्नई में हैं, वो तो कश्मीर के आज के हालात की कल्पना ही नहीं कर सकते कि क्यों दुकानें बंद हैं, क्यों लड़के पत्थर चला रहे हैं, क्यों लड़के सड़क पर पत्थर रख कर सड़क को बंद कर रहे हैं और क्यों अपने आप पत्थर साफ कर सड़कें खोल देते हैं? क्यों दुकानदार ठीक शाम छह बजे दुकानें खोल देते हैं, सरकारी बैंकों ने क्यों अपना समय शाम छह बजे से कर दिया है? ये सारे सवाल आंधी की तरह दिमाग़ में इसलिए उड़ने लगे कि हमें तो श्रीनगर जाकर इन सवालों का जवाब मिल गया, लेकिन क्या देश के लोग कभी इस सच्चाई को समझ पाएंगे? फिर एक और सवाल कौंधा कि पूरे देश में कहीं भी एक दिन का बाज़ार बंद कराने का स्लोगन जब कोई राजनीतिक दल करता है, तो लोग दुकानें बंद नहीं करते हैं. उन दुकानों को बंद कराने के लिए राजनीतिक दलों के युवा कार्यकर्ता लाठी लेकर सड़क पर निकलते हैं, तब वो एक दिन के लिए दुकानें बंद करा पाते हैं, लेकिन कश्मीर 105 दिनों से बंद था. सिर्फ एक काग़ज़ का पर्चा कैलेंडर के रूप में निकलता है और लोग उसका पालन करते हैं.

> “कश्मीर एक दर्द के धुंध के बीच घिरा हुआ इलाक़ा है. सरकार कोई भी फैसला करे तो ये मान कर करे कि यहां के 60 लाख लोगों को या तो वह अपने पक्ष में करना चाहती है या 60 लाख लोगों को अपने विरोध में करना चाहती है. कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां बंद हैं. कोई विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सकता है. मंत्री अपने दफ्तरों में आराम से नहीं जा सकते हैं. कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं. प्रधानमंत्री जी, आपके हाथ में चाबी है, आप कृपया श्रीनगर जाएं. दो दिन वहां रहें और वहीं फैसला लें कि कश्मीर के लिए क्या करना है.”

श्रीनगर में मैंने जो देखा

इन सारे सवालों ने मुझे बेचैन किया, तो मैंने अगले दिन फिर से श्रीनगर जाने का फैसला किया क्योंकि 27 अक्टूबर से सरकार चार या पांच महीने के लिए जम्मू चली जाती है और श्रीनगर सरकारी अफ़सरों, सरकारी अमलों, मुख्यमंत्री व मंत्रियों से ख़ाली हो जाता है. सारे लोग जम्मू में होते हैं. यहां रह जाते हैं वो, जो यहां नहीं जा सकते हैं, जिनका यहां व्यापार है, जिन्हें श्रीनगर में पढ़ना है, जिन्हें श्रीनगर में रहना और सरकार से कोई ख़ास काम नहीं है. मुझे लगा कि इस स्थिति को देखना चाहिए.

मैं जब श्रीनगर पहुंचा, मुझे लेने श्रीनगर के हमारे वरिष्ठ संवाददाता हारून रेशी आए हुए थे. हारून रेशी ने रास्ते में बताया कि दुकानें वैसे ही बंद हैं, पत्थर चलने कम हो गए हैं, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं. अपेक्षा है कि प्राइवेट गाड़ियां भी कम चलें, पर वो गाड़ियां जिनमें पैसेंजर चलते हैं, वो लगभग नहीं के बराबर चल रही थीं. पुलिस का पहरा कहीं-कहीं था, लेकिन पुलिस का पहरा इसलिए नहीं था कि दुकानें बंद हों, कर्फ्यू इसलिए नहीं लगा था कि दुकानें बंद हों, बल्कि पुलिस का पहरा और कर्फ्यू इसलिए था कि अगर लोग चाहें, तो अपनी दुकानें खोल लें. सरकार उन लोगों को रोकेगी, जिन्हें आम भाषा में दुकानें बंद कराने वाला कहा जाता है, लेकिन लोग अपनी दुकानें नहीं खोल रहे थे. इसका मतलब, श्रीनगर के लोगों का साहस और धैर्य कमज़ोर नहीं हुआ था. भारत सरकार का ये आकलन कि हड़ताल करते-करते लोग थक जाएंगे और फिर वे अपनी दुकानें खोल देंगे, ग़लत साबित हुआ. भारत सरकार का ये आकलन, जिसे गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने घोषित किया था कि वो 7 दिन में स्थिति को सामान्य कर देंगे और उन्होंने सुरक्षाबलों को ये आदेश दिया था कि 7 दिनों में उन्हें कश्मीर की स्थिति सामान्य मिलनी चाहिए. उस समय लोगों को ये लगा था कि सरकार क्या करेगी, क्या सरकार गोलियां चलाएगी, लोगों को और जेल में भरेगी, लोगों की जान को और ख़तरा बढ़ जाएगा. राजनाथ सिंह द्वारा 11 सितंबर को की गई ये घोषणा, श्रीनगर में 12 तारीख़ के अख़बारों में छपी थी. अब अक्टूबर समाप्त हो रहा है. राजनाथ सिंह का एक सप्ताह, एक महीने से ज्यादा वक्त ले चुका है, लेकिन वो एक हफ्ता नहीं आया, जिसमें सरकार और सुरक्षाबलों की अपेक्षाओं से स्थिति सामान्य हुई हो. इस बीच सरकार ने बात भी नहीं की. किसी प्रतिनिधिमंडल को नहीं भेजा. मुख्यमंत्री ने भी किसी से बात नहीं की. मुख्यमंत्री बात करके करतीं भी क्या? लोगों की अपेक्षा तो दिल्ली की सरकार से थी और दिल्ली की सरकार ने अपने आंख और कान दोनों बंद कर लिए थे.

प्रोफेसर बट ने मीरवाइज़ से मिलने की सलाह दी

मैंने सोचा कि मुझे शहर में प्रोफेसर अब्दुल ग़नी बट से शुरुआत करनी चाहिए, जो जेल से बाहर हुर्रियत के सबसे बड़े नेता हैं. मैं सीधे प्रोफेसर बट के पास गया और उनसे मैंने कहा कि अब क्या हालात हैं और अब क्या होना चाहिए? ग़नी बट प्रोफेसर रहे हैं, चीज़ों को तार्किक ढंग से समझते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं. उन्होंने एक लंबा विश्लेषण मुझे दिया, साथ ही मेरे सर पर हाथ रख कर इस बात की शाबासी दी कि आप ने जो काम किया है, कश्मीर की तकलीफ़ को जिस तरह आप कश्मीर से बाहर ले गए हैं, वो क़ाबिले तारीफ़ है. मैंने उनसे कहा कि मैं पत्रकार हूं, मेरा काम ब्रेकथ्रू नहीं है. उन्होंने कहा कि आप पत्रकार के साथ इंसान भी हैं और हमारा जो दर्द है, आंसू है, इनकी जानकारी, इनकी पीड़ा देश के बाक़ी हिस्से के लोगों को होनी चाहिए. उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि इस दर्द को कम होने में उससे ज़रूर मदद मिलेगी. मैंने प्रोफेसर बट से पूछा कि विद्यार्थियों का एक साल ख़राब होने वाला है, बोर्ड की परीक्षा वो नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हां, बोर्ड की परीक्षा वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहां तो ज़िंदगी की परीक्षा में ही फेल या पास होने का सवाल पैदा हो गया है. अगर मान लीजिए कि बोर्ड या स्कूल की परीक्षा का सवाल उठाया भी जाए, तो कौन परीक्षा देगा? बच्चे तो जेल में हैं. उन्होंने डेढ़ घंटे के भीतर तीन बार चाय पिलाने और बिस्किट खिलाने के बाद ये सुझाव दिया कि मुझे हर हाल में मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ से मिलना चाहिए, जो जेल में बंद हैं. मैंने कहा कि मैं कैसे मिल

(शेष पृष्ठ 2 पर)

हम 1947 के जम्मू-कश्मीर की बात कर रहे हैं : गिलानी | P-4

जंग से मसाइल पैदा होते हैं हल नहीं : प्रो. अब्दुल ग़नी बट | P-6

आरएसएस ने कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होने दिया : कमल मोरारका | P-8

कश्मीर दर्द से चीख़ रहा है

पृष्ठ 1 का शेष

सकता हूं उनसे, तो उन्होंने कहा कि कोशिश कीजिए. मुझे मालूम है आप जिस तरह के पत्रकार हैं, अगर ठान लेंगे, तो ज़रूर मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ से मिल पाएंगे.

प्रोफेसर बट की बातों ने मन को और चिंतित कर दिया. मैं वहां से होटल पहुंचा, सामान रखा. पहले मैंने सोचा था कि मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि मुझे अपेक्षाकृत कम ख़र्चे वाले सर्किट हाउस में रहने के लिए किसी तरह जगह दिलवाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जैसे ही मैं सरकार से निवेदन करूंगा और अगर सर्किट हाउस में मुझे जगह मिल गई तो मेरे ऊपर ये शक पैदा हो जाएगा कि मैं कहीं सरकार की मिलीभगत से तो श्रीनगर में नहीं घूम रहा हूं. इस एक शंका ने मेरे पांव एक होटल की तरफ़ मोड़ दिए.

मीरवाइज़ से मिलना एक चमत्कार था

होटल में मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कैसे मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ से मिल सकता हूं, क्योंकि प्रोफेसर बट ने मुझे मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ से मिलने की सलाह दी थी. मैंने अपने पत्रकार दोस्तों, अधिकारी दोस्तों, सबसे बात की, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ. तभी एक चमत्कार हुआ. एक शख़्स ने कहा कि आप अगर मोबाइल फोन न ले जाएं, अपनी पहचान का डिंडोरा न पीटें, तो मैं कोशिश करता हूं कि किसी तरीक़े से आपकी मुलाक़ात मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ से हो जाए. मैंने उससे कहा कि नेकी और पूछ-पूछ. उस ईश्वर के बंदे ने पता नहीं कहां, कैसे, क्या चलाया कि मुझे मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ से मिलने की अनुमति मिलने का अंदाज़ा हो गया. फिर, मुझे फोन आया कि मैं फ़ौरन जहां मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ जेल में बंद हैं, वहां आऊं. उस शख़्स ने कहा कि मैं आपको वहां मिलूंगा और कोशिश करूंगा कि मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ से आपकी मुलाक़ात हो जाए. मैं टैक्सी में बैठा, टैक्सी से डल झील के किनारे होता हुआ ऊपर पहाड़ों की तरफ़ गया. श्रीनगर का सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट चश्मेशाही है. चश्मेशाही की तारीफ़ ये है कि वहां लगातार पानी आता रहता है. कहां से आता है, किसी को नहीं पता? उस चश्मेशाही पर्यटक स्थल के पास एक छोटा सा हट बना हुआ है, जिसमें मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ क़ैद हैं. मेरा ड्राइवर ग़नी डल झील के किनारे होते हुए चश्मेशाही की तरफ़ ऊपर चढ़ा. वहां से पुलिस के सिपाही, कुछ जेल के सिपाही दिखाई दिए. सुनसान, कोई नहीं. एक जगह मुझे एक शख़्स ने रोक दिया कि आप इससे आगे नहीं जा सकते. फिर मुझे अपने उस संपर्क से बात करनी पड़ी, पता नहीं उसने किस तरह से मैनेज किया कि मुझे कुटिया (हट) तक जाने की इजाज़त मिल गई. कुटिया में मुझसे दरख्वास्त ली गई. उस दरख्वास्त पर ऑफिशियल परमिशन लिखी गई और मैं मीरवाइज़ से मिलने चला गया. बहुत पहले मैं मीरवाइज़ से मिला होऊंगा, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म था कि जो तीन पत्रकार यहां आए थे, उस अंधेरे में उन्होंने जिस तरह एक मोमबत्ती जलाने की कोशिश की थी, उसकी रोशनी ने पूरे श्रीनगर के लोगों के मन में एक आशा की चमक पैदा कर दी थी.

मीरवाइज़ ने मुझे गले लगाया और मुझे अंदर कुटिया में ले गए. हम आपस में देश, दुनिया, कश्मीर के हालात की सारी बातचीत करने लगे और तब मीरवाइज़ ने मुझे बताया कि तीन महीने में आप पहले शख़्स हैं, जो पता नहीं कैसे मेरे पास तक आ गए, जबकि सप्ताह में एक बार मेरे घर के लोग मुझसे मिलने आते हैं. इसके अलावा मैंने किसी बाहरी आदमी का चेहरा नहीं देखा है. मैंने पूछा, तो यहां मिलने कौन आता है? तो उन्होंने कहा, यहां भालू आते हैं. जंगल में जगह है. मैंने पूछा, चूहे. उन्होंने छत की तरफ इशारा किया कि इस छत के अंदर, लकड़ी की छत है, इसके अंदर जब चूहे दिन में दौड़ते हैं, तो पता नहीं चलता, लेकिन सुनसान रात में जब हवा की आवाज़ भी तेज़ लगती है, तब ये चूहे दौड़ते हैं, तो बिल्कुल भूतिया आवाज़ के रूप में वो माहौल तब्दील हो जाता है. और मैं देख रहा था कि मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़, जो कश्मीर के सबसे ज्यादा इज़्ज़त वाले मज़हबी धर्मगुरु हैं, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़, जो हुर्रियत के चेयरमैन हैं, मीरवाइज़ उमर फ़ारूक़, जो काफ़ी पढ़े-लिखे हैं, काफ़ी सौम्य हैं, चीज़ों को समझते हैं और भारत सरकार की तरफ़ से अटल बिहारी जी के ज़माने में वो मुज़फ्फराबाद और इस्लामाबाद भी गए थे, ताकि अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित सुझावों पर उन लोगों को तैयार कर सकें. आज वो मीरवाइज़ अकेले एक कुटिया में बैठे हुए हैं और मैं सोचने लगा कि इन्हें यहां लाकर सरकार को क्या मिला? सरकार इन्हें इनके घर में नहीं रख सकती थी. कम-से-कम आराम से सोते, वो जेल के कर्मचारी उनके साथ हैं, उन्हें ज़बरदस्ती वहां जेल हो गई. दूर बैठे हुए हैं, वो भी अपने यहां रहते.

सेंट्रल जेल में यासीन मलिक से मेरी मुलाक़ात

मीरवाइज़ से लगभग एक-डेढ़ घंटे बात करने के बाद मैं वहां से निकला और निकलने के बाद मैं फिर होटल की तरफ़ चलने लगा कि रास्ते में मुझे लगा कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूं कि यासीन मलिक से भी मिल लूं? यासीन मलिक सेंट्रल जेल में बंद थे. मैंने अपने ऊपर कृपा करने वाले कुछ सज्जनों को फोन किया और कहा कि क्या ये संभव है कि मैं सेंट्रल जेल में यासीन मलिक से मुलाक़ात कर लूं. बहुत सारे लोग मिलने जाते होंगे जेल में, एक मैं भी जा सकता हूं, परमिशन लेकर. वो हंसे और कहे कि अच्छा ठीक है, आप सेंट्रल जेल की तरफ़ अपनी गाड़ी मोड़िए. मैं देखता हूं, क्या कर सकता हूं, पर ये निश्चित नहीं है कि आपकी मुलाक़ात हो ही जाए.

चश्मेशाही से लगभग बीस-पच्चीस मिनट चलने के बाद हम श्रीनगर सेंट्रल जेल पहुंचे और वहां पर किसी तरह हाथ जोड़ते, विनती करते, जेलर साहब से मिलते, पुलिस के चीफ़ से मिलते, अपने को एक साधारण इंसान बताते हुए मिलने की गुज़ारिश की. पता नहीं उस दिन कैसे ईश्वर मेहरबान था कि यासीन मलिक से मिलने की अनुमति भी मिल गई. मैं अंदर गया. मेरा सारा सामान बाहर रखवा लिया गया. यहां तक कि पर्स, जिसमें पैसे और क्रेडिट कार्ड थे, भी बाहर रखवा लिया गया. बिना सोचे, मैंने उसे बाहर छोड़ दिया कि ग़ायब हो जाएगा. ये कार्ड ग़ायब हो सकता है, पैसे ग़ायब हो सकते हैं. कुछ भी नहीं सोचा. मैं सीधे अंदर गया, अंदर जेलर के कमरे में, वो किसका कमरा था, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी अधिकारी का कमरा था, मैं बैठा हुआ था. अधिकारी भी बैठे हुए थे, मुझे घूर रहे थे. मुस्कुराते हुए घूर रहे थे, तब तक देखा कि कंबल ओढ़े यासीन मलिक धीरे-धीरे कमरे के अंदर आए. उन्हें मुझे पहचानने में कुछ वक़्त लगा, लेकिन जब पहचान लिया तो हम पास बैठे. मैंने उनसे बातचीत शुरू की. यासीन मलिक बहुत समझदार शख़्स हैं. यासीन मलिक उस टीम के लीडर हैं, जिस टीम ने कश्मीर के सवाल को दुनिया के सामने पहुंचाने के लिए हाथ में हथियार उठा लिए थे. जब कुलदीप नैयर और जस्टिस सच्चर 90 के शुरुआती दौर में श्रीनगर गए थे, तो उन्होंने उन्हें समझाया था कि आपलोग अगर हथियार रख देंगे, तो आपके साथ हम कश्मीर समस्या के हल के लिए बहुत कुछ कर सकेंगे. यासीन मलिक ने इनलोगों की बात मान ली थी. मैं उस शख़्स को देखता रहा. बीमार होने के बावजूद चेहरे पर एक सख़्ती, जो उसी दिन से जेल में बंद है, जिस दिन बुरहान वानी वाली वारदात हुई. बुरहान वानी की हत्या, शहादत या उनके एनकाउंटर में मारे जाने के दो घंटे बाद यासीन मलिक को क़ैद कर लिया गया.

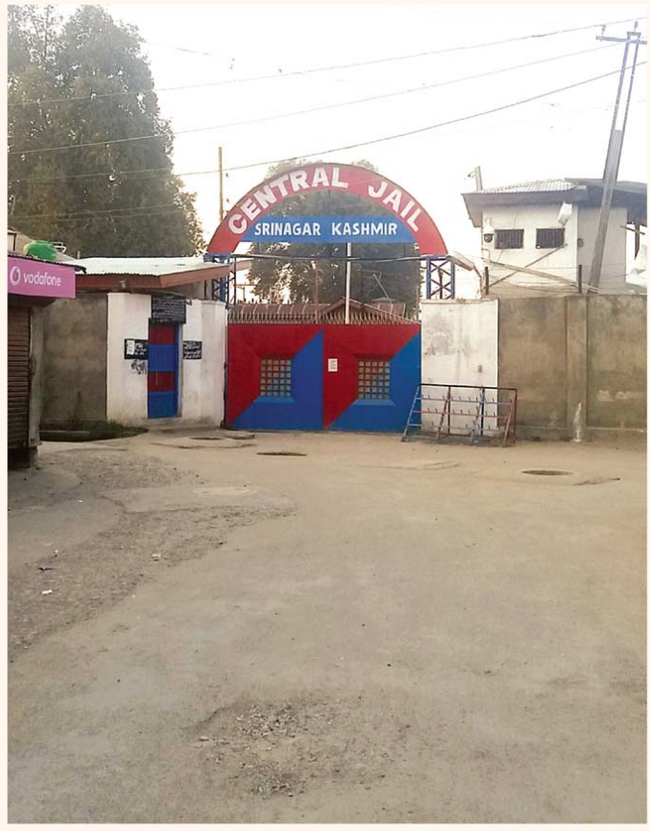

मैंने यासीन मलिक से पूछा कि इसका ब्रेकथ्रू क्या है? उन्होंने कहा कि क्या ब्रेकथ्रू होगा? जो सिचुएशन है, दुनिया के सामने है, पाकिस्तान के भी सामने है, हिंदुस्तान के भी सामने है. जब सरकार का प्रधानमंत्री ये कहे कि हम देश को इज़राइल बनाना चाहते हैं, जिस तरीक़े से इज़राइल स्ट्राइक करता है, हम वैसे ही स्ट्राइक कर रहे हैं. कश्मीर का मसला इस स्ट्राइक और इज़राइल के जुमलों के बीच ग़ायब हो जाता है, तो मैं क्या बात करूं, मैं क्या सोचूं? बहुत तल्ख़ थे यासीन मलिक साहब. बहुत ही तल्ख़. शायद उस नौजवान के मन में हथियार रखते हुए कुलदीप नैयर और जस्टिस सच्चर के वादों के टूटने का मलाल रहा होगा. हर किसी घटना के वक़्त सबसे पहले उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, उसका मलाल रहा होगा. उनकी बात को कश्मीर के बाहर न सुने जाने का दुख रहा होगा. उन्हें अपने साथ हुई हर नाइंसाफ़ी के लम्हे याद आते होंगे. मुझे लगा ये तल्ख़ी और ये सख़्ती उसका एक स्वाभाविक परिणाम है. मैं इसे अस्वाभाविक परिणाम भी कह सकता हूं.

यासीन मलिक से मिलते हुए जब मैं बाहर आने लगा, तो जो जेल का कर्मचारी मुझे बाहर छोड़ने आया, मैंने उससे पूछा कि जेल में सबसे पुराना क़ैदी कौन है? उसने कहा कि इसमें हुर्रियत के ही एक नेता बंद हैं, जो 23 साल से जेल में हैं. मैंने कहा कि 23 साल से जेल में बंद हैं. कहने लगा कि हां, वो एक मामले में छूट कर बाहर निकलते हैं, तब तक पुलिस दूसरा मामला लगा देती है. जब तक वो दूसरे से निकलते हैं, तो तीसरा लगा देती है. आज 23 साल से वो जेल में बंद हैं. तब मुझे लगा कि पुलिस की कार्यप्रणाली सारे देश में एक सी है. वो कश्मीर में अलग है, ऐसा नहीं है. किसी ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही होता है. सरकार जेल से निकलते ही कोई दूसरा आरोप लगा देती है और उन्हें जेल में भेज देती है. चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान पुलिस की कार्यप्रणाली दोनों जगह समान है. कम-से-कम यहां तो दोनों देशों ने व्यावहारिक एकता दिखाई.

कश्मीर की पुलिस और अधिकारी भी नाख़ुश हैं

यासीन मलिक के यहां से निकल कर मैं फिर होटल आया और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए? मैंने दिन भर की सारी घटनाओं के नोट्स लिए. नोट्स लेकर सोचता रहा कि अब मुझे अगले दिन क्या करना चाहिए? तभी मुझे पता चला कि एक पुलिस अफ़सर मुझसे मिलने आए हैं. मैंने उन्हें कमरे में आने का निमंत्रण दिया. हो सकता है वो व्यक्तिगत हैसियत से आए हों, सादे कपड़े में थे, लेकिन हो सकता है जम्मू-कश्मीर या केंद्र सरकार ने उन्हें भेजा हो यह जानने के लिए कि मैं आज कहां-कहां गया? मैंने उनका स्वागत किया. उनसे बातचीत की. वे 15 मिनट के लिए आए थे, लेकिन एक घंटे बैठ गए. उस बातचीत में मुझे पता चला कि जम्मू-कश्मीर के सरकारी अधिकारी, जम्मू-कश्मीर की पुलिस, ये सब इस स्थिति से बहुत नाख़ुश हैं. उनसे लंबी बातचीत के बाद मैंने ये नतीजा निकाला कि अगर सरकार अपनी इस नीति को नहीं बदलती, उसे हर चीज़ के जवाब में गोलियां चलानी है, तो एक दिन गोलियां चलाने वाले लोग कहीं गोली चलाने से इंकार न कर दें. मुझे ये डर लगा. उन्हीं से बातचीत में मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि सरकार ने सख़्ती की इतनी इंतहा कर दी है कि लोगों के मन से इसका डर निकल गया है. लोगों के मन से जेल और मौत का डर निकल गया है. अब ये मेरी समझ में नहीं आया कि अक्सर सरकारें वहीं तक ज़ुल्म करती हैं, जहां तक ज़ुल्म का डर बना रहे, लेकिन अगर ज़ुल्म उस हद को पार कर जाता है, जहां से ज़ुल्म का डर ही समाप्त हो जाए, तो ये बड़ी मूर्खतापूर्ण स्थिति मानी जाती है. जम्मू-कश्मीर में तो कम-से-कम सरकार उस स्थिति को पार कर गई है.

जो 1952 या 1954 में कश्मीर में पैदा हुए, उनकी संख्या लाखों में है, उन्होंने जबसे आंखें खोली हैं, तबसे कर्फ्यू, लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबर की गोलियां और अब पैलेट्स गन देखे हैं. इससे ज्यादा उन्होंने बंदूक़ों से निकली हुई गोलियां देखी हैं, लाशें देखी हैं. उनके लिए यही लोकतंत्र है. जो लोकतंत्र पटना में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, सहारनपुर में है, मुज़फ्फरपुर में है या चेन्नई में है, बंगलुरू में है, हैदराबाद में है, उस लोकतंत्र को तो वो जानते ही नहीं कि वो क्या चीज़ है.

सारी रात मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ़ ये सोचकर कि क्या सरकारें सचमुच हृदयहीन होती हैं, उनका हृदय नहीं होता. वो लोगों का दर्द नहीं समझते. क्या देश के लोग हृदयहीन हो गए हैं, जो कश्मीर की तकलीफ़ को जानना ही नहीं चाहते. जो 370 को कश्मीर के भारत के विलय में एक बाधा मानते हैं. 370 क्या है? महाराजा हरि सिंह के साथ क्या समझौता हुआ था? उसकी शर्तें क्या थीं? संयुक्त राष्ट्रसंघ में कौन गया था? क्या शर्तें थी उसकी? उन शर्तों का पालन किन लोगों ने नहीं किया या नहीं होने दिया, ये सारे सवाल देश के लोगों को क्यों नहीं पता? चूंकि ये सवाल लोगों को नहीं पता हैं, शायद इसलिए पूरा देश इस समय कश्मीर के एक-एक व्यक्ति को पाकिस्तानी मान रहा है और यह मानता है कि पाकिस्तान में शामिल करने के लिए सारे हुर्रियत के नेता जी-जान लगाए हुए हैं. (शेष पृष्ठ 3 पर)

जो 1952 या 1954 में कश्मीर में पैदा हुए, उनकी संख्या लाखों में है, उन्होंने जबसे आंखें खोली हैं, तबसे कर्फ्यू, लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबर की गोलियां और अब पैलेट्स गन देखे हैं. इससे ज्यादा उन्होंने बंदूक़ों से निकली हुई गोलियां देखी हैं, लाशें देखी हैं. उनके लिए यही लोकतंत्र है. जो लोकतंत्र पटना में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, सहारनपुर में है, मुज़फ्फरपुर में है या चेन्नई में है, बंगलुरू में है, हैदराबाद में है, उस लोकतंत्र को तो वो जानते ही नहीं कि वो क्या चीज़ है. दरअसल कश्मीर का लोकतंत्र अलग है और भारत का लोकतंत्र अलग है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 36
07 नवंबर- 13 नवंबर 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त क़ानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कश्मीर दर्द से चीख़ रहा है

पृष्ठ 2 का शेष

सैयद अली शाह गिलानी से एक दिलचस्प मुलाक़ात

मैं सुबह उठा, फिर सोचने लगा कि आज क्या किया जा सकता है. मुझे शाम को दिल्ली वापस चले जाना चाहिए और मैं जिन लोगों से मिला हूं, उनकी बातचीत के आधार पर एक आकलन अपने अख़बार में लिखूंगा. मैं नाश्ता करने के बाद बाहर निकला तो एक शख्स मिला. उसने मुझे पहचान लिया और कहा, आप सच्चे आदमी हैं. आप पहले ऐसे आदमी हैं, जिसने कश्मीर की सच्चाई कश्मीरियों के भी सामने रखी, जिससे हमको लगा कि आप हैं. आपके वो दो साथी कहां हैं?

मैंने कहा कि मैं उन्हें बिना बताए यहां आया हूं, अगली बार वो दोनों साथ आएंगे. उसने जिस तरह से अपनी बातें कही, मुझे लगा कि ये भोले-भाले लोग, इन्हें थोड़ी सी रोशनी की किरण दिखाई दी, किसी ने इनके पक्ष में बातें की, इससे ये उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगे. उसकी बातचीत के बाद मैंने तय किया कि मुझे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सर्वमान्य नेता अली शाह ग़िलानी से भी मिलना चाहिए. ग़िलानी साहब से पिछली बार जब मैं और मेरे दोनों पत्रकार साथी मिलने गए थे, तो पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया था. जिस सूत्र ने मुझे पिछली बार गिलानी साहब से मिलने की सलाह दी थी, जिसके जवाब में गिलानी साहब ने फिर हमें होटल में फोन किया था, मैंने उन्हीं से गुज़ारिश की कि क्या किया जा सकता है? उसने मुझे कहा कि आप गिलानी साहब के यहां पहुंचिए, देखिए कोशिश करते हैं. संयोग से हम गिलानी साहब के यहां गए, वहां हमें अंदर जाने दिया गया. ये हमारी आधिकारिक मुलाक़ात थी. मैं गिलानी साहब के पास गया. उन्होंने शायद 15 या 20 मिनट का समय दिया था. पर जब हमारी बातचीत शुरू हुई, तो बातचीत डेढ़ घंटे में तब्दील हो गई. जब डेढ़ घंटा बीता, तब गिलानी साहब ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा. गिलानी साहब इस समय 87 साल के हैं, उम्र के आख़िरी पड़ाव पर हैं और वहां से बैठकर वो जिस तरह से सारी समस्याओं को, कश्मीर को देख रहे हैं, मैंने उसी नज़रिए से उनसे बातचीत की. अचानक मुझे लगा कि ये बातचीत तो गिलानी साहब सबसे करते होंगे और तब मैंने गिलानी साहब से उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं के बारे में बातचीत की, जिसके बारे में आजतक उन्होंने किसी से बात नहीं की. गिलानी साहब की इस बातचीत को हम ***चौथी दुनिया*** के अगले अंक में छापेंगे, जिसमें गिलानी साहब क्या करना चाहते थे, जो वे नहीं कर पाए? गिलानी साहब क्या नहीं करना चाहते थे या गिलानी साहब को किस चीज़ का गम रहा ज़िंदगी में? कौन सी चीज़ उनकी ज़िंदगी से छूट गई, जो अब उनके पास कभी नहीं आ सकती? उन्हें चांद और सुरज की रोशनी से, किस तरह का अहसास होता है? गिलानी साहब अगर श्रीनगर में नहीं होते तो देश के किस हिस्से में रहना पसंद करते या दुनिया के किस हिस्से में रहना पसंद करते? ऐसे सारे सवाल, जो मानवीय सवाल हैं, उन सवालों को मैंने हिम्मत कर के पूछा और गिलानी साहब के चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, वे उस ज़िंदगी से मिली हुई तल्ख़ियों के भाव थे, ज़िंदगी से मिली हुई ख़ुशियों के रंग थे और ज़िंदगी से ना मिल सके लम्हों के अफ़सोसनाक साए थे.

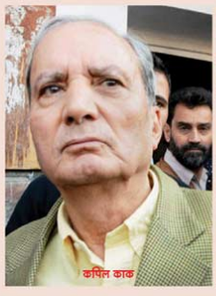

कपिल काक

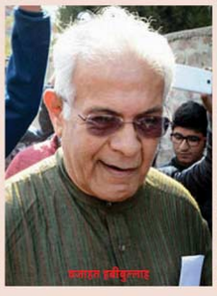

वजाहत हबीबुल्लाह

भारत भूषण

अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां सिरा छोड़ा था, उसी सिरे से इस सरकार को काम शुरू करना चाहिए, तभी कश्मीर का कोई हल निकलेगा, अन्यथा हल निकलना मुश्किल है. शायद उस इंटरव्यू को कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और दिल्ली में होम मिनिस्ट्री ने देखा और तब ये तय हुआ कि यहां से एक अध्ययन दल फ़ौरन कश्मीर भेजा जाए.

कश्मीर जो 1947 में था

गिलानी साहब के यहां से जब लगभग डेढ़ घंटे के बाद मैं निकला, तो मुझे लगा कि मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ ने कल और गिलानी साहब ने आज यह साफ़ कर दिया कि वह तो कभी पाकिस्तान में मिलने की बात ही नहीं करते. उनका सिर्फ़ ये कहना है कि जो वादे भारत की सरकार ने राजा हरि सिंह से किए थे और जिसके आधार पर उन्होंने जो शर्तें यूनाइटेड नेशंस में दी थी, उन पर अमल हो और वो शर्तें सिर्फ श्रीनगर के लिए नहीं, वो शर्तें पूरे कश्मीर के लिए, जो कश्मीर 1947 में था, यानी पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले तीन हिस्से, बलतिस्तान, गिलगित, मुज़फ्फराबाद और इधर श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू. ये सारा हिस्सा, इसमें वो शर्तें लागू हों. जो वादे पूरे हुए हैं, वो इन सारी चीज़ों में, उनका असर इन तीनों चीज़ों पर पड़े, जिनके लिए वो कहते हैं कि आप अगर पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के कब्ज़े वाले तीनों हिस्सों में वो चीज़ें कैसे लागू होंगी? इसलिए उन दोनों का मानना है कि हम पाकिस्तान का नाम इसलिए लेते हैं कि एक हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है. कश्मीर को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखने के लिए दोनों देशों की सरकारें बात करें और हम कश्मीर के दोनों हिस्सों के कश्मीर के लोग, उनकी बातों को सुनकर ये फ़ैसला करें कि उन्हें आगे क्या करना है.

पर ये बात तो हिंदुस्तान के लोगों को बताई ही नहीं जाती. वहां तो ये कहा जाता है कि कश्मीर में रहने वाला हर आदमी पाकिस्तान का समर्थक है और गिलानी साहब व हुर्रियत के बाक़ी नेता पाकिस्तान की वकालत करते हैं. मीरवाइज़ ने कहा कि यहां लोग जब पाकिस्तान का झंडा निकालते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वे पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं. इसका मतलब है कि वो भारत सरकार को चिढ़ाना चाहते हैं. अब तो उन्होंने पाकिस्तान और चीन दोनों का झंडा निकाल दिया है, तो क्या आप मानते हैं कि हमलोग चीन के साथ जाना चाहते हैं? दरअसल गिलानी साहब इस मसले में बिल्कुल साफ़ हैं. जब ज़िंदगी के चंद साल उनके पास हैं, तो वे चाहते हैं कि इस मसले का सही और कश्मीरियों को किए गए वादे के हिसाब से हल निकले.

गिलानी साहब ने अपनी आत्मकथा और अपने द्वारा लिखी हुई तमाम किताबों की प्रतियां मुझे सौंपी. एक किताब पर उन्होंने अपने दस्तख़त किए और मैं जब वहां से निकला तो गिलानी साहब अपनी आदत के ख़िलाफ़ मुझे बाहर सड़क पर, जहां दूर मेरी गाड़ी खड़ी थी, वहां तक छोड़ने आए. वे जब बाहर सड़क पर निकले तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कभी बाहर टहलने निकलते हैं, उनका कहना था कि हां, कभी-कभी निकलता हूं. थोड़ा सा दो क़दम आगे जाता हूं, तो ये मुझे वापस ले आते हैं और जब मैं कहता हूं कि नहीं दो क़दम और चलूंगा, तो ये मुझे थाने में ले जाते हैं. हम हंसे इसपर. जब गिलानी साहब मेरी कार के पास आए, तो मैंने मज़ाक़ में कहा कि गिलानी साहब, चलिए गाड़ी में बैठिए. हम गाड़ी में भाग चलते हैं. अभी ये लोग पीछा करेंगे. गोलियां ये चलाएंगे नहीं क्योंकि आप यहां बैठे हैं और चारों तरफ शोर हो जाएगा कि हिंदुस्तान का एक पत्रकार गिलानी साहब को लेकर फ़रार होने की कोशिश कर रहा है. गिलानी साहब खुल कर हंसे. मुझे लगा कि 87 साल का एक व्यक्ति इस मज़ाक़ को भी किस तरीक़े से इंज्वॉय कर रहा है, इसका लुत्फ ले रहा है.

मैं दोबारा मीरवाइज़ से क्यों मिला

गिलानी साहब के यहां से निकलते समय भी मेरे दिमाग़ में एक बात चल रही थी कि क्या मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ से एक ऐसी बात नहीं हो सकती, जिससे मैं उनका हर्फ़-दर-हर्फ़ नोट कर लूं. तब मुझे अफसोस हुआ कि कल जब मैं मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ के पास गया तो मैं क्यों काग़ज़ पेन नहीं ले गया. मैंने फिर कोशिश की और सबसे पहले शाम की टिकट कैंसिल कराई. गिलानी साहब के यहां से मैं शायद 4 बजे निकला. वहां से निकलने के बाद मैंने फिर चश्मेशाही की तरफ़ दौड़ लगाई. रास्ते में मैंने अपने सारे संपर्कों से कहा कि सरकार से, ग़ैर सरकार से, साहब से, नौकर से, जिससे भी हो, मुझे किसी तरह से मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ से आधे घंटे मिलने का मौक़ा मिल जाय. मैंने कहा, नहीं मिलेगा, तो मैं वहां इंतज़ार करूंगा सड़क पर, जहां से चश्मेशाही का रास्ता शुरू होता है. मैं उस माहौल को देखना चाह रहा था. रात के अंधेरे में वो इलाक़ा कैसा लगता है, जिसे किताबों में, कहानियों में, पृथ्वी के स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है, वो रात में कैसा लगता है? कर्फ्यू वाली रातों में कैसा लगता है? सर्दी की रातों में कैसा लगता है?

क्या इसे मैं अपना अच्छा भाग्य कहूं या मित्रों की मदद कहूं, मुझे फिर किसी तरह जेल में जाने का मौक़ा मिल गया. मैं काग़ज़ों का एक पुलिंदा लेकर चश्मेशाही वाली सड़क पर चढ़ा. इस बार मेन गेट पर तैनात, जहां बैरियर लगा है, सिपाही ने पूछा, तो मैंने उसे अपने पूर्व सांसद होने का कार्ड दिखाया. उसने फ़ौरन अंदर जाने दिया. जेल के कर्मचारी मुझे मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ के पास ले गए. उन्होंने कहा कि अरे, आप फिर कैसे आए? मैंने कहा, मौलवी साहब, यही तो हमारा हुनर है. मैंने उन्हें मज़ाक़ में बताया कि किस तरह मैंने कैसे-कैसे उन लोगों से अपने पत्रकारीय जीवन में मुलाक़ात की, जिनसे कोई दूसरे कभी मुलाक़ात कर ही नहीं पा रहे थे. उनमें डाकू भी थे, अंडरवर्ल्ड के लोग भी थे, ऐसे राजनेता भी थे, जो कुछ करके छुपे हुए थे. इसमें सुकुर नारायण बखिया और हाजी मस्तान जैसे लोग, माधव सिंह, फूलन देवी जैसे डाकू और वो सारे मुख्यमंत्री, वो सारे मंत्री जिन्होंने कुछ ऐसा किया, जिसको मैंने रिपोर्ट किया और जिससे उनके पद के ऊपर आंच आई. कम-से-कम दो मुख्यमंत्रियों के इस्तीफ़े मेरी रिपोर्ट पर हुए और सात या आठ कैबिनेट मंत्रियों का मुझे याद है, या तो उनके इस्तीफ़े हुए या उनके विभाग बदले गए. मैंने ये मज़ाक़-मज़ाक़ में मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ को जब बताया, तो उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा. मैंने कहा, मीरवाइज़ साहब, इंटरव्यू अगर नहीं देंगे, तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी. मैं यहां अख़बार के लिए आया हूं. मैं उसमें आपकी कही हुई बात छापना चाहता हूं. मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ ने कहा, हमने तय किया है कि मैं, गिलानी साहब और यासीन मलिक साहब, हम तीनों आपस में मशविरा करके ही कोई बात कहेंगे. मैंने कहा, वही कीजिए. मैं आपसे बयान देने की बात नहीं कर रहा हूं. मैं आपसे स्थिति का आकलन करने की बात कह रहा हूं, जिसकी वजह से ये 106 दिनों का कर्फ्यू लगा है. लड़के जेल में हैं, लोग मारे गए हैं, पैलेट गन से लोगों की आंखें गई हैं. सरकार बंद है, डल झील सूनी है, सड़कों पर टैक्सियां नहीं चल रही हैं, विद्यार्थियों के इम्तिहान नहीं हो रहे हैं, जो घायल हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है. कश्मीर के इस बंद की वजह से उन लोगों की मौत इस खाते में नहीं लिखी जा रही है, जिन्हें डाइलिसिस कराना था, लेकिन जिनकी डाइलिसिस नहीं हुई और उनकी जानें चली गईं. मैं इसमें उन्हें नहीं जोड़ रहा हूं, जिनको कैंसर था, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल आना पड़ता है, वे नहीं आ पाए, इसलिए उनकी मौत हो गई. तब मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ ने मुझसे बात करनी शुरू की. मैंने उस बात की एक-एक चीज़ को जल्दी-जल्दी काग़ज़ पर नोट किया. नोट करने के बाद मैंने मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ से कहा कि मैंने जो नोट किया है और जो मेरी याद्दाश्त में रहेगा, उसे लेकर मैं स्टोरी करूंगा. अगर कहीं कौमा-फुलस्टॉप इधर-उधर हो जाय, तो कृप्या मुझे क्षमा कीजिएगा. मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ अपनी सौम्यता की हंसी हंसे. मैं वहां से निकलकर बाहर आया. ग़नी से मैंने कहा, मुझे आज फिर श्रीनगर घूमना है. ग़नी लड़का है, ड्राइवर है, टैक्सी चलाता है. मैंने फिर उसके साथ बैठकर डल झील का चक्कर लगाया. सुनसान, बियाबान. शहर में घूमा. वो दिन शुक्रवार था. मैं आपको बताता हूं कि पिछले दिनों कुछ गलियों में दुकानें खुली हुई थीं, लेकिन उस शुक्रवार को उन गलियों की दुकानें भी बंद थीं. हुर्रियत ने कहा था कि शुक्रवार को तो कुछ भी खुला नहीं होना चाहिए. चाय का एक कप अगर कहीं उस दिन मिल जाता, तो शायद लाख रुपए का एक कप होता. नहीं मिला कहीं. खाने के लिए लोग तरस जाते हैं, क्योंकि सारी दुकानें बंद, दवाइयों की दुकानें बंद, सबकुछ बंद.

मीरवाइज़ का इंटरव्यू और यशवंत सिन्हा का कश्मीर दौरा

रात में मैंने मीरवाइज़ के दिए हुए इंटरव्यू के प्वाइंट्स बनाए. अपने दिमाग़ में जितना याद था, वो सब मैंने लिखा और प्रश्न-उत्तर की शक्ल में एक तिहाई काम मैंने पूरा कर लिया. अगले दिन सुबह में पहले हवाई जहाज़ से, जो सुबह सात बजे वहां से दिल्ली के लिए उड़ता है, मैं उससे दिल्ली आ गया. रास्ते भर मैं सोचता रहा कि काश, कश्मीर का ये दर्द दिल्ली को समझ में आ जाए. दिल्ली पहुंचते ही मैंने ईटीवी को बताया कि मैं कश्मीर होकर आया हूं, मैंने मीरवाइज़ का इंटरव्यू छापा है. वो शाम को मेरे पास आए, तब तक अख़बार छप कर आ चुका था. उन्होंने अख़बार के पन्नों की तस्वीरें ली और टीवी पर दिखाया. उन्होंने मुझसे बातचीत की और उसे टीवी पर दिखाया. कश्मीर न्यूज़, जो शाम सात से आठ बजे तक आती है, फिर उसमें विस्तार से दिखाया. नतीजे के तौर पर पूरे कश्मीर को ये पता चल गया कि मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ का इंटरव्यू हुआ है और मीरवाइज़ इस इंटरव्यू में, ये-ये-ये कह रहे हैं. उस इंटरव्यू में मीरवाइज़ मौलाना उमर फ़ारूक़ ने यह कहा, जो मैंने टीवी पर बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां सिरा छोड़ा था, उसी सिरे से इस सरकार को काम शुरू करना चाहिए, तभी कश्मीर का कोई हल निकलेगा, अन्यथा हल निकलना मुश्किल है. शायद उस इंटरव्यू को कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और दिल्ली में होम मिनिस्ट्री ने देखा और तब ये तय हुआ कि यहां से एक अध्ययन दल फौरन कश्मीर भेजा जाए.

भूतपूर्व विदेश मंत्री और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में वजाहत हबीबुल्लाह, पत्रकार भारत भूषण, पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक और सुशोभा बार्वे कश्मीर गए. ये लोग सोमवार (23 अक्टूबर) की सुबह श्रीनगर के लिए चल दिए. वहां जाकर उन्होंने गिलानी साहब, मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ और प्रोफेसर बट से मुलाक़ात की. यासीन मलिक ने उनसे मिलने से मना कर दिया. ये लोग सिविल सोसायटी के लोगों से भी मिले. ये लोग वकीलों से मिले. वहां के व्यापारियों के कुछ ग्रुप से मिले, लेकिन इनलोगों ने कहा कि वे यहां सरकार से बात कर के नहीं आए हैं. उनका कोई सरकारी एजेंडा नहीं है. अच्छा होता, अगर ये इस बात को खोल देते कि हां, हम सरकार से बातचीत करेंगे. इसमें बुरा क्या है? सरकार को चाहिए कि वो बातचीत के रास्ते खोले. एक रास्ता इसमें ये भी है, लेकिन इन्होंने बार-बार ये स्टैंड लिया कि सरकार ने हमें नहीं कहा है. सवाल ये है कि अगर आपको सरकार ने नहीं जाने के लिए कहा है, तो पूरी सरकार आपके लिए सुविधाएं कैसे पैदा कर रही है और ***चौथी दुनिया*** को दिए हुए इंटरव्यू में मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ ने ये कहा कि जब तक राजनीतिक लोग नहीं छोड़े जाएंगे, राजनीतिक गतिविधियां नहीं होंगी. ये उनकी मांग थी. शायद उसकी वजह से सरकार ने मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़ को इतवार की रात जेल से निकाल कर उनके घर में भेज दिया. पर ये संयोग था कि पहले जेल में बंद होने की वजह से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से इनमें से कोई नेता नहीं मिला था. इस बार जेल से बाहर होने की वजह से अपने घर पहुंचने पर मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक़, यशवंत सिन्हा के नेतृत्व वाले दल से मिले. गिलानी साहब भी इनसे मिले. उन्होंने अपनी-अपनी बातें इनके सामने रखीं.

प्रधानमंत्री को तत्काल श्रीनगर जाना चाहिए क्योंकि समस्या का हल सिर्फ़ उनके पास है

कश्मीर एक दर्द के धुंध के बीच घिरा हुआ इलाक़ा है. 60 लाख लोग यहां हैं. सरकार कोई भी फ़ैसला करे तो ये मान कर करे कि वो 60 लाख लोगों को या तो अपने पक्ष में करना चाहती है या 60 लाख लोगों को अपने विरोध में करना चाहती है. कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां बंद हैं. कोई विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं जा सकता है. मंत्री अपने दफ्तरों में आराम से नहीं जा सकते हैं. सारी राजनीतिक गतिविधियां बंद हैं. हालत ये है कि जब श्रीनगर में एक सर्वदलीय मीटिंग हुई, तब हुर्रियत ने कह दिया कि आप चुप बैठिए, जब आप लोग सरकारों में थे, तब आपने क्या किया. उसके बाद किसी राजनीतिक नेता का वहां पता नहीं है. कश्मीर के लोग हमारे अपने लोग हैं. हम लाओस, चीन, सूडान, यमन की चिंता करते हैं, अपने लोगों की भी चिंता कर लें. मैं इस स्थिति के आकलन को इस निवेदन के साथ स्वीकार करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपके हाथ में चाबी है, आप कृप्या कर श्रीनगर जाएं. दो दिन वहां बैठें और वहीं फ़ैसला लें कि कश्मीर के लिए क्या करना है. आपने एक दिवाली श्रीनगर में मनाई थी. उससे ज्यादा ज़रूरी, इस दिवाली पर या इसके कुछ दिन बाद कश्मीर के लोगों को दिवाली का तोहफ़ा देना आपका फर्ज़ बनता है. ■

editor@chauthiduniya.com

एक्सक्लूसिव इंटरव्यू

हम 1947 के जम्मू-कश्मीर की बात कर रहे हैं गिलानी

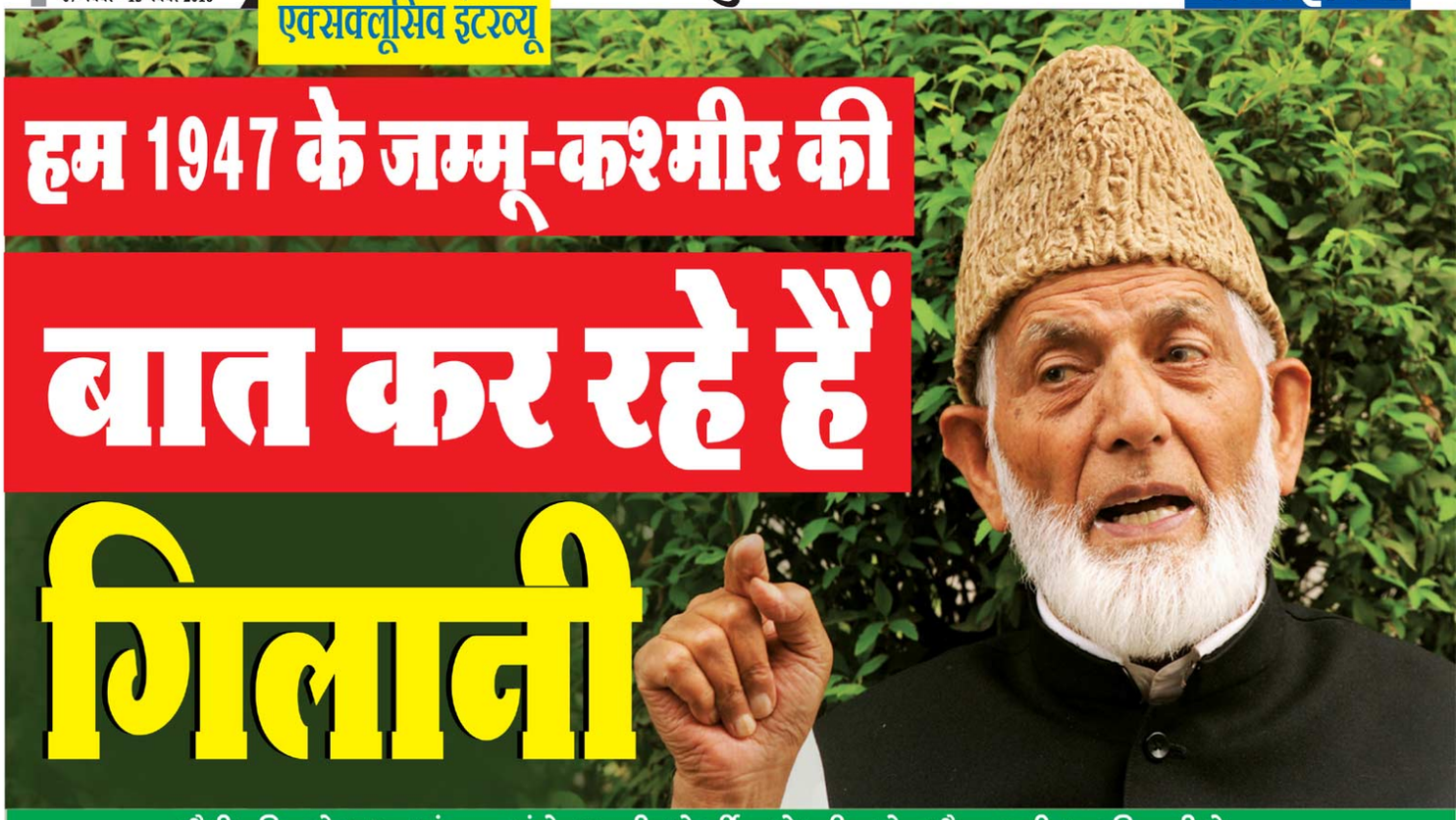

चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने हुर्रियत के वरिष्ठ नेता सैयद अली शाह गिलानी से कश्मीर मसले से लेकर उनकी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में विस्तृत बातचीत की.

सवाल – जैसे ही यहां से जम्मू की तरफ बढ़ते हैं या हवाई जहाज़ उड़ता है, फिर समझ लीजिए कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है. तो अभी हम लोग बात कर रहे थे. आप ने यहां हर बात साफ़-साफ कही है. अभी आप ही बता रहे थे. पर सवालों के ऊपर अगर आप एक बार इजाज़त दें, तो एक बार बातचीत करें, प्लेबेसाइट, पाकिस्तान, फ़ौज वगैरह पर.

जवाब – कश्मीर का मसला 1947 से चल रहा है. 1947 से लेकर आज तक यहां लोगों ने बेशुमार क़ुर्बानियां दी हैं, हिन्दुस्तान के फ़ौजी क़ब्ज़े के ख़िलाफ़. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो छुपी हुई है, जो प्रेस में नहीं आई है, जो किताबों में नहीं लिखी गई है, जो मुलाक़ातों के वक्त कही नहीं गई हैं. कोई ऐसी बात नहीं है. आप जो चाहते हैं, जो नए सिरे से दफ्तर को खोला जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है...

सवाल – इन चीज़ों के बारे में नहीं जैसे मिसाल के तौर पर....

जवाब – हिंदुस्तान ताक़त के नशे में मस्त है. जिस तरह कोई हाथी होता है न, हाथी को जब शराब पिलाई जाती है, तो वह मस्त हो जाता है. हिंदुस्तान ताक़त के नशे में मस्त है. वो रियलिटीज़ को तस्लीम नहीं करता है. वो अपने किए हुए वादों को अमलाने में, उसे पूरा करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता. 2010 में चिदम्बरम ने ऐलानन कहा कि कश्मीर प्रॉब्लम इज ब्रोकन प्रॉमिसेज़ (कश्मीर समस्या वादों का टूटना है). इससे बढ़कर और क्या हक़ीक़त हो सकती है कि उस वक्त के वज़ीर-ए-दाख़ला (गृहमंत्री) ने ऐलानन कहा कि कश्मीर का मसला जो है, वह यह है कि हमने उनके साथ वादे किए थे, वो वादे हमने पूरे नहीं किए हैं. यही है मसला. हिंदुस्तान ने वादे किए हैं. हिंदुस्तान की जो फ़ौज यहां आई है. आंजहानी (स्वर्गीय) पंडित नेहरू ने यहां लाल चौक में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मौजूदगी में कहा कि हम फ़ौज वापस बुलाएंगे और आपको अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का मौक़ा फ़राहम करेंगे. लेकिन ये क़ज़िया (झगड़ा) हमारे उनके दरम्यान रह गया. उनका क्लेम यह था कि कश्मीर हमारा है और इसमें जो आए हैं कबायली वगैरह उनको यहां से निकाला जाए और हमें कश्मीर क़ब्ज़ा ताय्युन किया जाए. जब वहां उनका क्लेम तस्लीम नहीं किया गया, पाकिस्तान ने भी अपना स्टैंड बताया फिर अक़वाम मुत्तहेदा (संयुक्त राष्ट्रसंघ) ने फैसला किया कि जम्मू और कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जम्मू और कश्मीर के लोगों को सेल्फ-डिटरमिनेशन (आत्मनिर्णय) का हक मिलना चाहिए, ताकि वे अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकें कि वे भारत के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ. ये क़रारदादें हैं, उनपर हिंदुस्तान ने दस्तख़त किए हैं, तस्लीम किया है इन क़रारदादों को. पाकिस्तान ने भी दस्तख़त किए हैं और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में ये क़रारदादें मौजूद हैं. अमेरिका ने भी और अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में जितने भी मुमालिक हैं, जितने भी सिक्युरिटी काउंसिल में मेम्बर हैं, सब इस पर गवाह हैं. अब जम्मू और कश्मीर के लोग यही कहते हैं कि भई, आपने दस्तख़त किए हैं, इन क़रारदादों पर, उनको अमलाने में आपको क्या उज्र होना चाहिए. मैंने बार-बार ये कहा है, अपनी तक़रीरों में भी, किताबों में भी मैंने लिखा है कि भाई रेफरेंडम के नतीजे में अगर लोग फ़ैसला करेंगे कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तो हमें कोई उज्र नहीं होगा, हम तस्लीम करेंगे. हमें किसी भी मुल्क के साथ कोई एख्तालाफ़ नहीं है, कोई ज़िद नहीं है, कोई अदावत नहीं है. हिंदुस्तान में जो एक अरब इक्कीस करोड़ लोग बसते हैं, वे हमारे इंसानी निस्बत से हमारे रिश्ते में हैं, भाई हैं. वहां के जो बीस करोड़ मुसलमान हैं, उनके साथ दो रिश्ते हैं. एक इंसानी रिश्ता है, एक दीनी रिश्ता है, मज़हब का रिश्ता है. तो हम इनलोगों के साथ अदावत कैसे रखें, दुश्मनी कैसे रखें? लेकिन हिंदुस्तान जो ज़ुल्म यहां कर रहा है, उस ज़ुल्म की मिसाल इस ख़ित्ते में नहीं मिलेगी. आप ख़ुद देख रहे हैं. तो हम हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान का जो क़ब्ज़ा है, हम उसके ख़िलाफ़ जिद-ओ-जोहद कर रहे हैं और निहत्थे हाल में कर रहे हैं. हमारे पास कोई बंदूक़ नहीं है, हमारे पास कोई पैलेट गन नहीं है, हमारे पास कोई गनर नहीं है. हां, जब हमारे जवानों को आगे बढ़ने से पुलिस रोकती है, फ़ौज रोकती है, बीएसएफ रोकती है, सीआरपीएफ रोकती है, तो वो अपनी-अपनी दिफ़ा के लिए पत्थर उठाते हैं. इसके बग़ैर उनके पास कुछ भी नहीं. लेकिन पत्थर के मुक़ाबले में गोलियां चलती हैं, पैलेट गन चलते हैं, टीयर गैस शेलिंग होती है, लाठीचार्ज होता है, जब्र होता है. लोगों का ख़ून बहाया जा रहा है, लोगों की बिनाई (दृष्टि) ख़त्म की जा रही है. अभी कल ही एक वो कश्मीर में ईशा बेटी की तस्वीर आई थी. उसके साथ उसकी मां थी और बाप भी बाएं तरफ़ था, दिन था. वो बेटी कह रही थी, मुझे बताओ, ये दिन है या रात, 14 साल की बेटी. अब ऐसा ज़ुल्म, छोटे जवानों को उनकी बिनाई छीनना, पैलेट गन का इस्तेमाल करना, कहां का इंसाफ़ है? क्या हिंदुस्तान के जो गुरु गुजरे हैं, कृष्णजी गुजरे हैं, दूसरे बहुत से महात्मा लोग गुज़रे हैं, क्या उन्होंने यही तालीम दी है हिंदुस्तान के लोगों को कि वो आम लोगों पर ज़ुल्म करें, जिनके पास कोई हथियार नहीं, जिनके पास कोई फ़ौज नहीं है, जिनके पास कोई पुलिस नहीं है, जिनके बारे में अदालत भी कोई काम इंसाफ फ़राहम नहीं करती है? मैं 2010 से हाउस अरेस्ट हूं. अदालत में भी गए, अदालत भी कोई फ़ैसला नहीं करती, कोई इंसाफ़ नहीं देती, कोई तहरीर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है. कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई इसको इस केस में हमने बंद रखा है. क्या वजह है? इसी तरह दूसरे लोग भी हैं. अब जो हज़ारों की तादाद में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों की तादाद में और फिर उनको जम्मू ले जाया जा रहा है. किसलिए जम्मू ले जाया जा रहा है? वहां जेलों की जो इंतेज़ामिया है, वो कॉम्युनल है, वो उनको वहां इज़ाएं (चोट) पहुंचाएंगे और फिर जो वहां क्रिमिनल केसेज़ में लोग, जो वहां जेल में हैं, वो भी उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, वो भी उनको सताते हैं, वो भी उनको तंग करते हैं. दो साल पहले एक शख्स को वहां क़त्ल किया गया, जब रजनी सहगल वहां सुपरिंटेंडेंट थीं, कोट बलवाल में, उसको वहां शहीद किया गया. तो इसीलिए उनको जम्मू भेजा जा रहा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि भई किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उसको अपने नज़दीकी किसी जेल में रखना, ताकि उसके रिश्तेदार जो हैं, वो उनके साथ मुलाक़ात कर सकें, उनको सहूलियत हो. लेकिन उसका भी कोई ख्याल नहीं किया जाता. अब ऐसे हालात में आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं.

सवाल– नहीं, मैं माफी के साथ बस यह जानना चाह रहा हूं कि जो कन्फ्यूज़न है वहां कि जब आप कश्मीर कहते हैं, तो वहां ये माना जाता है कि इसका मतलब ये है कि यहां की जो लीडरशिप है, ख़ासकर आप, इसको पाकिस्तान में मिलाने की बिसात बिछाते हैं. तो उसमें अभी यहां पता चला कि इसमें आप ये नहीं कहते हैं. आप ये कहते हैं कि कश्मीर का मतलब, जो 1947 में कश्मीर था, 47 में जो था, सारा हिस्सा, आप वो कहते हैं. तो सर ये वहां नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसमें आपका नज़रिया क्या है?

जवाब– हमारा नज़रिया ये है कि जम्मू-कश्मीर जो 1947 में था. आंजहानी (स्वर्गीय) हरि सिंह के दौरे इक्तेदार में जो था, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, जिसमें गिलगित भी शामिल है, जिसमें बलतिस्तान भी शामिल है, जिसमें जम्मू भी शामिल है, लद्दाख भी शामिल है, कारगिल भी शामिल है, सारा जो जुग़राफ़िया उस वक्त जम्मू-कश्मीर का था, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं. हम सिर्फ कश्मीर वैली के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हमें जम्मू के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है. मैंने आपसे कहा कि मज़हब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर, पेशे की बुनियाद पर, वतन की बुनियाद पर हम किसी भी इंसान के साथ तअस्सुब (भेद-भाव) नहीं रखते, कोई ज़िद नहीं रखते. हमें ये फ़रमाया गया है अल्लाह की तरफ से, जिसपर हम ईमान रखते हैं. जिसका तर्जुमा है – ऐ मेरे बंदों, मैंने तुमको पैदा किया है, लेकिन तुममें जो ये ज़ातें और क़बीलें हैं, ये ज़िद के लिए नहीं या किसी इख्तेलाफ़ के लिए नहीं हैं. तुम सारे एक ही मां बाप के बेटे और बेटियां हो. इस लिहाज़ से तुम्हें एक-दूसरे के साथ इंसानी रिश्ता है, ये हमको बताया गया है. हमको ये भी बताया गया है कि एक इंसान का क़त्ल करना, जो

निहत्था हो, सारी इंसानियत के क़त्ल के बराबर है और एक इंसान को जान का तहफ्फ़ुज़ देना, सारी इंसानियत को तहफ्फ़ुज़ देने के बराबर है. हम उसी पर अमल करने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब मैंने आपसे कहा कि सारा, आज़ाद कश्मीर का भी उसमें आएगा, **जब रेफरेंडम होगा, गिलगित भी आएगा, बलतिस्तान भी आएगा, जम्मू भी आएगा, लद्दाख भी आएगा. अगर इसमें हिंदुस्तान के साथ ही रहने का फ़ैसला हो जाए, हमको कोई उज़ूर नहीं है, हम रह सकते हैं.**

सवाल– लेकिन, इस प्रस्ताव, इस प्रपोज़ल के ऊपर पाकिस्तान की तरफ़ से तो आज तक कोई पॉज़ीटिव सिग्नल नहीं आया कि वह अपने यहां भी इस रिफरेंडम को सपोर्ट करेगा.

जवाब– नहीं, आपको मालूम नहीं है. देखिए, मैं आपको यक़ीन दिलाता हूं. मेरे सामने मुशर्रफ ने ऐलान किया कि जब हिंदुस्तान मानेगा, हम यहां रेफरेंडम करेंगे, हम आज़ाद कश्मीर से अपनी फ़ौज हटाएंगे. ऐलान किया है उन्होंने और उनके दस्तूर (संविधान) में भी लिखा हुआ है कि हम आज़ाद कश्मीर से फ़ौज हटाएंगे और जो वहां के लोगों का फ़ैसला होगा, वो हमें क़बूल होगा. ये कन्फ्यूजन जो है, ये इसलिए पैदा किया जाता है कि हिंदुस्तान को जम्मू-कश्मीर का

(शेष पृष्ठ 5 पर)

हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के साथ चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय

पृष्ठ 4 का शेष

मसला हल करने की नीयत नहीं है, इसीलिए वहां का मीडिया जो है, सब झूठ बोल रहा है, जम्मू-कश्मीर के बारे में. इतना झूठ बोल रहा है जितना हिमालया का कद हो. तो ऐसे हालात में वहां कन्फ्यूज़न ना पैदा हो जाए और क्या हो जाए?

सवाल- ये जो श्रीनगर में पिछले सौ दिनों से हो रहा है, एक कमाल की चीज़ देखने को मिली कि आपलोग एक कैलेंडर जारी करते हैं और पब्लिक उसके ऊपर हंड्रेड पर्सेंट उसका अमल करती है. जबकि पब्लिक के पास, आपने बिल्कुल सही कहा कि ना उनके पास पुलिस है, ना कहीं दंगा करते हैं, ना हुल्लड़ करते हैं लेकिन लोग उस कैलेंडर को बिल्कुल फॉलो करते हैं. ये कैसे हुआ सर? ये मतलब हिस्ट्री का एक नायाब दौर है.

जवाब- देखिए, मैं 29 नवंबर को पूरे 87 साल का हो जाऊंगा. अब मैं 88 में दाख़िल हो जाऊंगा. मेरी सारी ज़िंदगी में जो हमने लोगों के साथ काम किया है. पहले मैं 12 साल टीचर था. फिर 1962 में मुझे पहली बार गिरफ्तार किया गया. श्रीनगर जेल में ले जाया गया. तो जब से लेकर आज तक मैं पॉलीटिक्स में हूं. मैं असेंबली में भी 15 साल रहा हूं. वहां भी लोगों ने मेरी बात सुनी है, और मंगतराम शर्मा कह रहे हैं कि जब तक गिलानी ज़िंदा है, तब तक कश्मीर भी ज़िंदा रहेगा. मसला-ए-कश्मीर के बारे में मैंने अपनी सारी उम्र जो है, मुअक़िफ़ रखी है और लोगों को मालूम है कि ये शख्स है जो काज़ के लिए मुख्लिस है, इसकी कोई ज़ाती (व्यक्तिगत) गर्ज़ नहीं है. इसलिए हम जो बात कहते हैं और हम जो कैलेंडर देते हैं, ये हमारी कोई ज़ाती ख्वाहिश नहीं है, ये जो हमारी अपनी ख्वाहिश और लोगों के जो जज्बात हैं, उनको पेशेनज़र रखकर, हम कहते हैं उनको कि भारत का जो जबरी क़ब्ज़ा है उसके खिलाफ़, हम ये जो जिद-ओ-जोहद कर रहे हैं, उस जिद-ओ-जोहद का साथ देना है. उससे पीछे नहीं हटना चाहिए. इसलिए लोग, लोगों का भी ये जज्बा है. आप देख रहे हैं बुरहान शहीद हुआ, अल्लाह ताला उनकी मगफेरत करे. वह पहला शहीद नहीं था. 600 मज़ार यहां शोहदा के आबाद हो चुके हैं, 600 मज़ार और जम्मू से लेकर कश्मीर तक, 1947 से लेकर आज तक 6 लाख जानों की कुर्बानियां दी जा चुकी हैं, हिंदुस्तान के जबरी क़ब्ज़े के ख़िलाफ़, 6 लाख. वो ये है कि जम्मू में पांच लाख मुसलमानों को बेरहमी के साथ क़त्ल किया गया, अक्टूबर-नवंबर 1947 में. वहां पटियाला फ़ौज थी, हरि सिंह की फ़ौज थी, भारत की फ़ौज थी और कम्युनल एलिमेंट्स थे, जो हमेशा मुसलमानों के दुश्मन रहे. दुश्मन का ख़ून उनको बहुत प्यारा लगता है, मुसलमानों का ख़ून. तो 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया और गुज़िश्ता 25 सालों में यहां एक लाख लोगों को शहीद किया गया है. तो इस तरह कुल मिलाकर 6 लाख जानें हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, हिंदुस्तान के जबरी क़ब्ज़े के ख़िलाफ़. 10 हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गुज़िश्ता अरसे में. लेकिन पता नहीं है कि वो कहां हैं? कोई 7600 क़ब्रें हैं, जिनके बारे में मालूम ही नहीं है कि इनमें कौन दफ़नाए गए हैं और 6000 से ज्यादा हमारी माएं-बहनें और बेटियां हैं, जिनकी इज्जतें लूटी गईं. तो इतनी कुर्बानियां दी हैं इस क़ौम ने. मैं पूरे यक़ीन के साथ कहूंगा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, जो हिंदुस्तान के लोगों ने जद-ओ-जोहद की है, उसमें इतनी कुर्बानियां नहीं दी जा सकीं. एक जलियांवाला बाग़ का वो मैसेकर (नरसंहार) हुआ है, यहां हज़ारों की तादाद में मैसेकर हुए हैं, हज़ारों की तादाद में. लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान अपनी ज़िद से, हठधर्मी से पीछे नहीं हट रहा. ये नशा-ए-कुव्वत है. इक़बाल मरहूम ने, शायद इक़बाल को आप पढ़ते होंगे, कुछ शेर भी याद होंगे उनके. उन्होंने कहा है,

असकंदर-ओ-चंगेज़ के हाथों से जहां में
सौ बार हुई हज़रते इंसान की क़बा चाक!
तारीख़-ए-उमम का ये पयाम-ए-अदली है,
साहिब-ए-नज़रां नशा-ए-कूव्वत है ख़तरनाक.

दानीशमंद लोग जो हैं, उनसे कहा जा रहा है कि नशा-ए-कूव्वत जो है, वह बड़ा ख़तरनाक है. यही नशा-ए-कूव्वत सवार हो गया है भारत की हुकूमत पर भी और भारत के सियासतकारों पर भी. हम सारे, एक-सवा अरब लोग जो हैं, सबके बारे में हम नहीं कहते हैं कि सब एकसां (एक जैसे) हैं. बहुत लोग समझते भी होंगे. बहुत लोगों को हमारे साथ हमदर्दी भी होगी. बहुत लोग जो हम पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनका असर भी रखते होंगे, उनपर अफ़सोस भी करते होंगे. लेकिन एक मोफ़क्कीर (दार्शनिक) ने कहा है कि इंसानी समाज में जो बिगाड़ पैदा हो जाता है, वह बुरे लोगों के हाथों से ही नहीं होता है, वह उन लोगों से भी होता है, जो ख़ामोश रहते हैं. जो लोग ख़ामोश रहते हैं, ज़ुल्म देखकर, उन्हीं की वजह से यह बिगाड़ पैदा हो जाता है. अगर वो ज़ुबान खोलते और बुरे हाथों को पकड़ कर उनको बुराई से बाज़ रखते, तो बिगाड़ पैदा नहीं होता, लेकिन वे ख़ामोश रहते हैं. यही हाल हिंदुस्तान का है. हिंदुस्तान में इंसानियत का जज्बा रखने वाले करोड़ों की तादाद में हैं लोग, हम उससे इंकार नहीं करते, लेकिन ज़ुबान नहीं खोलते, ज़ुल्म के ख़िलाफ़. अल्लाह जो है उसपर, अगर आपको यक़ीन है तो एक अल्लाह है, सारी कायनात का मालिक है, उसको सबसे ज्यादा ज़ुल्म से नफ़रत है. ज़ुल्म नहीं किया जाना चाहिए. लेकिन इंसान ज़ुल्म करता है. भारत को जम्मू-कश्मीर में इंसानों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है. उन्हें यहां की ज़मीन चाहिए. हालांकि भारत के पास काफी ज़मीन है. कितना बड़ा मुल्क है. जम्मू-कश्मीर जो है, सारा जम्मू-कश्मीर, वो यूपी के एक ज़िले के बराबर है, उससे ज्यादा नहीं है. यूपी में, जो आबादी है, यूपी जो बहुत बड़ा सूबा है, उसमें जितनी ज़मीन है, एक ज़िले में जितनी ज़मीन होगी या आबादी होगी, उससे ज्यादा यहां नहीं है. लेकिन भारत को चस्का है, चस्का है ज़मीन का. आज आप देखेंगे कि यहां की जो ज़मीनें हैं, सबसे ज्यादा फ़ौज के क़ब्जे में हैं. एक ज़मीन का लालच, दूसरा जो यहां हुस्न है इस ख़ित्ते का, उसकी भी चाशनी है उसे. यहां के जंगलात हैं, जंगलात को साफ़ कर रहे हैं. उनके जितने भी कैंपस हैं, जंगलात के क़रीब-क़रीब, वहां उन्होंने, वो चराई की मशीनें रखी हैं और वहां के मुकामी (स्थानीय) लोगों से दरख्त कटवाते हैं. और फिर अपने कैंपों में उनकी चराई करते हैं, फिर फर्नीचर बनवाते हैं और फिर घरों को भेजते हैं. एक मिसाल मैं आपको दूंगा. अगर आप ख़ुद भी जाएंगे, देख सकते हैं. सोपियां में 5200 कनाल, फॉरेस्ट लैंड आर्मी ने अपने क़ब्ज़े में ले लिया है, कंटोनमेंट बनाने के लिए और जंगलात के जो माहिर लोग हैं, उनका कहना है कि यहां 3 लाख से 4 लाख तक दरख्त कटे हैं. जंगलों का सफाया हो रहा है, बाहरी के हाथों. यहां जो आबीवसाइल हैं, यहां आबीवसाइल पर हाइड्रो पावर्स जो बनते हैं, सारे भारत के क़ब्ज़े में हैं. हमारी ज़मीन, हमारा पानी और उनको पावर सप्लाई करने के जो होते हैं, हम सर्दियों के मौसम में ख़ासतौर पर परेशान रहते हैं, बिजली के लिए, लेकिन हिंदुस्तान उनको दे रहा है और दिल्ली में उनको फ़रोख्त

किया जा रहा है पावर को, हरियाणा में, राजस्थान में भी और यहां के लोग जो हैं, वे परेशान रहते हैं. इसी तरह पानी पर उनका क़ब्ज़ा है, ज़मीन पर उनका क़ब्ज़ा है और यहां जो-जो यहां बाक़ी चीज़ें हैं, ज़राए हैं, उनपर भी वो क़ब्ज़ा किए हुए हैं. मैं आपको ये बात भी बताऊंगा, आप यक़ीन करें, भारत के यहां से जितनी भी दवाएं आती हैं, ख़ासतौर जो कश्मीर के लिए बनाई जाती हैं, जम्मू के साथ दूसरा सलूक किया जा रहा है. कश्मीर के साथ और जम्मू के मुसलमानों के साथ उन दवाओं में भी मिलावट की जाती है. मैं दिल्ली में होता हूं सर्दियों में, वहां की दवा का एक

> **“अफ़सोस यही है कि हम ग़ुलाम हैं. इस पर बहुत अफ़सोस है. इक़बाल फ़रमाते हैं, मौत है एक सख्ततर जिसका ग़ुलामी है नाम / मकर-वो-फ़न ख्वाजगि का काश समझता ग़ुलाम. ऐ कि ग़ुलामी से है रूह मुज्महिल / सीना-ए-बेसोज़ में ढूंढ़ ख़ुदी का मुक़ाम. मैं आपको बताऊंगा कि हमारी मिसाल मोर के साथ मिलती है. मोर जब नशे में आता है, जब जोश में आता है, तो वो नाचता है और फिर उसे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं बहुत ख़ूबसूरत हूं, लेकिन जब अपनी टांगों पर नज़र पड़ती है, तो वो शर्मा जाता है, वही हाल हमारा है.”**

असर है और यहां जब हम दवा ले लेते हैं, उसका दूसरा असर है. अभी कल ही मैंने सुना, बाग़ जो हैं, उनमें जो दवाइयां छिड़की जाती हैं, उन दवाइयों में भी मिलावट की जाती है, ताकि यहां के बाग़ जो हैं, बर्बाद हो जाएं. कितना सुनेंगे आप कि कितने मसाएब हम पर डाले जा रहे हैं, कितना ज़ुल्म हम पर ढाया जा रहा है. ग़ुलामी का नतीजा है कि हम ग़ुलाम हैं, हम अंडर-सप्रेशन हैं और उन लोगों के हाथों में हैं, जिन्हें इंसानियत का कोई एहसास नहीं है. अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया. वो समझते थे, इंसानियत के साथ उनको मोहब्बत थी, उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम उनको छोड़ देंगे, क्या फ़र्क़ पड़ेगा? लेकिन हिंदुस्तान ऐसा नहीं है. हिंदुस्तान की हुकूमतें, चाहे कांग्रेस हो या पीडीपी या चाहे बीजेपी हो, आरएसएस हो, सबका एक मक़सद है कि कश्मीर को हिन्दू राष्ट्र बनाया जाए. ये उनकी पॉलिसी है. वो यहां मुसलमानों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करते. पार्लियामेंट में एक ख़ातून हैं, पार्लियामेंट मेम्बर हैं, उन्होंने एक जलसे में कहा है, देखो रामज़ादे बनो, हरामज़ादे मत बनो. रामज़ादे मतलब राम की नस्ल के और हरामज़ादे उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा.

सवाल-वो मंत्री हैं सरकार में.

जवाब - हां मंत्री हैं.

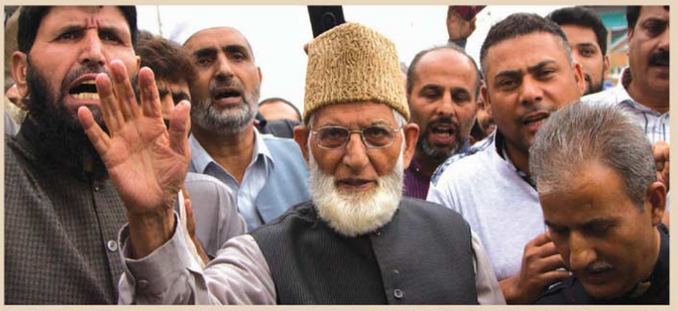

सवाल -आप ने 87 से जम्मू-कश्मीर को देखा, शुरू के दस साल मान लें बचपन में निकल गए, फिर तो आप सारा देख ही रहे हैं. तो आपने शेख़ साहब से लेकर महबूबा मुफ्ती तक जो सियासी लीडर्स हैं, सबको देखा है यहां पे. चूंकि आपसे सीनियर तो कोई है ही नहीं यहां पे, तो इनमें आपको किसी में इंसानियत, बेहतरी, कश्मीर के प्रति मोहब्बत नज़र आई, जितने लीडर्स हुए या नहीं नज़र आई?

जवाब -हमारी ग़ुलामी का जो आग़ाज़ हुआ है, वो 1938 में हुआ है. 13 जुलाई 1931 में हरि सिंह के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट हुआ और उसमें 22 मुसलमान शहीद किए गए. उन 22 मुसलमानों की शहादत के बाद, उस वक्त जो लीडर थे, उनमें शेख़ अब्दुल्ला भी थे, उसमें मौलवी युसूफ़ साहब भी थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस. उन्होंने ये अहद किया कि ये 22 जो शहीद हुए हैं, इनका जो मिशन है डोगरा राज से आज़ादी हासिल करना, उस मिशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे. ठीक है बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मगर शेख़ अब्दुल्ला ने 1938 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुक़ाबले में दूसरी पार्टी बनाई नेशनल कॉन्फ्रेंस. नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसी वक्त से, जबसे वो वजूद में आ गई, रिश्ता बना इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और शेख़ अब्दुल्ला के दोस्ताना तालुक़ात आंजहानी नेहरू जी के साथ मुस्तहक़म हो गए. उसके बाद से उनका नेशनल कांग्रेस के साथ ही रिश्ता रहा और जब हिंदुस्तान तक़सीम हुआ, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान की तक़सीम दो क़ौमी नज़रिए की बुनियाद पर हुई है. भले आज कोई माने या न माने, लेकिन दो क़ौमी नज़रिए की बुनियाद पर हुई. जहां हिन्दू अक्सरियत है, वह भारत बनेगा, जहां मुस्लिम अक्सरियत है पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा. 25 जुलाई 1947 को, अगस्त में ऐलान हुआ आज़ादी का, लेकिन उसे पहले 25 जुलाई को जो वहां लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो अंग्रेज़ों की तरफ से गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 25 जुलाई को ऐलान किया कि जो पौने छह सौ के क़रीब रजवाड़े थे, स्टेट्स थे, जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थे, उनसे कहा गया कि तुम्हें इख्तियार है, चाहे हिन्द का हिस्सा बनो, चाहे पाकिस्तान का हिस्सा बनो, चाहे इंडिपेंडेंट रहो, लेकिन तुम्हें तीन चीज़ों का ख्याल रखना होगा. ये किसने कहा लार्ड माउंटबेटन ने. गाइडलाइन्स दीं 25 जुलाई 1947 को. गाइडलाइन्स की बातें उन्होंने कहीं, फ़ैसला करने से पहले तुमको ये देखना होगा कि तुम्हारी सरहदें किस मुल्क़ के साथ मिलती हैं. दूसरी बात ये देखनी है कि तुम्हारे जो लोग हैं, उनमें किनकी अक्सरियत है, मुसलमानों की अक्सरियत है या हिन्दुओं की. तीसरा प्वाइंट ये था कि तुम्हारे जो लोग हैं, उनका मज़हबी और दीनी और तहज़ीबी रिश्ता किन लोगों के साथ है. ये तीन बातें थीं. अब जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर की साढ़े सात सौ मील सरहदें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं. समझे आप? 1947 में जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 85 फीसदी थी और मज़हबी और दीनी रिश्ता जो है, वो सिर्फ़ उसी हिस्से के साथ था जो पाकिस्तान बना. हमारे यहां उस वक्त यहां हरि सिंह के दौर में मुसलमानों के लिए तालीम बहुत कम थी. तालीम के बारे में उनको आगे बढ़ने में उनको मवाक़े नसीब नहीं थे. अक्सर लोग अमृतसर या लाहौर जाते थे पढ़ने के लिए. मैं ख़ुद गया हूं लाहौर. चार साल मैं लाहौर में रहा. ये रिश्ता था, उस रिश्ते के साथ जो पाकिस्तान बना. अब इन तीन बुनियादों की रू (लिहाज़) से आप ख़ुद फ़ैसला करिए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलने वाला था या हिंदुस्तान के साथ? ये तो पाकिस्तान का नेचुरल पार्ट था, लेकिन शेख़ अब्दुल्ला ने चूंकि उनका आंजहानी नेहरू के साथ रिश्ता था, दोस्ती थी, तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान बड़ा मुल्क है और यहां हमें बड़ा ताआऊन नसीब होगा. पाकिस्तान ग़रीब मुल्क है, अभी-अभी नया-नया बना है, तो वो क्या देंगे हमें. तो एक माद्दापरस्ती उस पर सवार हो गई और उसने हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाने का मोआहेदा किया. आंजहानी हरि सिंह ने, जो फ़र्ज़ी दस्तावेज़ इल्हाक़ का कहा जा रहा है, उसकी उसने ताईद की और फ़ौज भेजने की जब आंजहानी हरि सिंह ने फ़ौज के लिए हिंदुस्तान से मदद मांगी तो उस वक्त शेख़ अब्दुल्ला दिल्ली ही में थे. उसने हौसला दिया है नेहरू को, पटेल को और आंजहानी गांधी को कि तुम मेरे मश्वरे पर वहां फ़ौज भेज दो. गोया शेख़ अब्दुल्ला हमारी ग़ुलामी का सबब बना है. फिर आप ये भी याद रखिए कि जब उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार हो जाने के बाद 11 साल के बाद उनको रिहा किया गया. उस जल्से में मैं ख़ुद भी शरीक था, ग्यारह साल के बाद रिहा होने के बाद उन्होंने जल्सा किया मुज़ाहिद मंजिल में और उसके बाद उनको रियासतबदर किया गया (यहां नहीं रहने दिया गया दिल्ली में रहे वो). दिल्ली में रह कर 1971 में मैं उनसे ख़ुद मिला हूं. उन्होंने हज़रत बल में एक तक़रीर में कहा था कि लोग मुझे गलतकार कह सकते हैं, ग़लतियां हुई हैं मुझसे, लेकिन ग़द्दार नहीं कहेंगे, मैंने ग़द्दारी नहीं की. मैंने उनको याद दिलाया अप्रैल 1971 में दिल्ली में कि आपने जो ये कहा है कि लोग मुझे ग़लतकार कहेंगे, लेकिन ग़द्दार नहीं, ये आपका इशारा ग़लतकारी का किस तरफ है? ऐनक लगाई थी उन्होंने, ऐनक उठाई और कहा यही कि हमने लोगों के साथ इल्हाक़ किया, जिन पर हमने ऐतमाद किया, वो ऐतमाद के लायक़ नहीं थे. ये मैंने किताब में भी लिखा है और उसके बाद वो 22 साल तक रायशुमारी, रायशुमारी करते रहे, 22 साल तक. 22 साल के बाद उन्होंने आंजहानी इंदिरा गांधी के साथ इक़रार किया और कहा कि हमें इल्हाक़ के साथ कोई इख्तेलाफ़ नहीं है. हमें कुछ मुराआत (छूट) वग़ैरह दिए जाएं, लेकिन वो भी उनको कुछ नहीं मिला. इसके बाद वो सात साल तक ज़िन्दा रहे और ये उनकी ग़द्दारी थी क़ौम के साथ. तारीख़ में जो हक़ीक़तपसन्द ममालिक होंगे, वो उनको जम्मू-कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा ग़द्दार क़रार देंगे. उन्होंने लोगों के साथ धोखा किया. हालांकि, वे कुरान पढ़ते थे, लेकिन लोगों के साथ उन्होंने खुला धोखा किया. उसके बाद जितने भी, आप कहते हैं कि कितने लीडरों को देखा, कितने हुक्मरानों को देखा, सारे हुक्मरान यहां इक्तेदारपरस्त निकले और किसी को भी क़ौम के जज्बात के साथ दिलचस्पी थी और न क़ौमी मफ़ाद के साथ कोई दिलचस्पी रही. सिर्फ़ अपने इक्तेदार को, कुर्सियों की वो हिफ़ाज़त करते रहे.

सवाल-पब्लिक क्यों चुनती है ऐसे लोगों को?

गिलानी - आमलोग जो होते हैं, ख़ाम होते हैं. आमलोग सारे बाशउर नहीं होते, वो ख़ाम होते हैं. ख़ासतौर पर जहां तालीम ज्यादा न हो, ख़ासतौर पर जहां शउर न हो, जहां लोगों में देखने की सकत न हो कि सही क्या है, ग़लत क्या है? होता है हर क़ौम में.

सवाल- आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कौन से काम किए, जिसका आपको गर्व कि मैंने ये किया, और कौन से वो काम किए जिसका आपको अफ़सोस हो कि मैंने ये क्यों किया?

गिलानी- सुकून की बात यही है कि हमने कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की. हमने जो भी बात कही है, सच्ची बात कही है. मैंने शेख़ अब्दुल्ला को, जब 1975 के बाद वो एसेम्बली में आए, तो मैं भी उस वक्त मौजूद था एसेम्बली में, 15 साल रहा मैं एसेम्बली में, मैंने उनकी मौजूदगी में कहा कि जम्मू-कश्मीर में, हिन्दुस्तान में, पाकिस्तान में, जो फ़साद है, जो ख़ून बह रहा है, उसकी सारी ज़िम्मेदारी शेख़ अब्दुल्ला की है. ये जो बातें मैंने की हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सुकून की बात है. मैंने जब भी बात कही है, सही बात की है. मैंने हक़ बात की है और मैंने कभी दिल से हिंदुस्तान के ज़बरी क़ब्ज़े को क़बूल नहीं किया है और न ही उसको लेजिटिमेसी अता करता हूं, किसी भी हैसियत से.

सवाल- वैसे किन कामों का अफ़सोस है?

गिलानी- अफ़सोस यही है कि हम ग़ुलाम हैं. इस पर बहुत अफ़सोस है. इक़बाल फ़रमाते हैं, *मौत है एक सख्ततर जिसका ग़ुलामी है नाम / मकर-वो-फ़न ख्वाजगि का काश समझता ग़ुलाम. ऐ के ग़ुलामी से है रूह मुज्महिल / सीना-ए-बेसोज़ में ढूंढ़ ख़ुदी का मुक़ाम.* मैं आपको बताऊंगा कि हमारी मिसाल मोर के साथ मिलती है. मोर जब नशे में आता है, जब जोश में आता है, तो वो नाचता है और फिर उसे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं बहुत ख़ूबसूरत हूं, लेकिन जब अपनी टांगों पर नज़र पड़ती है, तो वो शर्मा जाता है, वही हाल हमारा है. हम जब अपने गिर्द हुस्न देखते हैं, डल देखते हैं, फिर जंगलात वग़ैरह तो हमें ख़ुशी होती है कि अल्लाह ताआला ने कितना हुस्न दिया है हमारे इस सूबे को. लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम ग़ुलाम हैं, तो बस मोर की तरह हमारी गर्दन गिर जाती है. ग़ुलामी बहुत बड़ा अज़ाब है, बहुत बड़ा अज़ाब.■

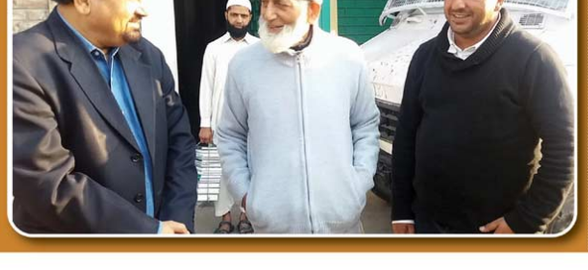

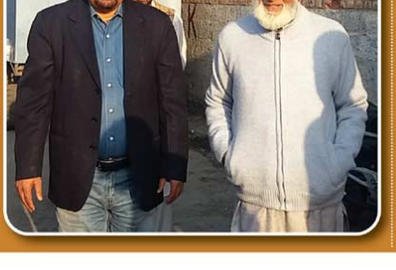

जंग से मसाइल पैदा होते हैं हल नहीं

प्रोफेसर अब्दुल ग़नी बट

चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने हुर्रियत के वरिष्ठ नेता प्रो. अब्दुल ग़नी बट से कश्मीर मसले पर विस्तृत बातचीत की.

सवाल- प्रोफेसर साहब, कश्मीर जहां आज खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि दो दीवारें खड़ी हैं, जिनमें कोई सुराख़ नज़र नहीं आ रहा है. इनमें सुराख़ करने का क्या तरीक़ा है और आज के हालात से निकलने का क्या रास्ता है?

पहली बात तो ये है कि कश्मीर को जुनूबी एशियाई ख़ित्ते से अलहदा ना समझा जाए. इसको जुनूबी एशियाई ख़ित्ते का एक हिस्सा तस्लीम किया जाए और जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जौहरी हथियार बनाने में कामयाब हो गए हैं, जब से ये जौहरी ममालिकतें बन कर के उभरी हैं, जब से कश्मीर का मसला जैसे जुनूबी एशियाई ख़ित्ते के मुस्तक़बिल के साथ जुड़ा दिखाई देने लगा है, जुड़ा हुआ है. इसलिए जब आप कश्मीर की बात करेंगे तो दरहक़ीक़त आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, बल्कि पूरे जुनूबी एशियाई ख़ित्ते की बात करते हैं. इसलिए हमें दिन को दिन कहना पड़ेगा और रात को रात. हम एक ऐसे मरहले पर पहुंचे हैं, जहां हमें दानिशमंदी के साथ भी, दूरंदेशी के साथ भी, और सबसे बड़ी बात ये है कि हक़ीक़तपसंदी के साथ भी आगे बढ़ने का फ़ैसला करना पड़ेगा. इसलिए कश्मीर में जो आप देख रहे हैं, शोरिश (हंगामा) है. इस शोरिश को भी समझना पड़ेगा. इसमें जो अनासिर हैं, उनको भी देखना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ने के लिए दिल को बड़ा भी करना पड़ेगा. सबका भला चाहना होगा. भला आपका भी हो, मेरा भी हो, सबका हो. भला हिंदुस्तान का भी हो, पाकिस्तान का भी हो, कश्मीरियों का हो और कश्मीर में जितने भी ख़ित्ते हैं, उन सबका भला हो. अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ा जाए. मुझे अपना वजूद आप में दिखाई दे और आपको अपना वजूद मुझमें दिखाई दे, तो फिर ये मसले बिल्कुल आराम के साथ हल हो सकते हैं. इनका हल निकाला जा सकता है. हल कैसे निकाला जाए? हल के लिए देखें, पहली बात तो पहले की जाए. जंग से मसाइल पैदा होते हैं और जन्म लेते हैं, हल नहीं होते हैं. इसलिए जंग को आप छोड़ दें. जंग नहीं करेंगे. हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले जंग नहीं करेंगे. कश्मीर वाले बिल्कुल ही जंग नहीं करेंगे. वो जंग कर ही नहीं सकते. कश्मीर के रगो-पै में जंग है ही नहीं, कश्मीर की सोच में जंग नहीं है, अमल में जंग नहीं है. कश्मीरियों पर जब कोई नारवा, कोई ग़ैर-हक़ीक़ी सूरत-ए-हाल ठूंसी जाती है, तो वे उसका मुक़ाबला करने के लिए मैदान में आते हैं ज़रूर, ये बात है, लेकिन वो जंग के इरादे से नहीं आते हैं. वो इस इरादे से, इस अज्म से आते हैं कि हम इन मसाइल का हल निकालें. कैसे निकालें, जंग से नहीं, हठधर्मी से नहीं, बल्कि बातचीत के माहौल में ख़ुशअसलूबी के साथ, दानिशमंदी के साथ, दूरंदेशी के साथ और हक़ीक़तपसंदी के साथ आगे बढ़ा जाए. मुझे इस सिलसिले में कोई ग़लतफ़हमी नहीं है कि कश्मीर में आप जहां भी जाएंगे, जिन लोगों से भी बात करेंगे, वो आपसे ये बात ज़रूर करेंगे कि कुछ ना कुछ तो करिए, या कुछ ना कुछ तो जो है, ये कुछ ना कुछ तो करिए, इसके मायने ये हुए कि रास्ता ढूंढिए और जो भी रास्ता आप मशावरत के साथ एक दूसरे से मिल बैठ के ढूंढ निकालते हैं, उस पे हम सब चलेंगे, तो इसलिए मैं ये समझता हूं, जंग नहीं, बल्कि बातचीत होनी चाहिए. बातचीत कहां हो? मेरा ये ख्याल है कि हम जिस मोड़ पर हैं, तारीख़ के जिस मोड़ पर हैं, उस मोड़ पर आकर के मैं ये समझता हूं कि तर्जीही बुनियादों पर इन्हें प्रिफरेंसेज जो हैं, उनको देखना पड़ेगा. वो प्रिफरेंसेज तर्जीहात क्या हैं? तर्जीहात ये हैं कि पहले मरहले पे बातचीत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ शुरू हो. उसका इंपैक्ट जो है, उसका असर जो है, वह पूरी रियासत की सोच पर पड़ता है. उसका असर पूरी रियासत के अमल पर पड़ता है. उसका असर पूरी रियासत के लोगों की हिकमत-ए-अमली यानी स्ट्रैटेजी पर पड़ता है. इसलिए अगर बातचीत वहां हो जाती है, तो यहां आपको अमन लौटते दिखाई देगा. यहां आपको सलामती के माहौल में घूमने-फिरने का शौक़ उभरता दिखाई देगा. यहां आपको मिल-बैठ के सोचने का मौका मयस्सर होता दिखाई देगा. सब चीज़ें होंगी, तो मेरी राय में पहले मरहले पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू हो. दूसरे मरहले पर निकलना है अगर, तो दूसरे मरहले पर जब ये बातचीत शुरू होगी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो आई ट्रस्ट, द आइस मस्ट ब्रेक. ये जो यख (बर्फ़) है, जमा हुआ ये जो बर्फ़ है, पिघलना शुरू हो जाएगा.

सवाल- तो बातचीत का कोर सबजेक्ट, पूरा कश्मीर होगा या केवल श्रीनगर होगा?

जब मैं कश्मीर की बात करता हूं, मैं पूरे कश्मीर की बात करता हूं. श्रीनगर तो एक शहर है कश्मीर का. कश्मीर के मायने, मैंने पहले कहा कि पूरा जुनूबी एशियाई ख़ित्ता है. ये जब जुनूबी एशियाई ख़ित्ता हो तो पूरा कश्मीर है और जब हिंदुस्तान भी हो, पाकिस्तान भी हो, पूरा ख़ित्ता है. और जब हम हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, दोनों का भला चाहते हैं, पूरे ख़ित्ते का भला चाहते हैं, तो उसमें पूरा कश्मीर आ जाता है. तो दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, वो ये है.

जब मैं कश्मीर की बात करता हूं, मैं पूरे कश्मीर की बात करता हूं. श्रीनगर तो एक शहर है कश्मीर का. कश्मीर के मायने, मैंने पहले कहा कि पूरा जुनूबी एशियाई ख़ित्ता है. ये जब जुनूबी एशियाई ख़ित्ता हो तो पूरा कश्मीर है और जब हिंदुस्तान भी हो, पाकिस्तान भी हो, पूरा ख़ित्ता है. और जब हम हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का, दोनों का भला चाहते हैं, पूरे ख़ित्ते का भला चाहते हैं, तो उसमें पूरा कश्मीर आ जाता है. तो दूसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं, वो ये है.

सवाल- पर इसका माहौल कैसे बनेगा?

हां, यही तो मैं कह रहा हूं. अब बातचीत की बात पर पूरा हिंदुस्तान-पाकिस्तान उसके बाद कश्मीरियों के हर ख़ित्ते के लोगों को इसमें शामिल किया जाए. कैसे शामिल किया जाए? मैं हवा में किले बनाने का क़ायल नहीं हूं. एक तिकोनी तर्ज़ का निज़ाम पैदा किया जाए. ट्राइंग्यूलर, इसके मायने ये कि हिंदुस्तान के साथ कश्मीर वाला बात करेगा. पाकिस्तान के साथ भी बात करेगा. वो प्रो-फ्रीडम लोग हों, या प्रो-इंडिया हों या प्रो-पाकिस्तान हों, जो भी हों, लेकिन एक ट्राइंग्यूलर फ्रेमवर्क में इनको बातचीत के लिए तैयार किया जाए. ये हो सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है. इन कश्मीरियों को बातचीत में शामिल करने के लिए लाज़िम है, देखें कि यहां जो रास्ते हैं, उस कश्मीर के, इस कश्मीर के, ये खुल जाएं. यहां जो तिजारत हो, वह फले-फूले और दोनों के दरमियान शुरू हो. हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए भी रास्ते खोले जाएं और बंदिशें तोड़ी जाएं और फिर माहौल को पैदा करने के लिए जब हम एक-दूसरे से मिलेंगे, पंजाबी, पंजाबी से मिलता है तो वो पंजाबी हो जाता है, ना हिंदुस्तानी रहता है, ना पाकिस्तानी रहता है. सिंधी गुजराती या सिंधी राजस्थानी मिलें, तो वो अपनी उसी बोली के हो जाते हैं और उस गोली से डरते हैं, जिस गोली का शिकार हम आजकल हो रहे हैं और बंटवारे के नतीजे में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि एक तारीख़ी चीज़ है, हो चुकी है, बल्कि एक तारीख़ी अल्मिए के तौर पर, जिसे आप सबकॉन्टिनेंटल आयरेनी कहते हैं. उसके नतीजे में हम एक-दूसरे से बिछड़ गए हैं-दूर हो गए हैं. इसको इससे निजात पाना है. इससे निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि रास्तों को खोला जाय और रास्तों को खोलने के साथ-साथ बुद्धि के दरीचों को खोला जाय, यानी आपकी जो अक्ल है, उसकी खिड़कियों को खोलना पड़ेगा. हवाओं को आने दीजिए, तब्दीली के हवाओं को अपने दिमाग़ में समोने के लिए आप कोशिश करें. तो ये दूसरी बात हुई. एक माहौल पैदा हो जाएगा. तीसरी बात, जो है वह मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगेन. अब आप देख लीजिए, आपका ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, आपने देखा है, तेवर भी आपने देखे होंगे, तेवर भी आपने परखे होंगे. नई सफबंदियां शुरू हो रही है दुनिया में. अब ये युनिपोलर वाली बात नहीं है कि आप अमेरिका के हो जाएं, मैं अमेरिका का हो जाऊं तो बस अमेरिका महाराजा है. अमेरिका महाराज नहीं है, अमेरिका आप जैसा है, मुझ जैसा है. लाइक इंडिया, लाइक पाकिस्तान, लाइक रशिया, लाइक चाइना यानी जैसे चीन है, जैसे रूस है, जैसे हिंदुस्तान है, जैसे पाकिस्तान है, वैसे अमेरिका भी एक है. वो युनिपोलर वाली बात, वो एक आंख वाली बात ख़त्म. आपने डॉलर देखा होगा. डॉलर पर जो निशानी है न, वो एक आंख की निशानी है, आपने देखा है, वो एक आंख वाली बात ख़त्म है. अब दो आंख की, आपको दोनों आंखों को मिलाकर देखना होगा. आपको ये हक़ीक़त तस्लीम करना पड़ेगा, वो ये है. रशिया इज ग्रोइंग लाइक चाइना. अब चीन तो पहले ही ग्रो हो चुका है. अब रशिया भी ग्रो हो गया है. रूस ने आंखों में आंखें डाल कर अमेरिका से कहा, ईरान के मसले को आप एक आंख से न देखें. हमारी भी आंखें हैं, आपने देखा होगा. जब न्यूक्लियाई तनाज़ा खड़ा हो गया था उसमें. जी, एक आंख से नहीं, तो फिर पांच जमा हो गए, पांच मुल्क जमा हो गए, हल निकल आया. दोनों के मोफ़ाद में हल निकल आया. फिर आप चलेंगे कहीं और. झगड़े जो हैं, हमारी इस दुनिया में हैं. उसमें रूस जो है, वह चीन की पॉलिसी पर चल रहा है. रूस और चीन के तेवर एक जैसे हैं. रूस और चीन के निशाने एक जैसे हैं. रूस और चीन के इरादे एक जैसे हैं और वो समझते हैं आप, वो इरादे क्या हैं. अब उन चीज़ों को देख कर के मुझे यूं दिखाई देता है कि हमारा जो आने वाला कल है, वो इस हक़ीक़त से जुड़ चुका है कि दिन को दिन कहा जाए और रात को रात कहा जाए. हिंदुस्तान और पाकिस्तान लड़ाई नहीं लड़ सकते. उस लड़ाई में उनका ख़ात्मा होगा. नहीं, फिर क्या करना है? उनको भाइयों की तरह रहने का सलीक़ा सीखना पड़ेगा. एक-दूसरे का मददगार, मोआविन बनना पड़ेगा. सपोर्ट. इंडिया शुड बी सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड पाकिस्तान शुड बी सपोर्टिंग इंडिया. और ये कैसे होगा? ये तो तभी होगा, जब हमारे दरमियान झगड़े ख़त्म हों. इन झगड़ों को ख़त्म कैसे किया जाए. उन झगड़ों में झगड़ों की मां जो है, वह कश्मीर है. अब इसको आप क्यों नहीं मानते? ये आज का झगड़ा नहीं है. आप तो तीन-चार जंगें लड़ चुके हैं. और पिछले कई सालों से, 26-27 सालों से जंग ही जंग है. भले ही फौजें ना लड़ रही हों, बाज़ाब्ता तौर पर एलान के बाद जंग ना लड़ रहे हों, लेकिन जंग हो रही है. सरहदों पर जंग चल रही है, कश्मीर की गलियों-कूचों में जंग हो रही है. सोच में जंग है, इरादों में जंग है, उठने-बैठने में जंग है, तिजारत में जंग है, रास्तों पर जंग है. तो इस जंग का ख़ात्मा करने के लिए हम मिल बैठेंगे. आप भी, मैं भी, वो बड़े लोग भी. तो देखेंगे आप और मैं, हम अपनी तरफ़ से कोई चीज़ पेश करेंगे. जरा इसको देखें, ये आपके लिए ठीक है. नुस्ख़ा पेश होगा. आप करेंगे. आप अख़बार में हैं. आप घूमते हैं, आप फिरते हैं, तो आप मेरे से बात करते हैं, मैं आपको एक ख़ाका देता हूं. ख़ाका ये है जी, संतोष भाई ख़ाका ये है, इस ख़ाके पर चलिए और देखिए कि अमन लौटता है कि नहीं, लौटता है और देखिए ख़ुशहाली आती है कि नहीं आती है और देखिए कि इस ख़ित्ते के सब लोग सुकून के साथ और ख़ुशहाली के साथ आगे बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं. अब मैंने कहा था आपसे कि 'पीस ऐट हार्ट एंड पीस ऐट होम.' ये एक बहुत बड़ा मकाम है, जिसको पाना होगा. बहुत बड़ी मंज़िल है, जहां तक जाना होगा और आप जब जाएंगे, वहां तो उधर जाकर आपको यह दिखाई देगा कि ये पाकिस्तान वाला मेरा भाई है. वो पाकिस्तान वाले को दिखाई देगा कि ये मेरा भाई है. कश्मीर वाला ये आवाज़ दे कि दोनों मेरे भाई हैं. हिंदुस्तान वाला मेरा भाई है, पाकिस्तान वाला मेरा भाई है. इस माहौल को... मेरा ख्याल है कि कई लोग ये कहेंगे कि आइडियलिज्म है. लेकिन इस आइडियलिज्म को रियलिज्म में बदलने के लिए आपको ये बातें भी सुननी होंगी और ये ताने भी सहने होंगे. आगे बढ़ना है तो फिर ये ताने सुनने होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

सरयू राय रघुवर से ख़फ़ा

मंत्रियों से मतभेद सरकार पर संकट

भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय इन दिनों अपने ही मुखिया से खासे नाराज चल रहे हैं. इसके कारण भी हैं, मुख्यमंत्री ने विभा की समीक्षा के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यकलापों की जमकर आलोचना कर दी. मुख्यमंत्री ने यहां तक कह डाला था कि इस विभाग में भ्रष्टाचार जमकर व्याप्त है. इस पर काबू पाने के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है. मुख्यमंत्री की इन आलोचनाओं से विभागीय मंत्री काफी तिलमिला गए.

प्रशान्त शरण

झारखंड में मुख्यमंत्री रघुवर दास और कुछ मंत्रियों के बीच उत्पन्न खटास अब साफ दिखाई देने लगी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास के तल्ख तेवर, उनके व्यवहार एवं मंत्रियों के कार्यकलापों की सार्वजनिक आलोचना से मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य नाराज हैं. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि रघुवर सरकार पर इसका सीधा असर पड़ सकता है. यों भी रघुवर दास से पार्टी के अधिकतर नेता, मंत्री, विधायक की नाराजगी जगजाहिर है. मुख्यमंत्री द्वारा अपने ही दल के कार्यकर्ताओं को 'चिरकुट नेता' बताये जाने से भी भाजपा में मुख्यमंत्री को लेकर खासी नाराजगी है. पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वे पार्टी के लिए समर्पित हैं और दिन-रात पार्टी के हित में काम करते हैं, पर इस सरकार में उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जाती है. उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है. भाजपा का सहयोगी दल आजसू भी मुख्यमंत्री की कार्यशैली से नाराज चल रहा है. आजसू ने कुछ बातों पर आपत्ति जाहिर करते हुए सरकार से समर्थन वापस लेने तक की धमकी दे डाली थी.

भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय इन दिनों अपने ही मुखिया से खासे नाराज चल रहे हैं. इसके कारण भी हैं, मुख्यमंत्री ने विभा की समीक्षा के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यकलापों की जमकर आलोचना कर दी. मुख्यमंत्री ने यहां तक कह डाला था कि इस विभाग में भ्रष्टाचार जमकर व्याप्त है. इस पर काबू पाने के लिए विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किया जा रहा है. मुख्यमंत्री की इन आलोचनाओं से विभागीय मंत्री काफी तिलमिला गए. सरयू राय ने मंत्री पद संभालते ही विभाग में सुधार के लिए कई योजनाएं लागू की थीं और इसका असर दिखने भी लगा था.

दरअसल दोनों नेताओं के बीच शुरू से ही दूरियों वाला रिश्ता रहा है. श्री राय झारखंड में भाजपा के चाणक्य माने जाते हैं. इनकी संघ परिवार एवं पार्टी के आला नेताओं के बीच अच्छी पकड़ है. यही कारण है कि रघुवर दास के नहीं चाहने के बाद भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह देनी पड़ी, लेकिन विभागों के बंटवारे के समय मुख्यमंत्री ने उनके अनुभवी होने के बाद भी उन्हें अदना सा विभाग थमा दिया. उस दौरान श्री राय ने अपने चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आने दी, पर वे अंदर से आहत थे. उन्हें यह अहसास हो गया कि मुख्यमंत्री उनका कद छोटा करने में लगे हुए हैं. उन्होंने पार्टी के आला नेताओं से अपनी नाराजगी व्यक्त कर उन्हें यह अहसास करा दिया कि वे मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहते हैं, पर आला नेताओं ने पार्टी की साख बचाने के लिए उन्हें मंत्री पद पर बने रहने की सलाह दी. पार्टी के आला नेताओं को यह अहसास था कि अगर श्री राय ने बगावत कर दी तो रघुवर सरकार में संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि भाजपा का एक मजबूत धड़ा रघुवर दास का घोर विरोधी है. माना जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का श्री दास के साथ छत्तीस का रिश्ता है और मुंडा को आधे से अधिक विधायकों का समर्थन हासिल है. ऐसे में अगर श्री राय बगावत पर उतर जाते हैं तो रघुवर सरकार गंभीर संकट में आ सकती है.

वैसे मुख्यमंत्री रघुवर दास इन सभी बातों से इंकार करते हुए कहते हैं कि पार्टी एकजुट है और न कोई नाराज है और न ही किसी मंत्री के साथ मतभेद. सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. श्री राय के संबंध में उन्होंने कहा कि वे एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं. लेकिन श्री राय की नाराजगी साफ दिख रही है, वे स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि किसी की आलोचना से पहले सारी बातों से अवगत हो जाना चाहिए. अगर मुख्यमंत्री को मेरे विभाग से कोई शिकायत थी, तो मुझे बताया जाना चाहिए था, ना कि सार्वजनिक तौर पर बयान देना चाहिए. श्री राय तो मुख्यमंत्री की कार्यशैली से ही नाराज हैं और उनके कार्यों पर सवालिया निशान लगाते हुए कहते हैं कि केवल बोलने और बयान देने से काम नहीं होने वाला है. काम करने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मंत्री और अधिकारियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं है. तल्ख लहजे में आदेश देना ही काफी नहीं होता है, बोली में मधुरता होनी चाहिए.

कुछ अन्य मंत्री भी मुख्यमंत्री रघुवर दास से खासे नाराज हैं. कारण साफ है कि मुख्यमंत्री ने अन्य मंत्रियों पर पकड़ बनाये रखने के लिए उनके विभाग में सख्त माने जाने वाले अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी है, जो मंत्री की एक नहीं चलने देते. कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने इसका रोना भी रोया, पर मुख्यमंत्री पर इसका कोई असर नहीं पड़ा.

मंत्रियों के बीच उत्पन्न नाराजगी ने मुख्यमंत्री रघुवर दास के चेहरे से मुस्कान गायब कर दी है. उन्हें यह अहसास हो गया है कि वे संकटों में घिरते जा रहे हैं, कभी भी मंत्रिमंडल में विद्रोह की आवाज उठ सकती है और सरकार पर संकट उत्पन्न हो सकता है. आलाकमान की शह एवं आला नेताओं के आशीर्वाद से उनकी गद्दी सलामत है, लेकिन कब तक यह बहुत बड़ा सवाल है, जो रघुवर दास को भी सोचने पर मजबूर कर देता है.

अहंकार में जाती रही सरकार

झारखंड में अक्सर ऐसा देखा गया है कि मुख्यमंत्री में अहंकार आते ही, उसकी सरकार किसी न किसी कारणों से चली जाती है. झारखंड गठन के बाद बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने. उनकी गठबंधन की सरकार थी, जिसमें जद यू शामिल थी. जद यू के पांच विधायक बाबूलाल की सरकार में मंत्री थे, पर झारखंड बिजली बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष राजीव रंजन को लेकर मुख्यमंत्री और तत्कालीन ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो में ठन गयी. ऊर्जा मंत्री जो जद यू कोटे से थे, हर हाल में अध्यक्ष को हटाना चाह रहे थे, पर बाबूलाल अपनी जिद पर अड़े रहे. उस समय झारखंड में राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय ने इस नजाकत को समझा और शतरंज पर अपनी बिसात बिछाने लगे. ऐसा माना जाता है कि सरयू राय भी बाबूलाल से नाराज चल रहे थे और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा. ऐसी चर्चा आम थी कि सरयू राय ने उस समय युवा तुर्क माने जाने वाले अर्जुन मुंडा को अपने पक्ष में किया, फिर सरकार गिराने और बनाने की रणनीति तय हुई. जद यू के विधायकों से संपर्क साधकर दोनों नेताओं ने उन लोगों को विश्वास में लिया. जद यू ने सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा की और अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया गया.

मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने निर्दलीय, जद यू और आजसू के समर्थन से सरकार बनाया. कुछ दिनों तक सरकार ठीक-ठाक से चली, पर समर्थन दे रहे मंत्रियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया. इससे मुख्यमंत्री का काम करना मुश्किल हो रहा था. कुछ दिनों बाद अर्जुन मुंडा ने मंत्रियों की बात सुननी बंद कर दी. उन्हें यह अहंकार हो गया कि ये सब मंत्री तो मंत्री पद छोड़ेंगे नहीं. अर्जुन मुंडा इस बात को समझ नहीं पाए और मंत्रियों ने ऐसी चाल चली कि अर्जुन मुंडा की ताज ही छिन गयी. अर्जुन मुंडा की सरकार जाने के बाद कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, जद यू, निर्दलीय सभी एकजुट हुए और भाजपा छोड़कर आए निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया. यह झारखंड की राजनीति में एक इतिहास बन गया कि कोई निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुआ. मधु कोड़ा 14 सितंबर, 2006 से 23 अगस्त, 2008 तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे.

ठीक इसी तरह शिबू सोरेन की सरकार गिराकर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने. इस बार उन्होंने शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का सहारा लिया. झामुमो के सहयोग से सरकार बनी. हेमंत को उपमुख्यमंत्री बनाया गया, पर हेमंत और अर्जुन मुंडा में किसी मुद्दे को लेकर ऐसी ठनी कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ. इसके बाद हेमंत ने अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण मुंडा की सरकार गिर गई. फिर हेमंत सोरेन कांग्रेस की मदद से 13 जुलाई, 2013 को सरकार बनाकर मुख्यमंत्री का ताज पहनने में कामयाब रहे.

वर्तमान राजनीति में भी यही हो रहा है, पार्टी के आला नेताओं खासकर अमित शाह का खुलकर समर्थन दिये जाने से रघुवर दास अति उत्साहित और अहंकार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं. मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनका व्यवहार भी ठीक नहीं है. अधिकारियों को तुम-ताम करने से आइएएस खेमा अंदर ही अंदर नाराज है. मंत्री सरयू राय ने तो मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है, जबकि चार मंत्री मुख्यमंत्री की कार्यशैली से आहत हैं. सीएनटी एवं एसपीटी मुद्दे पर भाजपा के अधिकतर आदिवासी विधायक मुख्यमंत्री से नाराज हैं. राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि मुख्यमंत्री रघुवर दास को उनका ही अहंकार ले डूबेगा.■

शिबू सोरेन की सरकार गिराकर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने. इस बार उन्होंने शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का सहारा लिया. झामुमो के सहयोग से सरकार बनी. हेमंत को उपमुख्यमंत्री बनाया गया, पर हेमंत और अर्जुन मुंडा में किसी मुद्दे को लेकर ऐसी ठनी कि दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ. इसके बाद हेमंत ने अर्जुन मुंडा सरकार से समर्थन वापस ले लिया, जिसके कारण मुंडा की सरकार गिर गई. फिर हेमंत सोरेन कांग्रेस की मदद से 13 जुलाई, 2013 को सरकार बनाकर मुख्यमंत्री का ताज पहनने में कामयाब रहे.

पार्टी और सरकार के भीतर सब ठीक-ठाक : गिलुवा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा का मानना है कि सरकार एवं संगठन में सबकुछ ठीक-ठाक है, कोई मतभेद या मनभेद नहीं है. रघुवर सरकार के कार्यकलापों से यहां की जनता खुश है और राज्य को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. व्यावसायिक घरानों का झुकाव झारखंड की ओर हो रहा है. उन्होंने इस बात से इंकार किया कि कुछ मंत्री रघुवर दास से नाराज चल रहे हैं. कार्यकलापों को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे सरकार से नाराज हैं. खाद्य मंत्री सरयू राय द्वारा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए जाने की बात पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है. वे सरकार एवं संगठन के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. संगठन के कार्यों में वे लगातार सलाह-मशविरा दे रहे हैं. पार्टी कार्यसमिति के विस्तार के संबंध में उन्होंने कहा कि जल्द ही नई कार्यसमिति की घोषणा कर दी जाएगी. सूची को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी के आला नेताओं से विचार-विमर्श किया जा रहा है. मुख्यमंत्री एवं प्रदेश के वरीय नेताओं से भी इस संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया है. सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, ताकि संगठन को मजबूती मिल सके.

सीएनटी एवं एसपीटी एक्ट के संशोधन के बाद पार्टी की छवि खराब होने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह विपक्षियों की चाल है. विपक्षी दल राज्य का विकास नहीं चाहते हैं, वे विकास में बाधक बने हुए हैं. भोली-भाली जनता को बहकाकर वे अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं.■

केवल बोलने से काम नहीं होने वाला: सरयू राय

रघुवर सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय, मुख्यमंत्री रघुवर दास की कार्यशैली एवं व्यवहार से खासे नाराज हैं. वे मुख्यमंत्री की बेरुखी एवं उनके बातचीत की शैली से भी आहत हैं. झारखंड राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले सरयू राय का मानना है कि केवल बोलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता. इसके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का होना जरूरी है. भ्रष्टाचार केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करने से नहीं रुकेगा, बल्कि बड़े अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए. अगर वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या आय से अधिक संपत्ति उनके पास है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. सरयू राय ने कहा कि किसी भी विभाग की आलोचना करने से पहले विभाग में हो रहे कार्यों से भली-भांति अवगत होना चाहिए, न कि समाचार-पत्रों में बयान देकर आलोचना करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री उनके कार्यों से खुश नहीं हैं, तो वे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं. वैसे उनका कहना है कि उन्होंने अपने विभाग में पारदर्शिता लाई और काफी हद तक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाया.

उन्होंने कहा कि मंत्री एवं जन-प्रतिनिधियों को अधिकारियों के साथ शालीनता से पेश आना चाहिए, ना कि तल्ख व्यवहार करना चाहिए. अधिकारियों के साथ डांट-फटकार से कार्यशैली में सुधार नहीं लाया जा सकता है. एक-दूसरे के साथ बेहतर तालमेल एवं व्यवहार से कार्यप्रणाली में सुधार लाकर राज्य का विकास किया जा सकता है.

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

आरएसएस ने कश्मीर समस्या का समाधान नहीं होने दिया

कश्मीर अब भी जल रहा है. दक्षिण कश्मीर से बड़ी तादाद में नौजवान गायब हैं. वे मारे गए हैं या ट्रेनिंग पर गए हैं, ये मालूम नहीं है, लेकिन वे गायब हैं. यह बहुत गंभीर मसला है और जबतक भारत सरकार गिलानी वगैरह से बातचीत करने का मन नहीं बना लेती, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोई समाधान नहीं निकलेगा. दरअसल भारत सरकार के लिए सबसे बेहतर काम यह होगा कि बातचीत के दरवाज़े खोले जाएं और वहां से शुरुआत हो, जहां से मुशर्रफ और वाजपेयी ने छोड़ा था. अगर वो प्रक्रिया बहाल रहती, तो इस समस्या का अब तक समाधान हो गया होता. मनमोहन सिंह ने कोशिश की, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं हो सका.

पिछले हफ्ते-दस दिनों से समाजवादी पार्टी का अंदरूनी घटनाक्रम देश में सियासी बहस का मुद्दा बना हुआ है. ये सब को पता है कि समाजवादी सांगठनिक शक्ति के अधिकतर हिस्से पर शिवपाल यादव का नियंत्रण है. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने के कारण इस गलतफहमी में हैं कि पूरी पार्टी उनके साथ है. उनकी छवि ठीक है, उन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है. अब चुनाव होने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के लिए यह संभव नहीं है कि वो शिवपाल यादव के सहयोग के बिना बेहतर प्रदर्शन कर पाए. जितनी जल्दी वे अपने मतभेद दूर कर लेते हैं, उनके लिए उतना ही बेहतर होगा. बहरहाल, इस सारे ड्रामे का फायदा मायावती को होगा. उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाता असमंजस की स्थिति में हैं कि उन्हें समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहिए या मायावती को क्योंकि वे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे. फ़िलहाल मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को अपना मन बनाने में मदद की है. यदि मुसलमानों ने मायावती का समर्थन कर दिया तो वो बेशक नंबर एक बन जाएंगी और ये भी हो सकता है कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाए. समाजवादी पार्टी जितनी जल्द अंदरूनी कलह से उत्पन्न अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त कर लेती है, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा.

दूसरी बड़ी खबर कॉर्पोरेट दुनिया से है, जहां रतन टाटा ने एक बार फिर टाटा सन्स की कमान अपने हाथ में ले ली है, जहां पहले उन्होंने साइरस मिस्त्री को बहाल किया था. साइरस 48 साल के हैं और रतन टाटा 78 वर्ष के हैं, लेकिन इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी. इंफ़ोसिस में भी पहले ऐसा हो चुका है. नारायण मूर्ति ने कमान दूसरे को सौंप कर ये समझा कि वे रिटायर हो गए, लेकिन उन्हें फिर वापस आना पड़ा. आखिरकार संस्थाएं दशकों और सालों में बनती हैं. ऐसी संस्थाएं नए लोगों द्वारा नहीं चलाई जा सकती हैं, जो उसके मूल्यों, संस्कृति और आचार से वाकिफ नहीं होंगे. मैं व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा को उनके द्वारा किए गए बदलाव के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा. उन पर एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा करने के लिए विशेष कारण नहीं बताया. वे किसी चपरासी या निचले स्तर के कर्मचारी को नहीं बदल रहे थे, जिसके लिए उन्हें चार्जशीट देना पड़े और एक जांच बैठाएं और सवाल-जवाब करें. ये ऐसे बदलाव हैं जो सबसे ऊंचे स्तर पर हुए हैं, जो गोपनीय रखे जाते हैं. उन्होंने बिलकुल सही तरीका अपनाया. अब दिल्लगी की बात यह है कि साइरस एक खुला ख़त लिख रहे हैं, जिसमें वो हर तरह के इलज़ाम लगा रहे हैं. वो कहते हैं कि चेयरमैन के तौर पर उनके पास कोई पावर नहीं था. अगर ऐसा था, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? पद पर बने रहने के लिए उनसे किसने कहा? ये सही नहीं है. हमें इंतज़ार करना होगा कि आगे क्या होता है? इस पद पर अगला व्यक्ति कौन बैठेगा, इसके लिए रतन टाटा को बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति फिर पैदा हो सकती है. उनके लिए यह सही होगा कि वे यह ओहदा किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दें जो टाटा से 30-40 सालों से जुड़ा हो और जो टाटा के एथिक्स को समझता हो. मेरे ख्याल से उन्हें चेयरमैन को अनियंत्रित पावर नहीं देना चाहिए. उन्हें एक कोर समिति बनानी चाहिए, जिसमें उन्हें भी रहना चाहिए. यदि वे कृष्णा कुमार या किसी अन्य सीनियर व्यक्ति को टाटा का चेयरमैन बनाते हैं, तो ये टाटा के लिए बेहतर होगा. 75 साल की आयु सीमा को भी बढ़ाकर 80 साल कर देना चाहिए, क्योंकि आप एकदम से नए व्यक्ति की तलाश नहीं कर सकते.

फ़िलहाल मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुसलमानों को अपना मन बनाने में मदद की है. यदि मुसलमानों ने मायावती का समर्थन कर दिया तो वो बेशक नंबर एक बन जाएंगी और ये भी हो सकता है कि उन्हें पूर्ण बहुमत मिल जाए. समाजवादी पार्टी जितनी जल्द अंदरूनी कलह से उत्पन्न अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त कर लेती है, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा.

कश्मीर अब भी जल रहा है. दक्षिण कश्मीर से बड़ी तादाद में नौजवान गायब हैं. वे मारे गए हैं या ट्रेनिंग पर गए हैं, ये मालूम नहीं है, लेकिन वे गायब हैं. यह बहुत गंभीर मसला है और जबतक भारत सरकार गिलानी वगैरह से बातचीत करने का मन नहीं बना लेती, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कोई समाधान नहीं निकलेगा. दरअसल भारत सरकार के लिए सबसे बेहतर काम यह होगा कि बातचीत के दरवाज़े खोले जाएं और वहां से शुरुआत हो, जहां से मुशर्रफ और वाजपेयी ने छोड़ा था. अगर वो प्रक्रिया बहाल रहती, तो इस समस्या का अब तक समाधान हो गया होता. मनमोहन सिंह ने कोशिश की, लेकिन उस समय भी ऐसा नहीं हो सका.

हमें मालूम है कि पाकिस्तान मुश्किल में है क्योंकि नवाज़ शरीफ के पास सीमित अधिकार हैं, सारे फैसले राहील शरीफ कर रहे हैं. लेकिन यदि हम बातचीत की प्रक्रिया को वहां से शुरू करें, जहां से मुशर्रफ और वाजपेयी ने छोड़ा था, तो इसमें कुछ न कुछ निकल कर आएगा. उस समय मुशर्रफ इस मसले को सुलझाने के हक में थे, लेकिन आडवाणी जी के माध्यम से आरएसएस ने समझौता होने से रोक दिया. जैसा कि अक्सर होता है आरएसएस हमेशा अल्पकालिक फायदे की सोचता है और ये नहीं देखता कि कितना दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाया है. बीजेपी कश्मीर में पावर में है, लेकिन कैसा पावर, ये पावर पुलिस और बंदूक का है. श्रीनगर में ट्रैफिक इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि वहां लड़के सड़कों पर पत्थर रख रहे हैं और दुकानें व पेट्रोल पंप छह बजे के बाद खुलते हैं, जब वे सड़कों से पत्थर हटा देते हैं, तो ऐसे में किसका आदेश चल रहा है, सरकार का तो नहीं चल रहा है. ये लड़के हैं, जिनका आदेश चल रहा है. जितनी जल्दी इस हालत को ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, उतना ही बेहतर होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सबक नहीं सियासत

कवर स्टोरी- उरी आतंकी हमले की सच्चाई (24 अक्टूबर-30 अक्टूबर) में मनीष कुमार ने जिन सैन्य चूकों और सरकारी अनियमितताओं की बात कही है, उनसे प्रथम दृष्टया उरी हमले के कारण स्पष्ट हो जा रहे हैं. श्रेय लेना हमारी राजनीति की परंपरा रही है, लेकिन इसके साथ-साथ सियासी मर्यादा और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाना जरूरी है. सैन्य मामलों में सियासी आरोपों-प्रत्यारोपों को किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता. भले ही सर्जीकल स्ट्राइक की वाहवाही ने उरी हमले के कारणों पर उपज रहे प्रश्नों को परदे के पीछे कर दिया है, लेकिन देशहित और सैन्यहित में इनकी पड़ताल जरूरी है. पेट्रोल-डीजल के ढेर के पास सैनिकों का टेंट लगाना किसी चूक ही नहीं भीतरघात की तरफ भी इशारा कर रहा है. सस्मय सच्चाई सामने आनी ही चाहिए. अब तक राजनीति में ही भाई-भतीजावाद और फेवरेटिज्म की बात सुनी और देखी जाती थी, लेकिन अब सेना में भी इसके संकेत देश की सुरक्षा के साथ-साथ हमारी संप्रभुता के लिए भी चिंताजनक हैं.

– रजत कुमार, *दिल्ली*

समाजवादी सिरफुटौवल

मुलायम थामें कमान इस पर घमासान, (24 अक्टूबर-30 अक्टूबर 2016) शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रभात रंजन दीन ने समाजवादी पार्टी में मचे जिस सियासी घमासान की बात की है, वह यूपी-2017 की राजनीतिक दशा और दिशा को भली भांति स्पष्ट कर रहा है. एक ही पार्टी में अलग-अलग खेमेबंदी सपा के भविष्य के लिए सुखद संकेत नहीं है. सपा पर पहले से ही परिवारवाद का ठप्पा लगा है, अब उस परिवार में प्रभुत्व के लिए संघर्ष, मुलायम सिंह की सियासी विरासत का बंटाधार करने की ओर अग्रसर है. सत्ताधारी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव उसके उस नेता की असल परीक्षा होती है, जो विगत पांच वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में काम किया होता है. पूरी पार्टी भी उसी के काम और नाम के सहारे चुनाव प्रचार में उतरती है. लेकिन यूपी में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पार्टी दफ्तर में बैठना छोड़ दिया है और पार्टी के

वरिष्ठ नेता भी उनसे अलग राह अख्तियार कर रहे हैं, यह मुलायम सिंह के लिए तो चिंता की बात है ही, कार्यकर्ताओं में भी हताशा भरने के लिए काफी है. पार्टी में अगर ऐसे ही सियासी सिरफुटौवल का दौर जारी रहा तो आगामी चुनाव में सपा के अंदर घर फूटे गंवार लूटे वाली कहावत चरितार्थ हो सकती है.

– रोहित पाण्डेय, *देवरिया, उत्तर प्रदेश*

अपना कश्मीर

संतोष भारतीय की संपादकीय जब तोप मुकाबिल हो, प्रधानमंत्री जी, आपको कश्मीरियों से मिलना चाहिए (24 अक्टूबर-30 अक्टूबर 2016) पढ़ा. कश्मीरियों को लेकर भारत के बाकी भागों के लोगों और भारत की सरकार के रवैये को लेकर संपादकीय में जो चिंता जाहिर की गई है, वह बिल्कुल वाजिब है. भारत की सियासत और सत्ता में बैठे लोग, कश्मीर के बारे में जो वाक्य सबसे ज्यादा बोलते हैं, वह है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. लेकिन भावनात्मकता और राष्ट्रवाद की परिधि से बाहर निकलकर देखें तो पता चलेगा कि इस वाक्य की सार्थकता सिर्फ नारों और सियासी फायदों तक ही सिमित है. हम कश्मीर को तो भारत का अभिन्न अंग कहते हैं, लेकिन कश्मीरियों के प्रति हमारे दिल में अभिन्न अंग वाला प्यार नहीं है. अगर होता, तो कश्मीरी इस हाल में जीने को विवश नहीं होते. कौन चाहता है कि वह संगीनों के साए में रहे, हर दिन सुबह आंख खुलते ही बंदूकधारी सैनिकों का सामना करना किसे पसंद हो सकता है. लेकिन कश्मीरी इसी को अपनी नियति मान कर जी रहे हैं. प्रधानमंत्री जी को उस दिशा में कदम बढ़ाना पड़ेगा ताकि कश्मीरी सही अर्थों में यह महसूस कर सकें कि वे भारत का अभिन्न अंग हैं.

– नीतीश कुमार, *दिल्ली*

अपराध की सियासी मान्यता

महागठबंधन की कमजोर कड़ी बने राजबल्लभ, (24 अक्टूबर-30 अक्टूबर 2016) शीर्षक से लिखा लेख पढ़ा. राजबल्लभ होने का मतलब, पढ़कर ही स्पष्ट हो गया कि राजबल्लभ जैसों की सियासी अहमियत कितनी है. लगता है कि राजनीति का अपराधीकरण बीते दिनों की बात हो गई, अब तो राजनेताओं की अपराधी प्रवृत्ति भी सियासी मान्यता की ओर बढ़ रही है. अपराधियों को सियासी शरण देना या नेताओं के अपराध का बचाव करना भारतीय राजनीति की परंपरा रही है, खासकर बिहार में. लेकिन अब वही बचाव, बिहार की सरकार और नेताओं के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है. शहाबुद्दीन मामले में राजद और जदयू नेताओं का आरोप-प्रत्यारोप सबने देखा. उसके बाद राजबल्लभ यादव की जमानत के विरोध में बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना भी गठबंधन सरकार के बड़े दल, राजद को रास नहीं आ रहा. राजद ने भले ही सियासी छीछालेदर से बचने के लिए राजबल्लभ को पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन लालू यादव के घर पर उनसे राजबल्लभ की मुलाकात ने ही बहुत कुछ बता दिया.

– दिव्यप्रकाश, *बेतिया, बिहार*

बेरोजगारों का देश

नौकरियां घट रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है, (24 अक्टूबर-30 अक्टूबर 2016) शीर्षक से लिखा हुआ शफीक आलम का लेख पढ़ा. अच्छे दिनों के सियासी शोर के बीच नौकरियां घटने की खबर चिंतनीय तो है ही, यह उन लाखों लोगों के सपनों का टूटना भी है, जिन्होंने सोचा था कि इस सरकार में उनके अच्छे दिन जरूर आएंगे. हालांकि इस जनतंत्र में जनता के सपनों का टूटना नई बात नहीं है, बात चाहे गरीबी हटाओ के नारे के बस नारों तक सिमट जाने की हो, शाइनिंग इंडिया के शोर की, देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है की, या अच्छे दिनों की, हकीकत यही है कि आम लोगों के अच्छे दिन कभी आए ही नहीं. सियासी वादों की बात बस आंकड़ो तक सिमट कर रह जाती है. जीडीपी की मायाजाल में देश निरंतर विकास के नए मानक गढ़ रहा है, लेकिन इस युवा देश का युवा आज भी बेरोजगारी के दंश से खुद को निकाल नहीं पाया. हम मंगल तक पहुंच गए, विभिन्न मंत्रालयों के विज्ञापन अपने अच्छे कामों का ढोल पीट रहे हैं, पर अफसोस कि हकीकत यही है कि भारत आज भी सिर्फ बेरोजगारों का ही नहीं, पढ़े-लिखे बेरोजगारों का भी देश है.

– सुस्मिता चौधरी, *कोलकाता, पश्चिम बंगाल*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं, जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

कश्मीर के छह हिस्से को मिला कर बातचीत हो

कश्मीर का एक सबसे बड़ा पेंच कश्मीर के बारे में, कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान के लोगों को जानकारियां बहुत कम हैं. जो कश्मीर जाते हैं, वो शिकारे में बैठने, कश्मीर की सुंदरता देखने, वहां घूमने, सैर-सपाटे के लिए जाते हैं. कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर के लोग कैसे जी रहे हैं, कश्मीर के नेताओं की सच्चाई क्या है, ये सब वो नहीं जानना चाहते हैं, न जानते हैं. दूसरी तरफ, पूरे भारत में कश्मीर को लेकर एक सामान्य राय बनी हुई है कि कश्मीर में धारा 370 खत्म होनी चाहिए और 370 खत्म होते ही कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा बन जाएगा. धारा 370 को वो कश्मीर के आंदोलन की वजह मानते हैं. ये इतनी बड़ी गलतफहमी है कि इसे न मीडिया दूर करता है, न सरकार दूर करती है, बल्कि ये गलतफहमी और बढ़ाती है कि कश्मीर के लोग 370 इसलिए बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वे पाकिस्तान में मिल सकें और वहां जितने आंदोलन हो रहे हैं, वो सब पाकिस्तान में शामिल होने के लिए हो रहे हैं.

इस सारी चीज का सबसे दुखद पहलू ये है कि सरकारी एजेंसियां, सरकार के प्रचार विभाग और मीडिया, सब ने एक अपवित्र गठजोड़ कर रखा है और हम कश्मीर की सच्चाई भारत के लोगों को बताना नहीं चाहते. इसका परिणाम ये हो रहा है कि जहां कश्मीर आज तक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का चेहरा नहीं देख पाया, वहीं पूरे भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं खत्म हो रही हैं और वो तरीके, जो तानाशाही तरीके हैं, जो दमन के तरीके हैं, उन्हें ही लोकतांत्रिक तरीका मानने का अभियान तेज हो गया है.

एक सबसे बड़ा खुलासा मैं ये करना चाहता हूं कि पिछले दिनों कश्मीर की कई यात्राओं के दौरान मेरी जितने कश्मीरी नेताओं से बातचीत हुई, खासकर सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, प्रोफेसर गनी बट, इन सब ने हर बार ये साफ कहा कि उनके आंदोलन का मतलब पाकिस्तान में जाना कतई नहीं है. वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार ने जो समझौता महाराजा हरि सिंह से किया था और अपनी तरफ से जो वादे संयुक्त राष्ट्र संघ में किए थे, उन वादों को भारत पूरा करे. उनका साफ कहना है, जो ऐतिहासिक रूप से सत्य है कि भारत का अंग कश्मीर कभी नहीं रहा. कश्मीर का मतलब कश्मीर के सारे हिस्से, तीन हिस्से जो आज हिंदुस्तान के साथ हैं, और तीन जो आज पाकिस्तान के साथ हैं. जब भारत और पाकिस्तान एक था यानी 1947 से पहले, अंग्रेजों के जमाने में, तब भी कश्मीर स्वतंत्र राज्य था. वहां पर अंग्रेजों ने कभी कब्जा नहीं किया था, जो एक हिंदुस्तान के रूप में देखा जाता, जो अंग्रेजों के अधीन था, जिनसे हमें आजादी मिली थी. वहां पर महाराजा हरि सिंह का शासन था. जब 1947 में आजादी मिली और उसके बाद जो बंटवारा हुआ, कत्लेआम हुआ, आपा-धापी हुई, उस आपा-धापी में भी कश्मीर में सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, न वहां कोई हिंदू मारा गया, न मुसलमान. उस समय एक समझौता, चूंकि कबायली कश्मीर में लूटपाट करने के लिए आ रहे थे, तो एक समझौता बंबई में महाराजा हरि सिंह के साथ भारत का हुआ कि हम कश्मीर में सेना भेजेंगे, कबायलियों से कश्मीरियों की रक्षा करेंगे. जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो भारत की सेनाएं एक मात्रा में वहां रहेंगी या कुछ मात्रा में रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर से अपनी सेनाएं 100 प्रतिशत हटा लेगा और उसके बाद वहां रायशुमारी होगी. कश्मीर के लोग ये तय करेंगे कि उन्हें हिंदुस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है. उस समय आजादी का तीसरा ऑप्शन, उस संयुक्त राष्ट्र संघ में दिए हुए प्रस्ताव में नहीं है, जिसपर भारत, पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र तीनों के हस्ताक्षर हैं. तब तक आर्टिकल 370 बनी रहेगी, जब तक आत्मनिर्णय की प्रक्रिया कश्मीर में शुरू नहीं होती है. अब इस ऐतिहासिक स्थिति को, बिना बताए 370 खत्म करने की मांग कितनी खतरनाक है. जो लोग सरकार में हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग प्रचार कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि जिस दिन आर्टिकल 370 खत्म हुई, उसी दिन कश्मीर अपने आप एक आजाद देश बन जाएगा. इसके बाद अगर हमने कुछ करने की कोशिश की, तो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां खासकर सिक्युरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र संघ कश्मीर में हस्तक्षेप करने का अधिकार पा जाएंगी और यहां पर विदेशी ताकतें अपना प्रजेंस दिखाती रहेंगी.

कश्मीरी नेताओं ने साफ कहा कि वो पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं. वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि भारत अपने इस वादे को पूरा करे, क्योंकि ये एक समझौता था. अगर कश्मीर के लोग, पूरे कश्मीर के लोग, हिंदुस्तान में शामिल होते हैं, तो वो एक जनमत संग्रह होगा, एक प्लेबेसाइट होगा. उनमें से कइयों ने कहा कि कौन पाकिस्तान के साथ जाना चाहेगा? पाकिस्तान खुद अपने को संभाल नहीं पा रहा है, इसके बावजूद अगर लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहेंगे, तो पाकिस्तान चले जाएं, पर अब एक नई तीसरी स्थिति बन गई है कि कश्मीर के लोग न पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, न भारत में मिलना चाहते हैं, वो आजाद रहना चाहते हैं. उनका कहना है कि हमारी आजादी की गारंटी पाकिस्तान भी दे और भारत भी दे. इस मांग पर बातचीत करने में क्या दिक्कत है? अगर पाकिस्तान अपनी सेनाएं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से, बलूचिस्तान से, गिलगित से, मुजफ्फराबाद से हटाने की बात करता है, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा. लेकिन मुझे लगता है कि वो नहीं हटाएगा, पर हम तो अपनी सेनाएं कम कर सकते हैं. हमारी सारी सेनाएं सीमा पर होनी चाहिए. हमारी सेनाएं शहर में नहीं होनी चाहिए. अगर ये हो जाता है और पाकिस्तान इस चीज को नहीं मानता है, तो ये सारी प्रक्रिया अपने आप समाप्त हो जाती है और जो आज की स्थिति है, वो बनी रहती है. इस सवाल पर अटल जी के जमाने में मुशर्रफ से बहुत बातचीत हुई थी और पाकिस्तान इसके लिए तैयार था कि हम कोई रास्ता निकालें और अभी की लाइन ऑफ कंट्रोल को हम अंतरराष्ट्रीय सीमा मान लें. लेकिन वाजपेयी जी के ही कुछ साथियों को लगा कि ऐसा नहीं करना

तब तक आर्टिकल 370 बनी रहेगी, जब तक आत्मनिर्णय की प्रक्रिया कश्मीर में शुरू नहीं होती है. अब इस ऐतिहासिक स्थिति को, बिना बताए 370 खत्म करने की मांग कितनी खतरनाक है. जो लोग सरकार में हैं, वो तो जानते हैं, लेकिन जो लोग प्रचार कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि जिस दिन आर्टिकल 370 खत्म हुई, उसी दिन कश्मीर अपने आप एक आजाद देश बन जाएगा.

चाहिए, इसलिए नेता में और प्रतिनिधि में फर्क होता है. वाजपेयी जी राष्ट्रभक्त थे, वे भारत का हित समझते थे और कैसे समस्याओं को हल किया जाए, ये उन्हें आता था. प्रधानमंत्री मोदी ने भी बांग्लादेश से सीमा का समझौता हल किया और उसके बारे में देश को कुछ नहीं बताया कि ये सीमा का समझौता किन शर्तों के तहत हुआ. बस बाद में ये पता चला कि कुछ हिस्सा इधर, कुछ हिस्सा उधर. मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, मैं फिर प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध करता हूं कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के समय की सारी फाइलों को, उनके जमाने के लोगों को, उनके वार्ता में शामिल राजनीतिज्ञों को, उनसे बातचीत कीजिए और पता कीजिए कि वाजपेयी जी ने क्या कदम उठाए थे? उन्हीं के आधार पर आप आज कश्मीर समस्या को हल करने की कोशिश कीजिए क्योंकि एक बार कश्मीरियों की भावनाओं को रड्डेस करना जरूरी है. उन्हें यह बताना जरूरी है कि हम उस अंतरराष्ट्रीय समझौते का सम्मान कर रहे हैं और जो समझौता हमारे पहले की सरकार ने किए हैं, हम उसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कल ये मांग चारों तरफ उठेगी कि भारत अंतरराष्ट्रीय समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है, तो फिर हम धीरे-धीरे सीरिया और अफगानिस्तान की स्थिति पर चले जाएंगे. हमारे सर के ऊपर कश्मीर है और हमें चाहिए कि हम कश्मीर के लोगों को अपना बनाएं. उनकी इस छोटी सी मांग को हम स्वीकार करें क्योंकि इसी मांग को लेकर वहां पिछले 115 दिनों से आंदोलन चल रहा है.

हमारे यहां एक बाजार बंद कराने के लिए, एक दिन का बंद कराने के लिए राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं का जुलूस निकालते हैं, तोड़-फोड़ करवाते हैं, जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाते हैं. इन राजनीतिज्ञों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर में बिना एक आदमी के सड़क पर निकले, बिना पत्थर चलाए दुकानें अपने आप बंद हैं, कारोबार अपने आप ठप हैं, आवागमन अपने आप ठप हैं, उसके ऊपर जनता का कोई दबाव नहीं है या वहां के राजनीतिक दलों का या वहां के तथाकथित अलगाववादियों का कोई दबाव नहीं है. वहां पर सरकार की फौजें हैं, सरकार की सीआरपीएफ है, सरकार की पुलिस है, जो घूमती रहती है, जो भी दुकान खोलने का विरोध करेगा, उसे वो गिरफ्तार कर लेंगे. उसके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, लेकिन कोई दुकानदार दुकान नहीं खोल रहा है. इस ताकत को, भारत सरकार को पहचानना चाहिए और कश्मीर के लोगों को ये वादा करना चाहिए कि हम उन सभी से बातचीत करेंगे, जिनके साथ पूरे कश्मीर के छह हिस्सों में एक तरह की काउंसिल बने, एक तरह का प्रशासन हो. इसके लिए जो भी स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, उनके साथ बातचीत शुरू होगी, ये वादा करने में क्या जाता है? सिर्फ इतना वादा करने से कश्मीर में स्थिति सामान्य हो सकती है और उसके बाद उस वादे पर अमल करने से हम समस्या के हल की तरफ भी बढ़ सकते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

पिछले दिनों कश्मीर की कई यात्राओं के दौरान मेरी जितने कश्मीरी नेताओं से बातचीत हुई, खासकर सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, प्रोफेसर गनी बट, इन सब ने हर बार ये साफ कहा कि उनके आंदोलन का मतलब पाकिस्तान में जाना कतई नहीं है. वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारत की सरकार ने जो समझौता महाराजा हरि सिंह से किया था और अपनी तरफ से जो वादे संयुक्त राष्ट्र संघ में किए थे, उन वादों को भारत पूरा करे. उनका साफ कहना है, जो ऐतिहासिक रूप से सत्य है कि भारत का अंग कश्मीर कभी नहीं रहा. कश्मीर का मतलब कश्मीर के सारे हिस्से, तीन हिस्से जो आज हिंदुस्तान के साथ हैं, और तीन जो आज पाकिस्तान के साथ हैं.

मत-मतांतर

सम्मान और स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं बनें

डॉ. बीआर अंबेडकर का संविधान सभा में दिया गया अंतिम भाषण जो उन्होंने 25 नवंबर 1949 को दिया था. वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे. उनका यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना तब था...

अगर हम लोकतंत्र को बनाए रखना चाहते हैं, न सिर्फ स्वरूप में बल्कि यथार्थ में, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार में पहली जरूरी चीज है कि हम अपने सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पाने के लिए संविधान के सुझाए रास्ते पर चलें. इसका मतलब है कि हम क्रांति के खूनी रास्तों को छोड़ दें. इसके मायने यह भी हैं कि हम सत्याग्रह, असहयोग और सिविल नाफरमानी के रास्तों को भी छोड़ दें. जब सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को पाने के लिए संविधान सम्मत कोई रास्ता ही न बचा हो, तो गैर संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है. पर जब संविधान सम्मत रास्ते खुले हों, तो गैर संवैधानिक तरीकों के लिए कोई कारण नहीं दिया जा सकता. ऐसे तरीके 'अराजकता के व्याकरण' के अलावे कुछ नहीं हैं, और जितनी जल्दी हम उन्हें छोड़ दें, यह हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा.

दूसरी बात, जो हमें ध्यान में रखनी होगी, वह है जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा दी गई चेतावनी, जो उन्होंने लोकतंत्र को सहेजने को इच्छुक हर शख्स को दी थी- अपनी स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति के, चाहे वह कितना महान क्यों न हो, चरणों में रखने से बचना, या उस पर भरोसा करते हुए उसे ऐसी शक्तियां देना कि वह लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए ही खतरा बन जाए, इस स्थिति से बचना. एक महान शख्सियत के प्रति कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, पर कृतज्ञता की भी सीमाएं होती हैं. जैसा कि आयरिश देशभक्त पैट्रिक डैनियल ओ' कोनेल ने कहा है कि सम्मान, प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हुआ जा सकता. यह चेतावनी दुनिया के किसी और देश के बरअक्स भारत के लिए ज़्यादा जरूरी है. भारत में भक्ति या नायक-पूजा ने, दुनिया के किसी और हिस्से के बरअक्स, राजनीति में कहीं ज़्यादे बड़ी भूमिका निभाई है. बतौर धर्म, भक्ति आत्मा की मुक्ति की राह भले हो सकती है, पर राजनीति में, भक्ति या नायक पूजा लोकतंत्र के अवसान और अंततः तानाशाही की ओर ही ले जाएगी.

तीसरी बात, जो हमें याद रखनी होगी कि हम राजनीतिक लोकतंत्र से ही संतुष्ट न हो जाएं. हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी जरूर बनाएं. जब तक राजनीतिक लोकतंत्र के आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो, सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र अधिक समय तक नहीं चल सकता. सामाजिक लोकतंत्र के मायने क्या हैं? इसका मतलब है, ऐसी जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता व बंधुत्व को जीवन के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती हो. स्वाधीनता, समानता व बंधुत्व के सिद्धांतों को एक त्रिकोण के अलग-अलग हिस्सों के रूप में नहीं देखा जा सकता. ये आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक-दूसरे से अलग किए जाने पर वे लोकतंत्र के उद्देश्य को हासिल करने में बाधक बन जाएंगे. स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से और स्वाधीनता व समानता को बंधुत्व से अलग नहीं किया जा सकता. बराबरी के बगैर, आज़ादी अल्पतंत्र को पैदा करेगी, जबकि बगैर आज़ादी के बराबरी व्यक्तिगत पहल में बाधक बनेगी. बगैर बंधुत्व के, आज़ादी और बराबरी हकीकत नहीं बन सकती. हमें एक पहरेदार की जरूरत होगी, जो इनके अनुपालन को तय कर सके. हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि भारतीय समाज में दो चीजों की मौजूदगी नहीं है. इनमें से एक है समानता. सामाजिक धरातल पर देखें तो भारतीय समाज श्रेणीबद्ध असमानताओं का समाज है. जहां कुछ लोगों के पास अथाह धन है तो वहीं बहुत से लोग गरीबी में जीवन बिता रहे हैं. 26 जनवरी 1950 के दिन हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं. राजनीति में तो हमारे पास समानता होगी पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी. राजनीति में तो हम 'एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट एक मूल्य' के सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में, अपने सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं के चलते, 'एक व्यक्ति एक मूल्य' के सिद्धांत को नकारते रहेंगे. हम कब तक ऐसे अंतर्विरोधों के जीवन में जीते रहेंगे? हम कब तक सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारना जारी रखेंगे? अगर हमने ऐसा और अधिक समय तक किया, तो हम ऐसा अपने राजनीतिक लोकतंत्र की कीमत पर ही कर रहे होंगे. हमें इस अंतर्विरोध को जल्द से जल्द मिटाना होगा, नहीं तो असमानताओं के शिकार लोग उस राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को उखाड़ फेकेंगे, जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से तैयार किया है.

दूसरी जिस चीज की कमी हमारे समाज में है, वह है बंधुत्व की भावना. बंधुत्व के मायने क्या हैं? बंधुत्व का मतलब है कि यदि भारतीय लोग एकमेव हैं तो उनके बीच एक साझी भाई-चारे की भावना का होना. यह सिद्धांत एका को बढ़ाता है और सामाजिक जीवन को मजबूत करता है, पर इसे हासिल करना कठिन है. मुझे याद है जब राजनीतिक रूप से सक्रिय हिंदुस्तानी 'भारत के लोग' कहने की बजाय 'भारतीय राष्ट्र' कहना अधिक पसंद करते थे. मेरा मानना है कि 'हम एक राष्ट्र हैं' ऐसा मानकर हम एक बड़े भ्रम को बढ़ावा दे रहे हैं. हजारों जातियों में बंटे लोग भला एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी यह बात हम समझ लें कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभी हम एक राष्ट्र नहीं हैं, उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा. क्योंकि तभी हम राष्ट्र बनने की जरूरत को बेहतर समझ पाएंगे और इस उद्देश्य को हासिल करने के तरीकों और साधनों के बारे में सोच पाएंगे. इस उद्देश्य की प्राप्ति कठिन है. जातियां राष्ट्र-विरोधी हैं. पहला कारण तो ये कि वे सामाजिक जीवन में अलगाव को बढ़ावा देती हैं. दूसरे वे एक जाति और दूसरी जाति के बीच ईर्ष्या और असहिष्णुता को बढ़ाती हैं. अगर हम सच में राष्ट्र बनना चाहते हैं तो हमें इन सब मुश्किलों से पार पाना होगा, क्योंकि बंधुत्व यथार्थ तभी हो सकता है जब राष्ट्र मौजूद हो. और बगैर बंधुत्व के समानता और स्वाधीनता महज दिखावा होंगी. ■

(अनुवाद- शुभनीत कौशिक).

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के 63 शहरों में 117 आवासीय परियोजनाओं की श्रृंखला

Call : 95340 95340

अफ़ीम बना नक्सलियों का टॉनिक

बिहार तथा झारखंड में व्यापक पैमाने पर अफ़ीम की खेती कर नक्सली न केवल आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं बल्कि अंगदी पांव भी जमाने लगे हैं. एनसीबी की लाख चौकसी के बाद भी अफ़ीम की खेती पर ग्रहण नहीं लग पा रहा है.

राजेश/गीता

नक्सलियों के नाक में नकेल डालने के लिए भले ही तरह-तरह की योजनाएं बनाई जा रही हो और समय-समय पर योजनाओं को मूर्तरूप भी दिया जाता हो. लेकिन हकीकत यह है कि बिहार और झारखंड न केवल नक्सलियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनते जा रहे हैं बल्कि व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती कर नक्सली आर्थिक रूप से संपन्न भी होते रहे हैं. बिहार व झारखंड से नक्सलियों के पैर नहीं उखड़ रहे, तो इसका सबसे बड़ा कारण नक्सलियों के द्वारा बिहार व झारखंड में अफीम की खेती करना ही है. नक्सलियों के साथ पुलिस की अक्सर भिड़ंत तो हो रही है, लेकिन नक्सलियों द्वारा की जा रही अफीम की खेती का बुनियाद नष्ट कर पाना पुलिस के लिए पानी में आग लगाने जैसा साबित हो रहा है. अफीम के सौदागर बन चुके नक्सलियों की खेती की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बिहार और झारखंड के कई इलाकों में परंपरागत खेती से तौबा कर किसान अफीम की खेती करना ही फायदेमंद समझने लगे हैं. मक्का व अन्य फसलों के बीच हो रही अफीम की खेती को खंगाल पाना पुलिस के लिए आसान भी नहीं है. ऐसी बात नहीं है कि अफीम की खेती पर पुलिस के द्वारा ग्रहण लगाने की कोशिश नहीं की जाती है, कोशिश तो समय-समय पर की गई है और कई बार फसलों को नष्ट भी किया गया है. लेकिन छोटे स्तर के किसानों पर शिकंजा कसने के अलावा पुलिस अब तक कुछ नहीं कर सकी है. अवैध रूप से अफीम की खेती कर संपन्न किसान और अधिक संपन्न तो हो ही रहे हैं, नक्सलियों के लिए टॉनिक भी पैदा कर रहे हैं. अफीम की खेती से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की आमद कर नक्सली अपनी ताकत में इजाफा करते जा रहे हैं और छोटे किसानों से लेकर बड़े-बड़े किसानों को आर्थिक संपन्नता प्रदान कर इन्हें अपने कुनबे में शामिल करते जा रहे हैं. नॉरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष अफीम की खेती कर नक्सलियों द्वारा लगभग दो सौ करोड़ रुपए एकत्रित किए गए हैं. इसके पहले भी अफीम की खेती से नक्सलियों को करोड़ों रुपए की आमदनी हुई है. कैमूर, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, पूर्णिया, लक्खीसराय, भागलपुर सहित कुछ अन्य इलाकों में भी अफीम की खेती तो हो ही रही है, जमुई, खगड़िया और गया में भी व्यापक पैमाने पर अफीम का उत्पादन किया जा रहा है. दरअसल इन इलाकों की भौगोलिक बनावट भी नक्सलियों के साथ-साथ अफीम की खेती करने वाले किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है और धीरे-धीरे किसानों की फौज अफीम की खेती का गुर सीखने की कला में निपुण होती जा रही हैं. वैसे जांच के दौरान यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कम समय में अधिक मुनाफे की चाहत रखने वाले स्थानीय व्यवसासियों द्वारा अफीम की खेती में निवेश किया जाता है. यहां तक कि व्यवसासियों द्वारा अफीम की खेती के लिए बीज सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के बावत व्यापक तौर पर फंडिंग भी किया जाता है. एनसीबी को लगातार मिल रही खुफिया रिपोर्ट के आधार पर गया, खगड़िया और जमुई जिलों में पिछले वर्ष 370 एकड़ में लगे अफीम के फसल को नष्ट किया गया था. लेकिन एनसीबी तथा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा अन्य इलाकों को खंगाल पाना दुरुह साबित हुआ. जबकि एनसीबी को यह जानकारी भी मिली थी कि इन तीन जिलों के लगभग 800 एकड़ में अफीम की खेती हो रही है. भौगोलिक बनावट को देखकर आकर्षित नक्सलियों द्वारा कोसी इलाके में अफीम की खेती की संभावना तलाशी जा रही है. अब जबकि अफीम की खेती का समय नजदीक आ गया है, रिपोर्ट आ रही है कि कोसी में भी अफीम की खेती होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. नदियों के गर्भ में बसे कोसी इलाके में अपना साम्राज्य कायम कर चुके अपराधी भी अब धीरे-धीरे नक्सलियों से सांठ-गांठ कर अफीम की खेती करने की चाहत में जुट गए हैं. जानकारों का कहना है कि कुख्यात दस्यु सरगना रामानंद यादव से अगर नक्सलियों का पंगा नहीं होता तो अब तक कोसी में व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती शुरू हो गई होती. माना जाता है कि कुख्यात दस्यु सरगना रामानंद यादव का नक्सलियों से पंगे का सबसे बड़ा कारण भी कहीं न कहीं अफीम की खेती ही है. कहा जाता है कि कुछ वर्ष पूर्व कुख्यात दस्यु सरगना रामानंद यादव की सहरसा पुलिस द्वारा नाटकीय ढंग से की गई गिरफ्तारी के बाद नक्सलियों ने कोसी तथा फरकिया में पांव पसारना शुरू कर दिया था. कुछ इलाकों में अफीम के फसल की बुआई भी की गई थी. लेकिन रामानंद के जेल से छूटते ही नक्सलियों ने कम से कम फरकिया से तौबा करना ही ठीक समझा. कई पुलिस अधिकारी भी दबे जुबान से इस बात को स्वीकारते हैं कि कुख्यात दस्यु सरगना रामानंद यादव द्वारा नक्सलियों से अक्सर पंगा लेने के कारण ही फरकिया में नक्सलियों का पांव नहीं जम सका. बिहार के कोसी अथवा फरकिया की स्थिति को कुछ देर के लिए नजरअंदाज कर अगर झारखंड की बात करें तो गया के पड़ोसी जिला अर्थात झारखंड के चतरा सहित कुछ अन्य इलाकों में पहले से अफीम की खेती होती रही है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अधिक मुनाफे की चाहत रखने वाले व्यवसायियों तथा किसानों की अफीम की खेती में दिलचस्पी बढ़ने से स्थिति भयावह होती जा रही है. समय रहते अगर नक्सलियों की 'अफीम आधारित अर्थव्यवस्था' को नष्ट नहीं किया गया तो बिहार के साथ-साथ झारखंड में न केवल नक्सलियों के अंगदी पांव जमने की संभावना प्रबल होगी बल्कि पुलिस को दिन में तारे दिखने की संभावनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता. एनसीबी के क्षेत्रीय निदेशक टीएन सिंह कहते हैं, अफीम की खेती का समय नजदीक आते ही एनसीबी की चौकसी बढ़ गई है. सभी स्तर पर कड़ी नजर रखकर अफीम की खेती को नष्ट करने सहित अन्य कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया गया है. गया-चतरा इलाके में खुफिया सहित अन्य स्तर पर भी कार्ययोजना बनाकर इसे मूर्तरूप देना शुरू कर दिया गया है. किसी भी कीमत पर अवैध रूप से हो रही खेती को नष्ट करना ही एनसीबी का लक्ष्य है. बहरहाल, दावे के मुताबिक एनसीबी अफीम की खेती को पूरी तरह नष्ट कर पाती है अथवा नहीं, यह तो समय ही बताएगा. लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर दावे के मुताबिक अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती को नष्ट नहीं किया गया तो पिछले वर्ष की तरह इस बार भी व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती होगी और स्थानीय पुलिस हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएगी.

अनोखा है अफ़ीम की खेती का तरीक़ा

बिहार तथा झारखंड में व्यापक पैमाने पर हो रही खेती के तरीकों पर अगर नजर डाली जाय तो अफीम की खेती का तरीका भी अनोखा है. किसानों को बीज से लेकर अन्य संसाधन नक्सलियों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं और नक्सलियों के संरक्षण में ही अफीम की खेती होती है.

अफीम का फसल तैयार होने के बाद बिचौलियों के द्वारा खरीद लिया जाता है. अफीम के तैयार फसल को बिचौलियों अथवा एजेंट के द्वारा महज 25 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाता है और 52 से 55 हजार रुपए प्रति किलो के हिसाब से इसकी बिक्री की जाती है. मुनाफे का 60 प्रतिशत हिस्सा नक्सलियों द्वारा लिया जाता है, जबकि 40 प्रतिशत हिस्से को बिचौलिए, किसान और खेती में निवेश करने वाले व्यवसायियों सहित अन्य के बीच बांटा जाता है. जानकारी के अनुसार अफीम की खेती से प्रति एकड़ 13 से 15 लाख रुपए की आमदनी होती है. आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अफीम के फसल की बुआई से पूर्व ही मुनाफे का 40 से 50 प्रतिशत हिस्सा नक्सलियों द्वारा वसूल लिया जाता है और मुनाफे का शेष हिस्सा फसल तैयार होने के बाद लिया जाता है. किसान भी दबे जुबान से इस बात को स्वीकारते हैं कि एक बार अफीम की खेती करने वाले किसानों को नक्सलियों द्वारा धमकाए जाने के कारण बार-बार खेती करना होता है. एक बार अफीम की खेती करने वाले किसान अगर बार-बार खेती करने से इंकार करते हैं तो नक्सलियों के सितम का शिकार होते हैं और बार-बार खेती करने के लिए मजबूर होते हैं तो पुलिसिया गिरफ्त का सामना करना पड़ता है. पुलिस की नजर में आने वाले किसानों की जिंदगी नरक बन जाती है. नक्सलियों तथा पुलिस के भय से किसानों को अंतत: खेती तो क्या घर-बार भी छोड़ना पड़ता है.

लीज़ पर ज़मीन लेकर धंधेबाज़ करते हैं अफ़ीम की खेती

एनसीबी तथा पुलिस से बचने के लिए कोसी के इलाकों में धंधेबाजों के द्वारा लीज पर जमीन देकर अफीम की खेती कराई जाती है. इस बात का खुलासा तब हुआ था जब बिहार के खगड़िया जिले के बभनगामा पंचायत स्थित खटहा दियारा के चार एकड़ में लगी अफीम के फसल को नष्ट किया गया था. एएसपी अभियान विमलेश चन्द्र झा के नेतृत्व में खगड़िया जिला पुलिस द्वारा जब जमीन मालिक महेन्द्र साव से पूछताछ की गई, तो उसने पुलिस को बताया था कि मानसी के किसी व्यक्ति को इन्होंने लीज पर जमीन दिया था. लीज पर जमीन लेने वालों के द्वारा खेत में किस फसल की बुआई की गई, इसकी जानकारी इसे नहीं है. एसएसपी विमलेश चन्द्र झा का कहना था कि नष्ट किए गए फसल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ो रुपए हो सकती है. इन्होंने यह भी कहा था कि मामले की जांच कर इस बात का पता जरूर लगाया जाएगा कि आखिर स्थानीय स्तर पर कौन-कौन इस तरह की खेती करने के जिम्मेवार हैं. हालांकि इसके बाद पुलिस या तो सुस्त पड़ गई अथवा गुनहगार अपना दामन बचाने में सफल हो गए. बहरहाल, स्थानीय लोगों का कहना है कि अन्य जगहों पर भी लीज पर जमीन लेकर धंधेबाजों के द्वारा व्यापक पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

"टी.आई." ब्राण्ड शटरपत्ती
क्वालिटी में सर्वोत्तम

AL™ अलीगढ़ लॉक्स प्रा.लि.

पीरमुहानी,जगत जननी माता मन्दिर के नजदीक, पटना-3
फोन : 0612-3293208, 6500301, Email : aligarhlocks@gmail.com

अपने क्षेत्र बिहार का प्रथम एवं एकमात्र TM प्रतिष्ठान ❖ नक्कालों से सावधान
कृपया हमारे इस नाम से मिलते-जुलते प्रतिष्ठान को देख भ्रमित न हों।

ईम्पोर्टेड केमिकल से तैयार, लैब टेस्टेड

पेन्ट डिस्टेम्पर
कोई भी हो
वॉल पुट्टी केवल ईटालियन वॉल पुट्टी

Laboratory Tested
Please Compare Lab Report
Laboratory Tested

Made from Imported Chemicals
ईटालियन
व्हाईट
वॉल पुट्टी
Slight Costly but Superior

लैब रिपोर्ट अवश्य चेक करें।
लैब रिपोर्ट हमारे सभी डीलर्स के यहां उपलब्ध है

प्रखण्ड स्तर या अपने क्षेत्र हेतू सप्लायर / डीलरशिप के लिए सम्पर्क करें।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाऐ
सीमेन्ट
कोई भी हो परन्तु
वाटरप्रूफिंग केमिकल सिर्फ
मिस्टर केमिस्ट

सीमेन्ट कोई भी हो लेकिन वाटरप्रूफिंग केमिकल मिस्टर केमिस्ट ही हो, क्योंकि मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग केमिकल ईम्पोर्टेड केमिकल से बनाया गया है, प्रत्येक पैक पर नम्बर युक्त होलोग्राम से नकल से पूरी तरह सुरक्षित १, ५, १०, २० एवं २०० लीटर होलोग्रामिक पैक में अब आपके यहां भी उपलब्ध। मिस्टर केमिस्ट वाटरप्रूफिंग सीमेन्ट की ताकत बढ़ाए, घर को मजबुत बनाए।
Mob : 9431234022 / 9435040133 Mail ID : mcwaterproof@yahoo.com

संकट में मानपुर का वस्त्र उद्योग

- कभी बिहार का मैनचैस्टर कहा जाता था
- बीएसपीसीबी के नोटिस से बुनकर परेशान
- 12 हज़ार से अधिक पावरलूम में लगे हैं 50 हज़ार लोग
- सरकारी पदाधिकारियों की मनमानी से परेशान है बुनकर

सुनील सौरभ

बिहार में पिछले ढाई दशक में कोई नए कारखाने नहीं लगे, लेकिन इतना हुआ कि पहले से जो कारखाने थे, वे किसी न किसी कारण से बंद होते चले गए. जिससे रोजगार प्राप्त लोग भी बेरोजगार होने लगे. बिहार के मगध क्षेत्र में ही आजादी के बाद कई ऐसे कारखाने लगे, लेकिन आज की तारीख में उन सभी का कोई अस्तित्व नहीं है. उदाहरण स्वरूप, गया कॉटन एण्ड जूट मिल, गुरारू चीनी मिल और वारिसलीगंज चीनी मिल, वर्षों से बंद पड़ा है. गया कॉटन एण्ड जूट मिल को तो कपड़ा मंत्रालय ने पूरी तरह बेच डाला. कर्मचारियों की यूनियनबाजी भी इन सबका प्रमुख कारण रही है. कभी देश के चर्चित उधोग समूह में शामिल रहा रोहतास इंडस्ट्रीज डालमियानगर के बारे में कहा जाता था कि यहां सुई से लेकर हवाई जहाज तक के पार्ट-पुर्जे का निर्माण होता है. लेकिन कर्मचारी यूनियन की स्वार्थ भरी राजनीति ने इसके संचालकों को उधोग बंद करने को विवश कर दिया. यहां काम करने वाले हजारों परिवार के सदस्य आज बड़े ही खराब स्थिति में हैं.

स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला गया का मानपुर का वस्त्र उधोग आज 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है. यहां चलने वाले 12 हजार से अधिक पावरलूम और सैकड़ों हस्तकरघों से प्रतिदिन लगभग 35 लाख रुपए का कपड़ा निर्माण किया जाता है. यहां उत्पादित कपड़े, बिहार के अलावा बंगाल, ओडिशा, असम, मणीपुर, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में जाते हैं. लेकिन कुछ महीने पूर्व बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (बीएसपीसीबी) ने मानपुर के पावरलूम तथा रंगाई-छपाई के कारखानों के संचालकों को नोटिस दिया तो बिहार का मैनचैस्टर कहे जाने वाले मानपुर के वस्त्र उधोग में कार्यरत बुनकरों एवं अन्य लोगों में दहशत फैल गई. इस नोटिस पर जिला प्रशासन तथा प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने कार्रवाई शुरू कर दी. आरोप यह लगाया गया कि पावरलूम तथा यहां स्थापित रंगाई-छपाई कारखानों से जो केमिकल युक्त पानी निकल रहा है, उससे आसपास के मुहल्लों तथा फल्गु नदी के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ गया है. प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने जिला प्रशासन को यह भी कहा कि मानपुर में जो भी पावरलूम तथा वस्त्र उधोग के कारखाने चल रहे हैं, उन्होंने नियंत्रण पर्षद से एनओसी नहीं लिया है. इसपर प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों ने बिना अनुमति वाले पावरलूम को बंद करने या कराने की बात कह दी. इस बात पर मानपुर वस्त्र उधोग में हड़कंप मच गया. लाचार होकर पावरलूम संचालकों और बुनकरों ने एक सप्ताह तक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर दिया. इसके कारण प्रतिदिन कमाने वाले मजदूरों और बुनकरों को प्लाई करने की नौबत आ गई. प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का कहना है कि मानपुर पटवाटोली में कई दशक से सूत से कपड़ा तैयार किया जाता है. कपड़ा तैयार करने से पूर्व सूत को कई रंगों में रंगा जाता है. सूत को रंगीन करने के लिए कई करखाने चल रहे हैं. इस कारखाने से निकलने वाला रंगीन पानी फल्गु नदी के भूगर्भ में जा रहा है. इस रंगीन पानी से फल्गु नदी और आसपास के इलाके प्रदूषित हो गए हैं. इन क्षेत्रों के चापाकल से निकला पानी पीने लायक नहीं है. इसी कारण से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने गया के डीएम को एक महीने में मानपुर के पावरलूम को बंद कराने का निर्देश दिया. जिससे कि फल्गु नदी को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके और आसपास बसे लोगों को स्वच्छ जल की आपूर्ति की जा सके. मानपुर पटवा टोली में प्रतिदिन 12 हजार पावरलूम से 10 लाख मीटर कपड़े का उत्पादन किया जाता हैं. प्रतिदिन यहां से करीब 40 लाख का कारोबार होता है. लेकिन बिहार सरकार ने बुनकरों को सुविधा देने के बजाय उनके पुस्तैनी धंधे को ही बंद कराने का निर्णय लिया है. वस्त्र उधोग बुनकर सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा ने बताया कि मानपुर में 12 हजार पावरलूम हैं. जिसमें करीब 30 हजार से अधिक बुनकर एवं मजदूर काम करते हैं. पावरलूम से निकलने वाले पानी से कोई प्रदूषण नहीं होता है. इसकी जांच कराई जाए. जांच कराने के लिए बुनकर तैयार हैं. प्रदूषण पर्षद ने एकतरफा निर्णय लिया है, जिसका विरोध हमलोग कर रहे हैं. वहीं एक और बुनकर नेता का कहना है कि बिहार में बुनकरों को उत्तर प्रदेश की तरह बिजली सस्ती नहीं मिलती है. जिससे मानपुर में तैयार वस्त्र का दाम उत्तर प्रदेश के अनुपात में ज्यादा हो जाता है. जिसके कारण यहां के बुनकर अपने माल को उत्तर प्रदेश नही भेज पाते हैं. सरकार द्वारा बुनकरों को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अभी तक अश्वासन ही मिलता रहा है. मानपुर के बुनकरों की मुख्य मांग है कि पटवाटोली सहित कई मुहल्ले में गिरने वाले रंगीन पानी की जांच पुन: कराई जाए, प्रदूषित जल को रोकने के लिए फिल्डर चैंबर बने, यहां के कारखाने से निकले रंगीन पानी को रोकने के लिए भागलपुर, बिहारशरीफ की तरह नियम लागू हो. ज्ञात हो कि मानपुर के वस्त्र उधोग का पटवाटोली, पिछले एक दशक से आई.आई.टी में बड़ी संख्या में जा रहे अपने छात्रों के कारण भी चर्चा में आया है. अबतक यहां से करीब 100 से अधिक लड़के आई.आई.टी कर चुके हैं. जिनमें से अधिकतर देश-विदेश के विभिन्न बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं. मानपुर पटवाटोली को पहले लोग बिहार का मैनचैस्टर कहा करते थे. लेकिन हाल के वर्षो में वस्त्र उत्पादन के साथ ही यहां का पटवाटोली आई.आई.टी उत्पन्न करने के कारण भी चर्चित हो गया है. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने यदि यहां के पावरलूम तथा वस्त्र उधोग को बंद करा दिया तो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लगभग 50 लाख से अधिक लोगों को बेरोजगार होना पड़ेगा. यहां के बुनकर तथा रंगाई-छपाई के कारखाना संचालकों ने अभी से ही दूसरे धंधे में घुसने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है. अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में बिहार का मैनचैस्टर कहे जाने वाले मानपुर का वस्त्र उधोग, अन्य बंद हो गए उधोगों की श्रेणी में आ जाएगा. पावरलूम के संचालक एवं बुनकर राज्य सरकार से अन्य राज्यों की तरह सुविधा देने तथा कारोबार को बढ़ावा देने की मांग करने में लगे हैं, जिससे कि हजारों-हजार लोगों की रोजी-रोटी बरकरार रहे.■

कभी देश के चर्चित उधोग समूह में शामिल रोहतास इंडस्ट्रीज डालमियानगर के बारे में कहा जाता था कि यहां सुई से लेकर हवाई जहाज तक के पार्ट-पुर्जे का निर्माण होता है. लेकिन कर्मचारी यूनियन की स्वार्थ भरी राजनीति ने इसके संचालकों को उधोग बंद करने को विवश कर दिया. यहां काम करने वाले हजारों परिवार के सदस्य आज बड़े ही खराब स्थिति में हैं.

फ़र्ज़ी जाति प्रमाण-पत्र पर चुनाव लड़ बनी जिप अध्यक्ष

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

बिहार में अलग-अगल तरह के फर्जीवाड़े का मामला सामने आते रहता है. फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के सहारे बड़े पैमाने पर शिक्षक नियुक्ति का मामला पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा है. इस मामले में सैकड़ों शिक्षकों की नियुक्ति रद्ध की जा चुकी है. सैकड़ों मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं. अब बिहार के गया जिले में फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर चुनाव लड़ कर जिला परिषद की अध्यक्ष बनने का मामला सामने आया है. शिकायत मिलने के बाद गया के जिला पदाधिकारी ने जब जांच करने का आदेश दिया तो मामला सही पाया गया. जिला पदाधिकारी ने जिला परिषद अध्यक्ष के पद पर करुणा कुमारी के निर्वाचन को रद्ध करने की अनशंसा राज्य निर्वाचन आयोग से की है. साथ ही उनपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोषी सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है. इस मामले में जिप अध्यक्ष करुणा कुमारी की छोटी बहन किरण कुमारी पर भी मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही हैं. फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर जीत कर आए एक अन्य जिप सदस्य पप्पू कुमार और गया जिले के मोहनपुर प्रखण्ड के मटिहानी ग्राम पंचायत के मुखिया तुला प्रसाद का भी निर्वाचन रद्ध करने की अनुशंसा की गई है. हालांकि मामला सामने आने के बाद भी जिप अध्यक्ष करुणा कुमारी और इनके परिवार के सदस्यों द्वारा लगातार इस बात को नकारा जा रहा था कि आरोप सही नही है. गया के जिला पदाधिकारी कुमार रवि से, संबंधित क्षेत्र के लोगों ने लिखित शिकायत की थी कि जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 गुरूआ से निर्वाचित होने वाली करुणा कुमारी, जिला परिषद निर्वाचन संख्या 34 डोभी से निर्वाचित होने वाले पप्पू कुमार और मोहनपुर प्रखंड मटिहानी ग्राम पंचायत से मुखिया पद पर निर्वाचित होने वाले तुला प्रसाद का जाति प्रमाण-पत्र गलत है. इस शिकायत पत्र को निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया. आयोग ने इस मामले की जांच करने की जिम्मेवारी डीएम कुमार रवि को सौपा. डीएम की जांच में तीनों जनप्रतिनिधियों का जाति प्रमाण-पत्र गलत पाया गया. गया के डीएम के आदेश पर गुरूआ के अंचल पदाधिकारी रेमीष केरकट्टा ने 13 अक्टूबर 2016 को जिला परिषद सदस्य करुणा कुमारी, डोभी के अंचल पदाधिकारी ने 3 अक्टूबर को जिला परिषद सदस्य पप्पू कुमार तथा मोहनपुर के अंचल पदाधिकारी ने 14 अक्टूबर 2016 को मुखिया तुला प्रसाद के जाति प्रमाण-पत्र को रद्ध कर दिया. करुणा कुमारी दांगी जाति का प्रमाण-पत्र देकर जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ी थीं. जबकि इनकी जाति कुशवाहा है, यह जाति आरक्षित वर्ग में नहीं आती. जिला परिषद का गुरूआ निर्वाचन क्षेत्र अतिपिछड़ा के लिए आरक्षित है. राज्य सरकार ने दांगी को अतिपिछड़ा वर्ग में शामिल किया है. जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि फर्जी जाति प्रमाण-पत्र पर चुनाव लड़ने वाले तीनों जनप्रतिनिधियों का जाति प्रमाण-पत्र बनाने वाले सरकारी कर्मियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाय. करुणा कुमारी का निर्वाचन आयोग से चुनाव रद्ध होता है, तो जिला परिषद् की अतिपिछड़ा सीट से जीत कर आने वाली एकमात्र महिला लक्ष्मीनिया देवी फिलहाल अध्यक्ष पर काबिज हो सकती हैं. करुणा कुमारी के गलत जाति प्रमाण-पत्र पर चुनाव लड़ने का मामला तब सामने आया, जब करुणा कुमारी तथा इनके पति चुनावी रंजिश को लेकर अपने क्षेत्र के लोगों को तंग करने लगे. इन्हें वोट नहीं देने वाले कई शिक्षकों को इन्होंने स्कूल में जाकर जांच के बहाने प्रडताड़ित किया.■

थाइराइड नवविवाहित महिलाओं के लिए बन रही परेशानी का कारण

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
DR. P.K. VERMA (MD)
DELHA, GAYA PRASANN CLINIC

डॉ. पी.के. वर्मा जो कि डेल्हा के प्रसन्न क्लीनिक में प्रेक्टिस करते हैं और वर्तमान में चर्चित गांव महाकार में पदस्थापित हैं ने बताया कि वह महाबौध फाउन्डेशन से भी जुड़े हुए हैं और जनसेवा के उद्देश्य से पहला मंगलवार और तिसरे गुरूवार को फ्री इलाज और चेकअप करते हैं जिसमें डाइबिटिज, अस्थमा, थाइराइड के एवं अन्य मरीज आते हैं।

थाइराइड – के बारे में बताते हुए डॉ. पी.के. वर्मा ने कहा कि यह गले की ग्रन्थी है जिसमें परेशानी होने पर दुर्बलता, झुर्री आना, थकान, ज्वाइन्ट पेन, और मोटापा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब शरीर के हारमोन सही से बाहर नही निकल पाते या असमय काम करना बंद कर देते हैं तो यह परेशानी आती है। डॉ. वर्मा का कहना है कि खासकर नव विवाहिता महिलाओं के लिए यह सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बन जाता है आप इसे यह न समझें कि यह बांझपन का कारण है लेकिन अक्सर थायराइड के केस में महिलाएँ बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है या कन्सीभ नहीं कर पाती है। इसके प्रभाव से बचने के उपाय है कि आप रोज प्राणायाम (उज्जैयी प्राणायाम) को करें। जिसमें गले से एक प्रकार का स्वर निकाला जाता है। खाने में हमेशा आयोडिन नमक का इस्तेमाल करें और प्रीजर्व यानि सहेज कर रखी गयी चीजों के खाने से बचें अर्थात स्वच्छ और ताजी चीजें खायें और स्वस्थ रहें। आइये थाइराइड के बारे में कुछ और जान लें : – थायरायड की प्राकृतिक चिकित्सा– थायराइड के लिए हरे पत्ते वाले धनिये की ताजा चटनी बना कर एक बड़ा चम्मच एक गिलास पानी में घोल कर पीए रोजाना.... एक दम ठीक हो जाएगा (बस धनिया देसी हो उसकी सुगन्ध अच्छी हो) आहार चिकित्सा ""– सादा सुपाच्य भोजन,मट्ठा,दही,नारियल का पानी,मौसमी फल, ताजी हरी साग –सब्जियां, अंकुरित गेंहू, चोकर सहित आंटे की रोटी को अपने भोजन में शामिल करें। परहेज –मिर्च–मसाला,तेल,अधिक नमक, चीनी, खटाई, चावल, मैदा, चाय, काफी, नशीली वस्तुओं, तली–भुनी चीजों, रबड़ी,मलाई, मांस, अंडा जैसे खाद्यों से परहेज रखें। अगर आप सफेद नमक (समुन्द्री नमक) खाते है तो उसे तुरन्त बंद कर दें और सैंधा नमक ही खाने में प्रयोग करें, सिर्फ सैंधा नमक ही खाए। ■ – भारती

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

पारिवारिक कलह और महत्वाकांक्षा के

पा के सामने ही डूब रही सपा!

प्रभात रंजन दीन

मुलायम परिवार में महत्वाकांक्षा के टकराव ने समाजवादी पार्टी को तहस-नहस करके रख दिया. समाजवादी पार्टी का विभाजन तो हो चुका, तलवारें तो चल चुकीं, बस युद्ध की औपचारिक मुनादी नहीं हुई. समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह के बहिष्कार की औपचारिक घोषणा ने अखिलेश यादव और उनके समर्थकों के पार्टी से अलग होने की सनद पहले ही दे दी थी. फिर बाद के अप्रत्याशित और अनापेक्षित घटनाक्रम ने कसर पूरी कर दी. कुछ ही दिनों के अंतराल में सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव तक पार्टी से निकाल दिए गए. उसके पहले एमएलसी उदयवीर सिंह निकाले गए थे. फिर मंच पर शिवपाल और अखिलेश से लेकर शिवपाल और अखिलेश के समर्थकों के बीच तक हाथापाई की स्थिति पहुंची. फिर अखिलेश ने शिवपाल समेत कुछ मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया. फिर शिवपाल ने अखिलेश समर्थक मंत्री पवन पांडेय को पार्टी से बाहर निकाल दिया. फिर शिवपाल ने अपने सरकारी आवास से अपने नेम प्लेट से मंत्री पद हटा दिया. यानि, एक तरफ सुलह के संवाद चलते रहे तो दूसरी तरफ कलह के मवाद बहते रहे. इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर नए सिरे से राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर दी. इस मुलाकात को लेकर तरह-तरह के कयास लग रहे हैं. समाजवादी पार्टी में मचा घमासान थमने के बजाय और तल्ख होता जा रहा है. एक तरफ शिवपाल तो दूसरी तरफ अखिलेश अपना-अपना पावर दिखाने में लगे हैं. समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक तौर पर दिखते तो शिवपाल के साथ हैं, लेकिन बेटे अखिलेश के खिलाफ तकनीकी सख्ती दिखाने से परहेज करते हैं. राजनीति के विश्लेषक सपा की इस दुर्गति के लिए सीधे तौर पर मुलायम को ही दोषी मानते हैं. उनका कहना है कि मुलायम अगर सख्ती और संतुलन रखते तो पार्टी इस हालत में नहीं पहुंचती.

मुलायम की इसी ढिलाई का नतीजा है कि पिछले कई महीनों से समाजवादी पार्टी के अलमबरदारों का चल रहा पारिवारिक झगड़ा आज प्रदेश और देशभर में नक-कटावन प्रसंग बन गया है. इस कलह की वजहों के बारे में जो कोई भी बोल रहा है, उसे बर्खास्तगी का अधिनायकवादी फरमान पकड़ा दिया जा रहा है. अखिलेश का साथ देने में मुलायम परिवार के ही वरिष्ठ सदस्य प्रो. रामगोपाल बाहर हो गए. रामगोपाल के लिए उनके भाई शिवपाल ने वैसे ही बोल बोले जो अमर सिंह उनके बारे में बोलते हैं. शिवपाल यादव ने रामगोपाल को भाजपा का एजेंट बताया, षड्यंत्रकारी बताया, भ्रष्ट कहा, उनके बेट-बहू को घसीटा और बिहार महागठबंधन तोड़ने का जिम्मेदार बताया. रामगोपाल ने अपनी बर्खास्तगी के बाद कहा कि मुलायम आसुरी शक्तियों से घिरे हुए हैं. उन्होंने कहा, मैं समाजवादी पार्टी में रहूं या ना रहूं लेकिन इस धर्मयुद्ध में अखिलेश यादव के साथ हूं. यह लड़ाई सरकार और पार्टी में अपने वर्चस्व को लेकर अखिलेश और शिवपाल के बीच चल रही है. अखिलेश जब 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी शिवपाल ने बाधा डालने की कोशिश की थी. इस कलह प्रकरण ने कई ऐसे सच भी सामने ला दिए, जिनके बारे में सामान्य लोगों को कुछ भी पता नहीं था. जब मुलायम ने पार्टी मंच से कहा कि वे अमर सिंह के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते क्योंकि अमर सिंह ने उन्हें जेल जाने से बचाया था, नहीं तो उन्हें कम से कम सात साल की सजा जरूर हुई होती, यह सुनकर पार्टी के नेता भी हतप्रभ रह गए. इस कथन ने अमर सिंह के हुनर और उस पर नेताजी की आश्वस्ति को खुद-ब-खुद रौशनी में ला दिया.

बहरहाल, सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव के चुनाव आयोग जाने से भी यह कयास लगाया जा रहा है कि विभाजन की औपचारिक घोषणा में अधिक वक्त नहीं रह गया है. मुलायम पक्षीय सपा ने पिछले दिनों किरणमय नंदा को मीडिया के सामने आगे कर संधि-सुलह का जिस तरह का प्रहसन खेला था उससे ही साफ पता चल गया था कि पार्टी का मुलायम-खेमा घबराया हुआ, चिंतित और आशंकित है. तभी बार-बार यह कहा गया कि अखिलेश ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे. दरअसल, दो दिन पहले ही मुलायम ने यह कह कर कि चुनाव के बाद विधानमंडल दल नेता का चुनाव करेगा, मामले को फंसा दिया था. मुलायम ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला कर कहा था कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बाद में तय होगा. मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा. मुलायम के इस बयान के बाद अखिलेश ने खुले तौर पर यह घोषित कर दिया कि चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे. अखिलेश ने इस बारे में खुल कर कहा कि कोई साथ दे या न दे, वे अकेले चुनाव प्रचार करेंगे. सपा के अखिलेशी खेमे ने भी बाकायदा इस बारे में मीडिया के समक्ष बयान देने शुरू कर दिए. मुलायम ने किरणमय नंदा को सामने लाकर यह दिखाने की भी कोशिश की कि यह मसला पारिवारिक नहीं, बल्कि पार्टीगत है. लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है. किरणमय नंदा पूरी तरह पूर्व निर्देशित तौर-तरीके से अपना किरदार निभाने की कोशिश कर रहे थे. नंदा बार-बार यह कह रहे थे कि वे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से बोल रहे हैं, लेकिन लोग यह समझ रहे थे कि यह डायलॉग उनका अपना नहीं है, क्योंकि पार्टी में उनकी हैसियत सब जानते हैं.

समाजवादी पार्टी की स्थापना के 25वें वर्ष में पार्टी के टूटने का सांकेतिक दस्तावेज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के उस पत्र से तैयार हो गया जो उन्होंने 19 अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को लिखा. अखिलेश ने लिखा कि तीन नवंबर से वे चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे और प्रदेश भर का दौरा करेंगे. यानि, पांच नवंबर को होने वाले रजत जयंती समारोह में वे शरीक नहीं रहेंगे. हालांकि बाद में उन्होंने यह भी कहा कि वे चनाव प्रचार के लिए भी निकलेंगे और रजत जयंती समारोह में भी मौजूद रहेंगे. अखिलेश ने सपा प्रमुख को लिखा था कि वे तीन नवंबर से पूरे प्रदेश भर में 'विकास से विजय की ओर' अग्रसरित होने का बिगुल फूकेंगे. अखिलेश की वह चिट्ठी स्पष्ट विद्रोह की मुनादी मानी गई थी. वैसे, इस पत्र के पहले अखिलेश खेमे की तरफ से रजत जयंती समारोह के बहिष्कार की बाकायदा औपचारिक घोषणा कर दी गई थी. अखिलेश के चुनाव प्रचार दौरे की सूचना प्रदेश भर की सांगठनिक इकाइयों को भेज दी गई, ताकि रजत जयंती के पहले ही साफ हो जाए कि कौन अखिलेश की तरफ हैं और कौन शिवपाल की तरफ. जो तिकड़मबाजी पिछले कुछ अर्से में मुलायम परिवार में हुई, उतनी तो दो सियासी दलों के बीच भी नहीं होती. रजत जयंती समारोह के लिए बनी आयोजन समिति का प्रमुख जानबूझ कर गायत्री प्रसाद प्रजापति को बनाया गया, जिसे अखिलेश ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, पर बाद में बुझे मन से वापस लेना पड़ा था. शिवपाल यह जानते हैं कि गायत्री प्रजापति को अखिलेश पसंद नहीं करते, लेकिन पार्टी में वे सारे फैसले ऐसे ही ले रहे हैं जो अखिलेश पर नागवार गुजरे.

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने भी सपा के रजत जयंती समारोह के बहिष्कार का संकेत दे दिया था. उन्होंने मुलायम सिंह को पत्र लिख कर उन्हें आगाह किया था कि वे जो कुछ कर रहे हैं, उससे पार्टी का सत्यानाश हो जाएगा और उसके लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी. रामगोपाल ने मुलायम को लिखा, 'समाजवादी पार्टी को आपने बड़ी मेहनत से बनाया था. पार्टी चार बार सत्ता में भी पहुंची. पिछली बार किसी अन्य दल के समर्थन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी. उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जो कार्य किए हैं, वो पूरे देश के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहे हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस समय निर्विवाद रूप से प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ उससे पार्टी का मतदाता निराश और हताश है. अब तो उसमें नेतृत्व के प्रति आक्रोश भी उत्पन्न हो रहा है. लोगों को (शेष पृष्ठ 13 पर)

ये शब्द बताते हैं अखिलेश की पीड़ा

जब अखिलेश ने कहा कि अपना नाम भी उन्होंने ही तय किया था, लिहाजा वे अकेला चलना बखूबी जानते हैं, तो वह वह स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि परिवार में किस तरह की परिस्थितियों से वे दो-चार होते रहे हैं. समाजवादी पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि तमाम तिकड़मों, खींचतान और विरोधाभासों के बीच अखिलेश ने पूरी मर्यादा से पांच साल तक सरकार चला ली. मुलायम, अमर, शिवपाल, आजम के चार कोनों से लगातार खींचे जाने के बावजूद अखिलेश ने कभी आपा नहीं खोया और कभी अनुशासन से नहीं डिगे. उसी मर्यादा से उन्होंने नैतिकता का स्टैंड भी जनता के समक्ष साफ किया. माफिया सरगना मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल के सपा में विलय से लेकर अपराधियों और दागियों को टिकट देने तक के मसले पर अखिलेश ने विरोध जताया. पार्टी नेतृत्व ने उनकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन जनता ने इसे अपने मन में दर्ज कर लिया. आम सपाइयों से भी बात करें तो पलड़ा अखिलेश की तरफ का ही भारी दिखता है. आम सपाइयों का भी मानना है कि अखिलेश के विशाल होते कद से अग्रजतों को तकलीफ हो रही है. जब अखिलेश ने सफलता-पूर्वक सरकार चला कर दिखा दिया तो फिर उनके पर क्यों नोंचे जा रहे हैं? क्या अखिलेश को अपना करियर बनाने का हक नहीं है? अखिलेश पर जब कोई दाग नहीं है, पार्टी की अच्छी छवि बनी है और जनता के बीच उन्हीं का चेहरा स्वीकार्य है, तो फिर उन्हें किनारे लगाने की साजिश क्यों हो रही है? एक सपाई ने झटके से यह सवाल सामने रखा, तो वहां मौजूद कई पत्रकारों को भी शिवपाल और उनके खास समर्थकों के चेहरे से उन सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए थे. अखिलेश समर्थक और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लोकप्रियता का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. राजनीति के मौजूदा दौर में अखिलेश जैसे बेदाग, विनम्र और संवेदनशील व्यक्तित्व की सर्वथा कमी है. इसीलिए जनता का उनके प्रति बेमिसाल भरोसा है. वे जहां भी जाते हैं, उन्हें देखने-सुनने वालों की भीड़ जमा हो जाती है. जनता विकास चाहती है. विकास की गारंटी अखिलेश यादव ही हो सकते हैं. राजेंद्र चौधरी ने यह कह कर पूरे माहौल का स्पष्टीकरण दे दिया कि अखिलेश यादव ने अब तक कहीं भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया. प्रदेश की जनता को बहुत अरसे बाद साफ-सुथरी राजनीति के दर्शन हुए हैं, मूल्य बढ़ते हैं, जनता इसे खोना नहीं चाहती. अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत से राजनीति के शून्य को भरा है. चौधरी यह भी बोल गए कि अखिलेश ही डॉ. राम मनोहर लोहिया की वैचारिक विरासत का नेतृत्व कर रहे हैं. अखिलेश के कारण ही माफियाओं से मुक्त राजनीति का आग्रह बना है और नैतिकता के पक्ष को बल मिला है. ■

टकराव में बिखर गई समाजवादी पार्टी

जॉर्डिंग कहीं अमर सिंह के प्लान्टेड तो नहीं!

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राजनीति को आधुनिक पेशेवर तकनीक के जरिए भी साधने की कोशिश कर रहे हैं. अखिलेश को उम्मीद है कि युवाओं का समर्थन हासिल कर वे राजनीति की ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं. इसी इरादे से अखिलेश ने मशहूर राजनीतिक रणनीतिकार स्टीव जॉर्डिंग की सेवाएं लेने का निर्णय लिया. जॉर्डिंग हावर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी विभाग के प्राफेसर हैं. वे हिलेरी क्लिंटन के चुनाव प्रचार का मैनेजमेंट भी संभाल रहे हैं. जॉर्डिंग,अखिलेश की साफ़ और विकासवादी छवि को लेकर गांवों और कस्बों में धूम मचाएंगे. हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि स्टीव जॉर्डिंग की सेवाएं लेने का फैसला पार्टी का है. एक नेता ने यह भी आशंका जाहिर की कि स्टीव जॉर्डिंग अमर सिंह के करीबी हैं और कहीं उन्हें अमर सिंह ने ही तो प्लान्ट नहीं किया है! ऐसे में वे अमर सिंह और शिवपाल के ही इशारे पर अधिक काम करेंगे. अमर सिंह, बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन के करीबी हैं और क्लिंटन फाउंडेशन को चंदा देने-दिलाने के विवादास्पद प्रसंग में भी नाम कमा चुकेहैं. बहरहाल, अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन के चुनाव अभियान प्रबंधक व राजनीतिक सलाहकार स्टीव जॉर्डिंग को सपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार अभियान को नए सिरे से डिजाइन कराना है. जॉर्डिंग की सलाह पर ही फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन को अम्बैसेडर बनाकर समाजवादी पेंशन योजना के प्रचार का बड़ा अभियान शुरू किया गया. स्टीव की टीम जमीनी स्तर पर चुनाव प्रबंधन का खाका तैयार कर रही है. लेकिन भारी कलह के कारण विभाजन के मुहाने पर खड़ी समाजवादी पार्टी के लिए जॉर्डिंग क्या जुगाड़ कर पाएंगे, इस पर संशय है. ■

पृष्ठ 12 का शेष

कष्ट ये है कि पहले नंबर पर चल रही पार्टी कुछ इन गिने-चुने लोगों की गलत सलाह के चलते काफी पीछे चली गई है. ये जो लोग आजकल आपको सलाह दे रहे हैं, जनता की निगाह में उनकी हैसियत शून्य हो गई है. पार्टी जिसे चाहे उसे टिकट दे, लेकिन जीतेगा वही जिसकी हैसियत होगी और पार्टी तभी चुनाव जीतेगी जब पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव होंगे. अगर आप चाहते हैं कि पार्टी फिर 100 से नीचे चली जाए तो आप चाहे जो फैसला लें, लेकिन एक बात याद रखें कि जो जनता आपकी पूजा करती है, समाजवादी पार्टी बनाने के लिए, वही जनता समाजवादी पार्टी के पतन के लिए आपको और केवल आपको दोषी ठहराएगी. इतिहास बहुत निष्ठुर होता है, ये किसी को बख्शता नहीं.'

रामगोपाल के इस पत्र के परिप्रेक्ष्य में सपा के ही नेता कहने लगे हैं कि पार्टी के पतन के लिए मुलायम जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनकी सहमति के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता. मुलायम को लिखे इस पत्र के बाद सपा में सुगबुगाहटें और तेज हो गईं. यह इतिहास ही बना कि पार्टी में पहली बार किसी वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को इतनी तल्ख चिट्ठी लिखी. इस पत्र ने मुलायम और उनके सिपहसालारों को स्पष्ट तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया. रामगोपाल ने बाद में कहा भी कि प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार ने जो काम किए हैं, वे पूरे देश के लिए पथ प्रदर्शक हैं. पार्टी चुनाव तभी जीतेगी जब अखिलेश चेहरा होंगे. अखिलेश निर्विवाद रूप से प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं. लोगों में नेतृत्व के प्रति नाराजगी है. स्थिति यह है कि पार्टी के मुख्यमंत्री-विरोधी तत्वों को जनता ही नापसंद कर रही है और इसका असर चुनाव में दिखेगा. रामगोपाल ने यह भी कहा कि मुलायम को जो लोग सलाह दे रहे हैं, जनता की निगाह में उनकी हैसियत शून्य है. रामगोपाल के पत्र से ही साफ हो गया कि पार्टी के डूबने में अब कोई कसर बाकी नहीं. इसके बाद विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह ने भी मुलायम को पत्र लिख कर आर-पार की रेखा खींच दी. उदयवीर सिंह ने सपा प्रमुख को पत्र लिख कर कहा कि वे अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दें और खुद संन्यास लेकर पार्टी को नष्ट होने से बचा लें. अखिलेश यादव को हर दृष्टिकोण से योग्य बताते हुए उदयवीर ने अखिलेश को नेतृत्व सौंप देने की मांग की और पार्टी में हड़कंप मचा दिया. उदयवीर ने अखिलेश यादव की सौतेली मां पर षडयंत्र रचने का आरोप लगाकर और सनसनी फैला दी. एटा-मैनपुरी से एमएलसी उदयवीर ने कहा कि अखिलेश यादव के खिलाफ उनकी सौतेली मां साधना गुप्ता साजिश कर रही हैं. उदयवीर ने कहा कि शिवपाल यादव भी साजिश में हिस्सेदार हैं. उन्होंने मुलायम को सतर्क रहने के लिए भी कहा. उदयवीर ने मुलायम सिंह यादव को चार पेज की लंबी चिट्ठी लिखी थी. लेकिन मुलायम पर न तो रामगोपाल के पत्र का कोई असर पड़ा और न उदयवीर के पत्र का. हां, उदयवीर के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की भूमिका शुरू हुई, जो उनके निष्कासन पर आकर ही थमी. इसके बाद रामगोपाल पर भी वही कार्रवाई दोहराई गई. सपा के ही नेता कहते हैं कि रामगोपाल पर कार्रवाई होने का मतलब है पार्टी की इतिश्री.

मुलायम के खिलाफ मुखर विद्रोह का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि समाजवादी पार्टी के अखिलेशवादी खेमे ने रजत जयंती समारोह और मुलायम के कार्यक्रमों के बहिष्कार का बाकायदा औपचारिक ऐलान कर दिया. समाजवादी पार्टी मुख्यालय के समानांतर बने जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के दफ्तर में अखिलेश समर्थकों ने 18 अक्टूबर को बैठक की और बहिष्कार का सर्वसम्मत फैसला लिया. यह पार्टी नेतृत्व को खुली चुनौती थी, क्योंकि रजत जयंती समारोह की कामयाबी के लिए मुलायम खास तौर पर मीडिया के समक्ष प्रस्तुत हुए थे. इस खेमे ने मीडिया को जो आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति भेजी वह पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुले विद्रोह का ऐलान था. विज्ञप्ति में कहा गया कि बसपा शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन में जिन लोगों ने सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया और जिन लोगों की वजह से प्रदेशभर में समाजवादी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का माहौल बना, उन्हें ही चुन-चुन कर बाहर निकाला गया. एमएलसी सुनील सिंह यादव, आनन्द भदौरिया, अरविन्द प्रताप यादव, संजय लाठर के साथ-साथ प्रदेश युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश यादव, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष मो. एवाद, यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव दुबे और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव को झूठी शिकायतों के आधार पर समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. अनुशासनहीनता के आरोप दुर्भाग्यपूर्ण हैं. एमएलसी संतोष यादव सनी, विधायक अरुण वर्मा, जयसिंह जयंत, पूर्व प्रदेश महासचिव युवजन सभा राहुल सिंह, पूर्व राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा अवधेश वर्मा, कर्नल सत्यवीर सिंह यादव, जुगुल किशोर बाल्मीकि, पूर्व प्रदेश महासचिव यूथ ब्रिगेड अरुण यादव, रामसागर यादव, विजय यादव, प्रदीप तिवारी, ओम नारायण यादव, पूर्व प्रदेश सचिव युवजन सभा प्रदीप शर्मा, प्रदेश सचिव छात्रसभा मनीष दुबे, प्रदेश महासचिव छात्रसभा करुणेश द्विवेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवजन सभा अरविन्द गिरि, पूर्व जिलाध्यक्ष युवजन सभा राबिन सिंह यादव, दानिश सिद्दीकी, प्रदेश सचिव छात्र सभा वैभव सैनी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी शिवकुमार यादव, प्रदेश मीडिया प्रभारी छात्रसभा मनोज यादव, जीतू वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष छात्रसभा सर्वेश यादव, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय भूपेन्द्र सिंह यादव, योगेश यादव गाजीपुर, अभिषेक यादव, एमएलसी उदयवीर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक सभा फिदा हुसैन अंसारी, त्रिशूलधारी सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष युवजन सभा कार्तिक तिवारी शैलू और नागेन्द्र सिंह यादव के हस्ताक्षरित बयान में कहा गया, 'हम सभी साथियों और पदाधिकारियों ने युवा नेताओं के निष्कासन के विरोध में निर्णय लिया है कि पांच नवंबर 2016 को समाजवादी पार्टी के प्रस्तावित स्थापना दिवस (रजत जयंती समारोह) में शामिल नहीं होंगे. हम सभी हजारों युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में निष्ठा एवं आस्था व्यक्त करते हैं.' विज्ञप्ति के साथ पार्टी के अखिलेश समर्थकों की भारी फेहरिस्त भी संलग्न की गई थी. उल्लेखनीय है कि अखिलेश समर्थक नेताओं के निकाले जाने के बाद समाजवादी पार्टी के सारे युवा संगठनों के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था.

समाजवादी पार्टी की छाती पर सवार होकर लिए गए इस फैसले के फौरन बाद ही अखिलेश ने मुलायम को पत्र लिख कर पूरी पार्टी को सकते में ला दिया. इसका असर यह हुआ कि पार्टी का शिवपाल खेमा फौरन सक्रिय हो गया, बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया. रजत जयंती समारोह की तैयारी समिति की लिस्ट भी जारी कर दी गई, जिसके मुखिया स्वनामधन्य गायत्री प्रजापति बनाए गए. तैयारी समिति के अन्य सदस्यों में नारद राय, पारसनाथ यादव, कमाल अख्तर, मनोज पांडेय और विशंभर प्रसाद निषाद के नाम भी शुमार हैं. तुरत-फुरत 21 अक्टूबर को प्रदेश भर के जिला अध्यक्षों और जिला महासचिवों को लखनऊ तलब कर उन्हें हिदायत दी गई और उनकी नब्ज भी टटोली गई. रजत जयंती समारोह को कामयाब करने के 'टार्गेट' दे दिए गए और तीन नवंबर से शुरू हो रहे अखिलेश के दौरे से दूरी बनाए रखने की ताकीद की गई. फिर आनन-फानन में 22 अक्टूबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली गई. प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शरीक होने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पहले तो औपचारिकता के तहत भी आमंत्रण नहीं भेजा गया. लेकिन जिला इकाइयों की तरफ से जमीनी तापमान मिलने के बाद शिवपाल ने फौरन ही पैंतरा बदला और अखिलेश से मिलने उनके सरकारी आवास पहुंच गए. उन्होंने अखिलेश को कार्यकारिणी की बैठक में शरीक होने का आमंत्रण भी दे डाला और रजत जयंती समारोह में उपस्थित रहने का आग्रह भी कर दिया. शिवपाल और अखिलेश के बीच देर रात तक बातचीत चलती रही, लेकिन नतीजा क्या निकला, इसे प्रदेश और देशभर के लोगों ने सार्वजनिक तौर पर देख लिया. ■

संकट से उबारेगा महागठबंधन

विभाजन के मुहाने पर खड़ी समाजवादी पार्टी को संकट से उबारने के लिए फिर से महागठबंधन में शामिल होने की जद्दोजहद हो रही है. मुलायम ने महागठबंधन में फिर से शामिल होने की पहल शुरू कर दी है. जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वरिष्ठ नेता शरद यादव के अलावा राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजित सिंह व कई अन्य नेताओं से संपर्क किया गया है. मुलायम ने डॉ. लोहिया और चौधरी चरण सिंह के समर्थकों को एक मंच पर आने का आह्वान दोहराया है. उन्होंने शिवपाल के जरिए सभी पुराने साथियों को समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह में शामिल होने के लिए न्यौता भेजा है. आपको याद ही होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम ने ही पहल करके नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, एचडी देवगौड़ा, अजित सिंह समेत सभी समाजवादियों को इकट्ठा कर महागठबंधन की शक्ल तक पहुंचाया था. मुलायम सिंह यादव को ही इसका सर्वमान्य नेता भी चुना गया था, लेकिन आखिरी दौर में मुलायम ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया. तब भी यह बात उठी थी कि रामगोपाल के दबाव में सपा, महागठबंधन से अलग हुई. अब तो समाजवादी परिवार के झगड़े में भी यह बात उजागर की जा रही है कि रामगोपाल के कहने पर ही मुलायम ने महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया था. अब रामगोपाल को ठिकाने लगा कर समाजवादी पार्टी महागठबंधन में शामिल होकर अपनी गलतियां सुधारने में लगी हुई है. हालांकि मुश्किल के समय सपा के पास यही विकल्प बचा है. इस बारे में सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि वह एक ऐसा गठबंधन बनाना चाहते हैं, जिससे साम्प्रदायिक ताकतों को हराया जा सके. इसमें लोहियावादी, चरण सिंह वादी और गांधीवादी शामिल हों और ऐसे लोगों को साथ लेकर हम दोबारा सरकार बनाएं. शिवपाल, मुलायम का ही पुराना डायलॉग दोहरा रहे थे. ■

रामगोपाल क्यों गए थे चुनाव आयोग!

पूरे कलह प्रसंग में अखिलेश का साथ देने वाले सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव के चुनाव आयोग पहुंचने से पार्टी के विभाजन के कयास पुख्ता होने लगे हैं. रामगोपाल ने चुनाव आयोग जाने की वजह नहीं बताई है, लेकिन इस बारे में चर्चाओं ने तेज गति पकड़ ली. पार्टी के ही लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी पर आधिकारिक दावे के मसले पर रामगोपाल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बातचीत की. चर्चा के केंद्र में पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह है, जिस पर दावेदारी का मसला संभवतः शीघ्र ही खड़ा होगा. नई पार्टी बनाने और सिंबल साइकिल की जगह मोटर-साइकिल रखने के मसले पर भी विचार हुआ. मोटर-साइकिल युवाओं के आकर्षण की आधुनिक पहचान चिन्ह है. अखिलेश समर्थक तो इस सिम्बल को लेकर नारे भी गढ़ने लगे, शिवपाल नहीं अखिलेश चाहिए, साइकिल नहीं मोटर-साइकिल चाहिए. ■

पार्टी के रसातल में जाने की चिंता नंदा को भी

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा हालांकि पार्टी में मुख्यधारा के नेता नहीं माने जाते और आम तौर पर मीडिया से मुखातिब भी नहीं होते, लेकिन पिछले दिनों लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम-शिवपाल प्रेरित संवाद दोहराने के बावजूद समाजवादी पार्टी की बदहाली का दु:ख उनके चेहरे से झलक रहा था. नंदा कई बार कुछ बेबाकी से बोल भी गए, फिर बात संभाली. उन्होंने जब यह कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही समाजवादी पार्टी का चुनावी चेहरा होंगे तो इससे संबंधित एक सवाल पर बोल गए कि मुख्यमंत्री को टिकट वितरण का अधिकार मिलना ही चाहिए, तभी पार्टी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी. नंदा ने यह भी कहा कि पार्टी से बर्खास्त किए गए युवा नेताओं की वापसी जरूर होनी चाहिए. नंदा बार-बार यह बोल रहे थे कि वे समाजवाद पार्टी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना होगा. चुनाव में युवाओं की जरूरत है, इसलिए उनकी वापसी होनी चाहिए. चुनाव का वक्त है, लिहाजा इस वक्त एकता की सबसे ज्यादा जरूरत है. पार्टी नेतृत्व को इस बारे में जरूर फैसला लेना चाहिए. इस पर एक सपा नेता ने कटाक्ष किया कि नंदा ऐसे ही बोलते रहे तो जल्दी ही वे भी पार्टी से बाहर होंगे. ■

पुरस्कार वापसी का पुरस्कार पार्ट-2

अनंत विजय

चंद दिनों पहले विश्व कविता समारोह के आयोजन के हवाले से पुरस्कार वापसी का पुरस्कार शीर्षक से इस स्तंभ में प्रकाशित लेख पर हिंदी साहित्य जगत में जमकर चर्चा हुई. अशोक वाजपेयी ने विश्व कविता समारोह के आयोजन पर सफाई देते हुए लिखा कि आयोजन का प्रस्ताव वो काफी पहले नीतीश कुमार को दे चुके थे और कमोबेश ये साबित करने में लगे रहे कि पुरस्कार वापसी की मुहिम से विश्व कविता समारोह के आयोजन का कोई लेना-देना नहीं है. अशोक जी देश की ब्यूरोक्रेसी में काफी ऊंचे पद पर रहे हैं, नेताओं के साथ काम करने और राजनीति को बेहद करीब से देखने और समझने का उनको मौका भी मिला है. लिहाजा वो यह बात बेहतर समझते होंगे कि राजनीति में जो दिखता है, दरअसल वो होता नहीं है और कई बार तो राजनीति में दो जमा दो चार भी नहीं होता है. विश्व कविता समारोह तो अब जब होगा तो बातें साफ होंगी लेकिन इस बात से इंकार कोई नहीं कर रहा है कि विश्व कविता समारोह के लिए पहल शुरू हो चुकी है. खुद बिहार के संस्कृति मंत्री ने स्तंभकार से बातचीत में माना है कि अगले साल अप्रैल में इस आयोजन के लिए तैयारी की जा रही है. मंत्री ने तो ये भी कहा कि अशोक वाजपेयी की सलाह को भी आयोजन समिति गंभीरता से ले रही है. आयोजन समिति की बैठक हो चुकी हैं और वाजपेयी जी समेत ज्यादातर सदस्यों ने उसमें हिस्सा भी लिया था. इस बैकग्राउंड को बताने का मकसद ये था कि पुरस्कार वापसी के पुरस्कार की बात हवा में ना होकर तर्कों और तथ्यों के आधार पर की गई थी. अशोक वाजपेयी जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले शुरु हुई असहिष्णुता के मुद्दे को हवा दी थी और लगभग उसकी अगुवाई भी की थी. उस दौर में जिन लेखकों, कलाकारों और पत्रकारों ने असहिष्णुता का मुद्दा उठाकर बिहार चुनाव के वक्त माहौल बनाया था, उनको अब पुरस्कृत करने का उपक्रम शुरू हो चुका है. जब देश में बढ़ती असहिष्णुता के मुद्दे पर लेखक, अभिनेता, कलाकार आदि पुरस्कार वापस कर रहे थे तो उस दौर में अशोक वाजपेयी की अगुवाई में तीन सदस्यों का एक दल राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला था. वाजपेयी के अलावा इस दल के सदस्य थे, मशहूर चित्रकार विवान सुंदरम और पत्रकार ओम थानवी. इन तीनों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर असहिष्णुता के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था. बिहार चुनाव के नतीजों के बाद असहिष्णुता का मुद्दा नेपथ्य में चला गया, पुरस्कार वापसी की मुहिम ठंडी पड़ गई और लेखकों-कलाकारों का विरोध भी लगभग खत्म हो गया. अब वक्त आ गया है, परोक्ष रूप से पुरस्कार वापसी ब्रिगेड के सदस्यों को पुरस्कृत करने का.

बिहार सरकार हर साल कई तरह के पुरस्कार देती है. जिसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर के तो कुछ स्थानीय कलाकारों को दिए जाते हैं. इन पुरस्कारों में पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय चाक्षुष कला पुरस्कार और परफॉर्मिंग आर्ट के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शन कला पुरस्कार दिए जाते हैं. पुरस्कार वापसी से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के लेखकों, कलाकारों को इन पुरस्कारों से नवाजा जा सकता है. अब ये कहना तो मुश्किल है कि पुरस्कार वापसी समूह के कलाकारों का नाम बिहार सरकार को कौन सुझा रहा है, लेकिन ये संयोग नहीं हो सकता है कि एक-एक करके उस समूह के कलाकारों को पुरस्कृत किया जा सकता है. जैसे उदाहरण के तौर पर विवान सुंदरम को बिहार सरकार ने चाक्षुष कला के लिए राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत किया है.

> **लेखकों के बहाने राजनीति करने वालों की पहचान उजागर की जानी चाहिए. जो शख्स ऐलानिया इस या उस पार्टी या दल के साथ रहता है वो जनता को छल नहीं सकता है लेकिन जो शख्स लेखक के वेष में रहकर राजनीति करता हो वो जनता को भ्रमित कर सकता है. जिस तरह से पुरस्कार वापसी की आड़ में राजनीति की बिसात बिछाई गई थी उसने साहित्य का बड़ा नुकसान किया और साहित्यकारों की साख पर बट्टा लगाया. और अब जब एक एक करके उनको पुरस्कृत किया जा रहा है तो बची खुची विश्वसनीयता भी खत्म होती दिखाई दे रही है. भारतीय समाज लेखकों से हर मुद्दे पर तटस्थता की उम्मिद करता है और अपेक्षा ये रहती है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने का सार्वजनिक साहस दिखा सकें.**

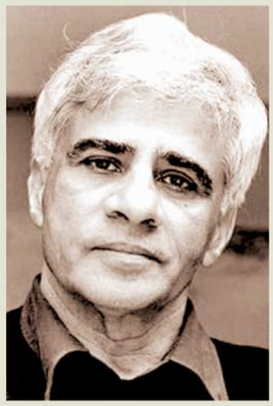

विवान सुंदरम को दिया गया ये पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर का है और उसमें एक लाख की पुरस्कार राशि के अलावा अंगवस्त्रम और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है. वर्ष 2015-16 के लिए विवाद सुंदरम को और वर्ष 2016-17 के लिए हिम्मत शाह को पुरस्कृत किया गया है. विवान सुंदरम इस पुरस्कार के योग्य हैं, बल्कि मेरा तो मानना है कि उनका कद इस लखटकिया पुरस्कार से कहीं बड़ा है, लेकिन सम्मान तो सम्मान होता है. विवान सुंदरम की प्रतिभा या उनके चयन पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है. लेकिन जिस तरह से पुरस्कार वापसी मुहिम से जुड़े लेखकों-कलाकारों को बिहार सराकर उपकृत कर रही है उस पर तो प्रश्नचिन्ह लगता ही है.

बिहार सरकार के इस पुरस्कार के लिए चयन समिति पर गौर करने से स्थिति और साफ हो जाती है. पुरस्कार की चयन समिति में बिहार सरकार के कला और संस्कृति विभाग के सचिव, संस्कृति निदेशक, सहायक निदेशक के अलावा बिहार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष और वरिष्ठ कवि आलोक धन्वा, बिहार ललित कला अकादमी के अध्यक्ष आनंदी प्रसाद बादल के अलावा चित्रकार अनिल बिहारी, नाटक के क्षेत्र से सुमन कुमार और लोकगाथा के करंट लाल नट थे. अब इस समिति के सदस्यों को देखने के बाद तो यही प्रतीत होता है कि इसमें सरकार की चली होगी. विवान सुंदरम और हिम्मत शाह की अशोक वाजपेयी से निकटता जग जाहिर है. पुरस्कार वापसी की मुहिम के वक्त तो विवान सुंदरम फ्रंट फुट पर खेल रहे थे. उस वक्त के उनके बयानों को देखा जा सकता है. तो सवाल वही कि क्या पुरस्कार वापसी की मुहिम से जुड़ने वालों को नीतीश सरकार एक-एक करके पुरस्कृत कर रही है. सवाल तो ये भी उठता है कि क्या पुरस्कार वापसी की मुहिम के पीछे कोई सोची समझी रणनीति थी. उस वक्त और उसके बाद तो यह बताने की कोशिश की गई कि पुरस्कार वापसी की मुहिम स्वत:स्फूर्त थी और एक-एक करके लेखक, कलाकार, फिल्मकार उससे जुड़ते चले गए. लेकिन बाद में विश्लेषण और पुरस्कार वापसी के लिए पुरस्कार दिए जाने की खबरों से ये साफ हो गया कि उस वक्त एक सोची समझी रणनीति के तहत इस मुहिम को हवा दी गई थी, ताकि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके और बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन को फायदा हो सके. हुआ भी वही. दरअसल हिंदी समाज के कई लेखक सत्ता से दूर नहीं रह सकते हैं. केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस तरह के ज्यादातर लेखकों की दुकानदारी बंद हो गई. उनके हाथ से सुविधा आदि तो छिन ही गया, पुरस्कार आदि बांटकर लेखकों को उपकृत करने का अवसर भी चला गया. केंद्र में अपनी दुकानदारी बंद होते देख कुछ लेखकों ने नीतीश कुमार का दामन थामा तो कुछ लेखक दिल्ली में केजरीवाल सरकार के साथ हो लिए. नीतीश कुमार से तो बकायदा कुछ लेखकों ने देशभर के रचनाकर्मियों से उनकी मुलाकातें और बैठक आदि करवाने का ठेका भी लिया है. केजरीवाल से भी कई लेखकों को उम्मीदें हैं, लेकिन वहां मैत्रेयी पुष्पा के आ जाने से कइयों की दाल नहीं गल पा रही है और वो बेचैनी से कभी कुमार विश्वास का दामन थामना चाहते हैं तो कभी कुछ और योजना बनाने में जुट जाते हैं. सवाल वही कि क्या इस तरह के कृत्यों से लेखकों की समाज में इज्जत या तटस्थता बनी रह सकती है. लेखकों के बहाने राजनीति करने वालों की पहचान उजागर की जानी चाहिए. जो शख्स ऐलानिया इस या उस पार्टी या दल के साथ रहता है वो जनता को छल नहीं सकता है. लेकिन जो शख्स लेखक के वेष में रहकर राजनीति करता हो वो जनता को भ्रमित कर सकता है. जिस तरह से पुरस्कार वापसी की आड़ में राजनीति की बिसात बिछाई गई थी, उसने साहित्य का बड़ा नुकसान किया और साहित्यकारों की साख पर बट्टा लगाया. और अब जब एक-एक करके उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, तो बची-खुची विश्वसनीयता भी खत्म होती दिखाई दे रही है. भारतीय समाज लेखकों से हर मुद्दे पर तटस्थता की उम्मीद करता है और अपेक्षा ये रहती है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने का सार्वजनिक साहस दिखा सकें. लेकिन इन दिनों जो हो रहा है उसपर नजर डालने से साफ होता है कि हमारे समाज के लेखक तटस्थ नहीं रह गए हैं. लेखकीय तटस्थता को सबसे पहले खत्म किया कम्युनिस्टों ने, जब उन्होंने अपनी विचारधारा के लेखकों को पार्टी का वर्कर और सिद्धांतों का प्रचारक बनाया. कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन होते गए और हमारे लेखक भी आज्ञाकारी कार्यकर्ता की तरह विभाजित होते चले गए. कम्युनिस्टों के विरोध में बने लेखकों के संगठन भी इस या उस पार्टी के ध्वजवाहक बनकर अपने को साबित करने में लगे रहे, चाहे वो परिमल हो या कोई और संगठन. समाज के मुद्दों पर हमारे लेखक अपनी पार्टी का मुंह जोहने लगे और पार्टी के स्टैंड को ही लेखकीय स्टैंड की तरह पेश करने लगे. बताते हैं कि इमरजेंसी के समर्थन के प्रस्ताव के लिए भीष्म साहनी तैयार नहीं थे लेकिन अनुशासित पार्टी वर्कर होने की वजह से उनको प्रस्ताव पास करवाना पड़ा. इस समस्या के बारे में हिंदी समाज को विशेष रूप से विचार करना होगा. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कनेर

परिचय

कनेर के पौधे भारतवर्ष में मंदिरों, उद्यानों और गृहवाटिकाओं में फूलों के लिए लगाए जाते हैं. इसकी दो प्रजातियां पायी जाती है, श्वेत और पीली कनेर. इस पर वर्ष-पर्यन्तफूल आता है. श्वेत और पीली कनेर जहां सात्विक भाव जगाती है, वहीं लाल (गुलाबी) कनेर को देखकर ऐसा भ्रम होता है कि जैसे यह बसंत और सावन का मिलन तो नहीं. छीली कनेर का उल्लेख चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता है. कहा जाता है कि यह अमेरिका से भारत आया. पीत कनेर की श्वेत, पीत आदि पुष्पों के आधार पर कई प्रजातियां पायी जाती है. परन्तु इन सभी प्रजातियों का एक ही वानस्पतिक नाम है. श्वेत कुष्ठ की चिकित्सा के लिए सफेद पुष्प वाले कनेर का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है. मध्यकालीन निघंटुओं में जैसे-राजनिघंटु में इसका संक्षिप्त वर्णन प्राप्त होता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

- **शिरो रोग** : कनेर के पुष्प तथा आंवले को कांजी में पीसकर मस्तक पर लेप करने से शिर शूल का शमन होता है.
- सफेद कनेर के पीले पत्तों को सुखाकर और महीन पीसकर जिस ओर पीड़ा हो उसी ओर के नासिकाछिद्र में एक दो बार सुंघाने से छींके आकर सिर दर्द में लाभ होता है.
- करवीर तथा दुग्धिका को कूटकर, दुग्ध से मिश्रित कर सिर पर लेप करने से बालों का असमय सफेद होने में लाभ होता है.
- **नेत्र रोग-** पीले कनेर की जड़ को सौंफ और करंज के रस के साथ पीसकर आंख में लगाने से नजला, पलकों का मोटापन, जाला, फूली इत्यादि नेत्र रोगों में आराम होता है.
- **मुख रोग-** सफेद कनेर की डाली से दातुन करने से हिलते हुए दांत मजबूत होते हैं ओर दंतशूल का शमन होता है.
- **हृदय शूल-** 100-200 मिग्रा कनेर कूल की छाल को भोजन के पश्चात् सेवन करने से हृदय वेदना का शमन होता है.

- कनेर के 50 ग्राम ताजे फूलों को 100 मिली मीठे तेल में पीसकर एक हफ्ते तक रख दें. फिर 200 मिली जैतून के तेल में मिलाकर कुष्ठ, सफेद दाग, पीठ का दर्द बदन दर्द दूर करने के लिए दो से तीन बार नियमित मालिश करें.
- **जोड़ों की पीड़ा-** कनेर के पत्तों को पीसकर तेल में मिलाकर लेप करने से जोड़ों की पीड़ा का शमन होता है.
- **त्वचा रोग-** सफेद कनेर की मूल छाल को तेल में पकाकर, छानकर लगाने दाद और कुष्ठ में लाभ होता है.
- **चर्मरोग-** सफेद कनेर की मूल क्वाथ को राई के तेल में उबालकर लगाने से त्वचा रोगों का शमन होता है.
- **खुजली-** कनेर के पत्तों से पकाए हुए तेल को लगाने से खुजली मिटती है.
- **कुष्ठ-** सफेद कनेर की जड़, कुटजफल, करंज के फल, दारुहल्दी की छाल और चमेली की नयी पत्तियों को पीसकर लेप करने से कुष्ठ में लाभ होता है.
- कनेर के पत्तों का क्वाथ बनाकर नियमित रूप से कुछ समय तक स्नान करने से कुष्ठ रोग में बहुत लाभ होता है.
- **उबटन-** सफेद कनेर के फूलों को पीसकर चेहरे पर मलने से चेहरे की कान्ति बढ़ती है.
- 50 मिग्रा कनेर की जड़ के महीन चूर्ण को दूध के साथ कुछ हफ्ते तक दिन में दो बार खिलाते रहने से अफीम की आदत छूट जाती है.
- **सर्पदंश-** सर्पदंश में 125 से 250 मिग्रा की मात्रा में या 1-2 करवीर के पत्र थोड़े-थोड़े अंतर पर देते हैं, जिसके कारण वमन होकर विष उतर जाता है.

प्रयोज्यांग: *मूल, मूल की छाल, पत्र तथा आक्षीर.*

मात्रा: *चूर्ण 30-125 मिग्रा अथवा चिकित्सक के परामर्शानुसार.*

- **विषाक्तता:** तीव्र विषाक्त होने के कारण इसका प्रयोग कम मात्रा में चिकित्सकीय परामर्शानुसार करना चाहिए. अत्यधिक मात्रा में इसके प्रयोग से उल्टी, पेट दर्द, बेचैनी, अतिसार, रक्तभाराल्पता, अवसाद तथा हृदयावरोध उत्पन्न होता है.
- इसके बीज अत्यंत विषाक्त होते हैं.

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

भौतिक शक्तियां चेतना का नियंत्रण नहीं कर सकती हैं.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

धार्मिक मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति ईश्वर-प्राप्ति करना चाहता है. इस ईश्वर को 'आत्म साक्षात्कार' भी कहा जाता है, यह इसलिए कि आत्मा और परमात्मा को एक ही तत्व मानते हैं. इसका अर्थ यह है कि अपनी आत्मा या अपने आत्मा-रूपी उस दिव्य चेतन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना. एक प्राणी के अंदर आत्मा छुपी रहती है तथा उसी छुपी आत्मा के कारण वह जीवंत है और जीवंत होने के कारण प्रकटित रूप से विभिन्न कर्मों में लिप्त है. पर आत्मा हर परिस्थिति में और स्थिति विशेष में परमात्मा के साथ अविच्छिन्न रूप से रहती है. अत: ईश्वर का साक्षात्कार आत्मा को उसकी भौतिक अभिव्यक्ति के रूप में समझना नहीं है, जिसमें कि सभी चेतन एवं जड़, दृश्यमान एवं अदृश्यमान तथा ब्रह्मांड में कार्य कर रही शक्तियां भी सम्मिलित हैं. चाहे कोई आकाश में सभी ब्रह्मांडों का भ्रमण कर ले और उनके विषय में ज्ञान प्राप्त कर ले, तो भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे ईश्वरीय साक्षात्कार हो गया है.

पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में दिखाई देने वाली इस चेतना की अभिव्यक्ति आत्मा या परमात्मा से उद्भूत हुई है. संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकट होने वाली ऊर्जा-शक्ति के सभी रूप चेतना से प्रकटित हैं और सभी प्रकार के भौतिक पदार्थ उन ऊर्जा शक्तियों से उत्पन्न होते हैं. इस प्रकार चेतना, ऊर्जा-शक्ति के सभी रूपों एवं भौतिक पदार्थों से श्रेष्ठतर है. चेतना को उर्जा के सभी रूपों एवं भौतिक पदार्थों का ज्ञान है और यह उनका नियंत्रण कर सकती है, जबकि विपरीत रूप में ऐसा होना संभव नहीं है. इसका तात्पर्य यह है कि भौतिक शक्तियां चेतना का नियंत्रण नहीं कर सकती हैं. अत: यह यथार्थ नहीं है कि मूर्तियों (जो कि दैवी शक्तियों का प्रतीक हैं,) की पूजा करने से व्यक्ति निश्चयमेव आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हो. आध्यात्मिक विज्ञान में किसी प्रयास का अर्थ अपनी सीमित चेतना का विस्तार कर उसे परम चेतना की स्थिति में पहुंचाना है. वह विज्ञान जिसके द्वारा चेतना का विकास होता है, उसे आध्यात्मिक विज्ञान कहते हैं. इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति निरंतर अपनी विचारधारा एवं आचरण का निरंतर विश्लेषण तथा अनुसंधान करने का प्रयास करता रहे. अपने अंत:करण को शुद्ध करने के प्रारंभिक प्रयास में मूर्ति-पूजा, मंत्र-जाप, धार्मिक अनुष्ठान आदि का विधान किया गया है. एक बार जब इंद्रियों पर नियंत्रण के द्वारा

अंत:करण शुद्ध हो जाता है, तो धीरे-धीरे चेतना का भी विस्तार होने लगता है. आध्यात्मिक विज्ञान के इस जगत में प्रवेश करने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है.

'श्री साईं सच्चरित्र' का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि श्री साईं बाबा इस विश्वातीत चेतना के एक शरीरधारी मानवीय प्रतीक थे. अगर हम आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं तो हमें गंभीरता से उनकी शिक्षाओं एवं व्यवहार के मर्म को समझते हुए आचरण करना चाहिए. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

भारत बना कबड्डी का सरताज

सैयद मोहम्मद अब्बास

विश्व खेल जगत में भारतीय खिलाड़ी अमिट छाप छोड़ रहे हैं. चाहे वह क्रिकेट हो या फिर टेनिस लगभग सभी खेलों में अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं. क्रिकेट में भारत का डंका बजता है. अभी हाल में ही भारतीय टेस्ट टीम ने नम्बर वन का खिताब अपने नाम किया तो दूसरी ओर भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई चैम्पियन्स ट्रॉफी में पाकिस्तान को धूल चटा कर विश्व खेल पटल पर अपनी धाक जमायी है. अन्य खेलों की बात की जाये तो कबड्डी जैसे खेल में भी भारत अब अव्वल साबित हो रहा है. कबड्डी विश्व कप में भारत ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है. भारतीय टीम ने इरान को खिताबी जंग में कड़ी टक्कर देते हुए 38-29 के अंतर से पराजित किया और भारत विश्व कबड्डी का सरताज बन गया है. इस जीत के साथ भारत ने लगातार तीन बार विश्व कबड्डी का खिताब जीतने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया है. भारत में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कबड्डी जैसे खेल में यह गौरव प्राप्त करना बड़ी बात है. भारतीय टीम की बात की जाये तो इससे पूर्व इरान को 2004 और 2009 में करारी शिकस्त देते हुए चैम्पियन बनने का गौरव प्राप्त किया था.

भारतीय खेल इतिहास में इसे एक सुनहरी कामयाबी माना जायेगा. विश्व कप कबड्डी में भारत के सफर पर गौर किया जाये तो शुरूआती मैचों के बाद टीम ने बेहद शानदार खेल का प्रदर्शन किया. देश में अक्सर क्रिकेट को लोग तव्वजो देते हैं, लेकिन अन्य खेलों की जीत को सुर्खियों में जगह नहीं मिलती है. इतना ही नहीं मीडिया भी ऐसे खेलों में मिली जीत को दिखाने के लिए आगे नहीं आता हैं. खैर यह बात कोई नई नहीं है. बात अगर कबड्डी विश्व कप की की जाये तो इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया है. इनमें सबसे आगे रहे भारत के अजय ठाकुर. अजय ने पूरी प्रतियोगिता में बेहद जानदार प्रदर्शन करते हुए 64 अंक जुटाते हुए टॉप रेडर बनने का तमगा हासिल किया. अजय ने खिताबी जंग में भी इरान की टीम को बौना साबित कर दिया. उसने इस फाइनल मुकाबले में 12 अंक हासिल किये जो खिताब के लिए सबसे अहम माना जा सकता है. दूसरी ओर थाईलैंड के थामसन ने 56 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. भारतीय टीम को पहले मुकाबले में कड़ा संघर्ष करने के बावजूद कोरिया से हार झेलनी पड़ी थी. इस मुकाबले में भी भारतीय खिलाड़ी छाये हुए थे. इस मुकाबले में अजय और नारवाल ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया था, लेकिन भारतीय टीम कोरिया से आगे नहीं निकल सकी. इसके बाद दूसरे मुकाबले में कंगारू को 56-20 के अंतर से चित कर अपनी दावेदारी को मजबूती दी. इस मैच में एक बार फिर अजय और नारवाल ने भारत की जीत में अहम रोल अदा किया. अजय ने सात और नारवाल ने पांच रेड अंक हासिल कर भारत की जीत पक्की कर दी. भारत

की अगली चुनौती बांग्लादेश से थी. भारत ने बांग्लादेश के खिलाड़ियों को सबक सिखाते हुए 57-20 से पटखनी दी और खिताब की ओर कदम बढ़ा दिया. यह जीत इसलिए भी अहम थी कि क्योंकि बांग्लादेश में कबड्डी को नेशनल गेम का दर्जा मिला हुआ है. इसके बाद भारतीय टीम ने अपनी तेज चपलता की बदौलत इंग्लैंड का शिकार करते हुए 74-20 के अंतर से उसे हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया. इस तरह से भारतीय टीम खिताब से दो कदम दूर थी. भारतीय टीम ने थाईलैंड को सेमीफाइनल में 73-20 के भारी अंतर से धूल चटाते हुए फाइनल का रास्ता तय कर लिया. इरान के साथ फाइनल मुकाबले से पहले टीम पर दबाव था, लेकिन खिताबी जंग में खिलाड़ियों ने लय बनाये रखी और कबड्डी विश्व कप का सरताज बनने का सपना पूरा कर लिया. फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की राह आसान नहीं लग रही थी क्योंकि इरान की टीम ने भी कमर कस रखी थी. पहले हाफ में आलम यह था कि भारतीय खिलाड़ी इरान की रक्षापंक्ति को भेदने में नाकाम दिखायी पड़ रहे थे. पहले हॉफ में भारत का डिफेंस भी कमजोर दिखा इसके चलते वह पहले हाफ में 19-15 से पिछड़ गया था लेकिन दूसरे हाफ में यह कहानी बदल गई.

इरान को अब भारतीय खिलाड़ी छोड़ने के मूड में नहीं थे. दूसरे हॉफ में अजय ठाकुर ने इरानी खिलाड़ियों को खूब छकाया और अपनी रेड की बदौलत इरानी कप्तान को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके बाद तो भारतीय खिलाड़ियों को पकड़ना इरान के बस में नहीं दिख रहा था.कबड्डी जैसे खेल को सुर्खियां तब मिली जब प्रो कबड्डी जैसी प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया जाने लगा. क्रिकेट की तरह यह खेल भी दुधिया रौशनी में खेले जाने लगा. इस खेल में चपलता बेहद अहम मानी जाती है. यह बात भी कटु सत्य है कि भारत की इस जीत को उतनी सुर्खियां नहीं मिलती है, जितनी क्रिकेट को मिलती है. देश में क्रिकेट का बुखार देखा जा सकता है. अन्य खेलों में बेहतर परिणाम न मिलने से लोग अब क्रिकेट जैसे खेलों को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं. कबड्डी में भले ही कोई सचिन तेंदुलकर अथवा विराट कोहली जैसा खिलाड़ी न हो, लेकिन भारत की इस जीत में कई खिलाड़ियों का अहम योगदान है. अजय ठाकुर उनमें से एक हैं, जो अब कबड्डी के खेल में भारत के विराट कोहली से कम नहीं है. उन्होंने अपने धासू खेल से यह सुर्खियां बटोरी है. वहीं भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अनूप कुमार की भी खूब वाहवाही हो रही है. कबड्डी में ऑलराउंडर माने जाने वाले अनूप कुमार की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशियाई खेलों में दो बार स्वर्ण पदक हासिल किया है. भारत ने साल 2010 और 2014 के एशियाई खेलों का गोल्ड अपने नाम किया. उनके शानदार खेल के लिए सरकार ने 2012 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया था. भारतीय टीम के कप्तान अनूप कुमार ने विश्व कप जीतने के बाद संन्यास की बात कही है. यह बेहद सुखद पल है कि उनकी कप्तानी में भारत ने विश्व कप अपने नाम किया है. कुल मिलाकर यह बेहद अच्छी खबर है कि अन्य खेलों में भारतीय खिलाड़ी तिरंगा बुलंद कर रहे हैं. ■

लोढ़ा कमेटी की सिफ़ारिशों से सकते में आया बीसीसीआई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी पैसा कमाने की मशीन, बीसीसीआई की हनक से दुनिया के कई बोर्ड डरते हैं. दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई अपनी ताकत और रूतबों के लिए जाना जाता है. वह जो भी चाहता है उसे आईसीसी को मानना पड़ताहै.हाल के दिनों में भारतीय क्रिकेट में कई बदलाव देखने को मिले लेकिन बीसीसीआई अपनी मर्जी का मालिक है. वह अपने हिसाब से कायदे कानून बनाता है, इतना ही नहीं उसकी कार्यप्रणाली पर कोई सवाल खड़ा हो, तो वह भी अपनी ताकत से उसे दबाने की कूवत रखता है. अभी कुछ साल पहले आईपीएल में फिक्सिंग के गंदे खेल का सच सामने आया था, जिसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मच गया था, लेकिन बोर्ड ने इस मामले को भी बड़ी खूबसुरती से निपटा दिया. दरअसल बोर्ड ने अपने अधिकारियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी की जोर भी लगा दिया था. खैर यह बात तो अब पुरानी हो चुकी, लेकिन अब नये मामले से उसकी राह आसान नहीं दिख रही है, यानी लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों से उसकी बोलती बंद हो गई है. हालांकि बोर्ड इस मामले से बचने की फिराक में दिख रहा है. लोढ़ा समिति का ताजा मामला बोर्ड के लिए अब गले की हड्डी बन गया है. मामला कोर्ट में चल रहा है. लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है. बीसीसीआई के द्वारा रिव्यू पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद बीसीसीआई का पूरा कुनबा सकते में आ गया है. इतना ही नहीं अनुराग ठाकुर की कुर्सी भी दांव पर लग गई. दरअसल बीसीसीआई शुरू से इस मामले को लेकर ढुल-मुल रवैया अपनाता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई बीसीसीआई की पुनर्विचार याचिका के खारिज होने का मतलब है कि बोर्ड को अब जस्टिस लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को पूर्ण रूप से लागू करना पड़ेगा. जिसके बाद यह तय है कि बीसीसीआई में भारी बदलाव देखने को मिल सकता है. खबरों की माने तो सुप्रीम कोर्ट लगातार बीसीसीआई पर शिकंजा कसता दिख रहा है. इस बीच कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने बोर्ड को राज्य संघो से मिलने वाली मदद पर भी रोक लगा दी है. स्वतंत्र ऑडिटर की नियुक्ति पर कोर्ट ने बोला है कि ऑडिटर बीसीसीआई को होने वाली आय तथा उसके खर्चों की समीक्षा करेगा, साथ ही ऑडिट भी करेगा. कोर्ट ने आगे कहा है कि कोई अनुबंध जारी करने के लिए लोढ़ा समिति से पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी. सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी की वजह आईसीसी के सीईओ डेविड रिचर्डसन के बयान पर अनुराग ठाकुर और रत्नाकर शेट्टी द्वारा दायर अलग-अलग हलफनामे भी हैं. रिचर्डसन ने बयान में कहा था ठाकुर ने आईसीसी अध्यक्ष से मौखिक अनुरोध कर ऐसा पत्र लिखने को कहा था, जिसमें इस बात का जिक्र हो कि सीएजी की नियुक्ति से बोर्ड के काम में दखलअंदाजी बढ़ जाएगी.

बीसीसीआई की दौलत पर नजर गड़ाई जाये तो इतना साफ है कि उसके पास इतना पैसा है, जो अन्य खेलों में नहीं दिखेगा. इतिहास पर गौर किया जाये तो बीसीसीआई पहली बार 1928 में सामने आया था. शुरुआती दौर में भले ही बोर्ड काफी छोटा हो लेकिन बाद के दौर में लगातार कामयाबी की नई सीढ़ियों पर चढ़ता दिखा है. मौजूदा समय में उसकी आमदनी 1967 करोड़ रुपए आंकी जा रही है. बोर्ड के पैसों के आगे अन्य बोर्ड बौने साबित हो रहे हैं. इसी के चलते वह विश्व क्रिकेट पर राज करता है. बीसीसीआई अपने हिसाब से चलने का आदी है.

आईसीसी की दखलअंदाजी बीसीसीआई को बर्दाश्त नहीं है. इतना ही नही यह डीआरएस यानी अंपायर निर्णय समीक्षा प्रणाली को भी मानने से इंकार करता आया है. लेकिन दबाव बढ़ने पर उसने अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में इसे लागू करने की बात कही है.

अभी कुछ साल पहले आईपीएल में मैच फिक्सिंग को लेकर कई बड़े खुलासे हुए थे. इस मामले में बीसीसीआई के कई बड़े आधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई थी, लेकिन बोर्ड ने इससे किनारा करने में देर नहीं की. हालांकि इस मामले में उसने अपने कई अधिकारियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था. साल 2013 में आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के तीन खिलाड़ियों को स्पॉट फिक्सिंग में शामिल होने की बात सामने आयी थी. इस मामले में यह भी खुलासा हुआ कि स्पॉट फिक्सिंग का खेल आईपीएल में चरम पर था. श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी. इसके बाद जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी ने बीसीसीआई को आड़े हाथों लिया था. फिक्सिंग के इस खेल में बीसीसीआई की खूब किरकिरी हुई थी, अब लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करने में आना कानी करने वाला बोर्ड बेहद मुश्किल भरे दौर से गुजर रहा है. उसे डर है कि उसकी सत्ता पूरी तरह से चरमरा जायेगी. पैसों के इस खेल में अब सेंध लगना तय माना जा रहा है. दरअसल लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों से बोर्ड इतना घबरा गया है कि वह इस मामले में आईसीसी से सोच विचार करने में लगा हुआ है, बीसीसीआई शुरू से लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ रहा है, लेकिन उसे हर बार इस मामले में मुंह की खानी पडी है. लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों में बीसीसीआई के कई अधिकारियों की कुर्सी जाना भी तय माना जा रहा है, जो कल तक बीसीसीआई के पैसों पर मौज करते थे. उनको इस बार बेदखल होने का डर सता रहा है. लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर गौर किया जाये तो बीसीसीआई इस बार क्लीन बोर्ड होता हुआ दिख रहा है. लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के अनुसार बीसीसीआई के कुनबे में मंत्री और अधिकारियों को शामिल नहीं किया जायेगा, इतना ही नहीं लोढ़ा समिति ने आयु को लेकर कई बड़े फैसले किये हैं, समिति की सिफारिशों में करीब 16 बिंदु को लेकर चर्चा की गई है. इसमें कुछ बिंदु पर तो बीसीसीआई की सहमती बनती दिखी है लेकिन कुछ मामलों में बोर्ड ने मानने से साफ इंनकार कर दिया है. लोढ़ा समिति की सिफारिशों में खास बात यह है कि इसमें एक आदमी एक पद का नियम बीसीसीआई होने की बात कही गई. सट्टेबाजी को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है सट्टेबाजी को देश में कानूनी बनाया जाये. चयन समिति में पूर्व अंतराष्ट्रीय खिलाड़ियों को मौका दिया जाये साथ ही चयन समिति का मुखिया सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाला हो. समिति की सिफारिशों में बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाने की बात कही गई है इसके आलावा बीसीसीआई में कई अहम बदलाव की मांग की गई है.

सवाल यह है कि बीसीसीआई आखिर क्यों लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मानने से बचना चाहता है. दरअसल यहां सारा खेल पैसों को लेकर है जो अधिकारी बीसीसीआई में अरसे से जमे हुए हैं और इसकी बदौलत अपनी जेबों को भरने में लगे रहते थे. उनको अब बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, बोर्ड के अधिकारी अपने निजी फायदे के लिए अपनी दुकान चलाते है, उन पर ताला लग जाने का खतरा है. बोर्ड के कई लोग राजनीतिक दलों की पार्टी से भी जुड़े रहते हैं, बोर्ड के अधिकारियों के अपने राज्य संघो में गहरी पैठ दिखती है. कुल मिलाकर देखा जाये तो लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लेकर बीसीसीआई अब चारों ओर से घिरता दिख रहा है. कोर्ट ने बेहद कड़ा रूख अपनाया हुआ है, अब देखना होगा कि बीसीसीआई कैसे लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

ख़ूबसूरती में ऐश्वर्या राय जैसा कोई नहीं : अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा का कहना है कि वह ऐ दिल है मुश्किल में काम करने के दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन की शख्सियत और ख़ूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गई थी. करण जौहर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर की भी अहम भूमिका है. अनुष्का ने कहा मेरा इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ एक सीन है लेकिन यह काफी प्रभावी है. वह काफी सुंदर हैं और उनके पास ढेर सारी उपलब्धियां हैं. अनुष्का ने कहा, ऐश्वर्या काफी प्रेरणादायक हैं. मेरे लिए उनके साथ फिल्म में साथ काम करना एक बेहतरीन अहसास है. मैं उनकी सुंदरता और शख्सियत से काफी मंत्रमुग्ध हो गई थी. करण ने आदित्य चोपड़ा को रब ने बना दी जोड़ी में अनुष्का को शामिल न करने के लिए कहा था और अनुष्का का कहना है करण के साथ काम करना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है.■

बायोपिक पर सर्वाधिक कमाई के मामले में

धोनी नंबर वन

भारतीय क्रिकेट इतिहास के सफलतम कप्तानों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर बनी फिल्म *एम.एस धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी* ने 30 सितंबर को रिलीज होने के बाद अब तक लगभग 130 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसी के साथ धोनी कमाई के मामले में भी साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है. एम.एस.धोनी ने कमाई के मामले में अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट, हाउसफुल-3 और रूस्तम को भी पीछे छोड़ दिया है. जबकि सलमान खान की फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान 300 करोड़ रुपए की कमाई के मामले में नंबर एक पर कायम है. फिल्म के निर्माताओं का दावा है कि यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बायोपिक है.

फॉक्स स्टार स्टूडियोज और अरुण पांडे के इंस्पायर्ड इंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्देशन नीरज पांडे ने किया है. इस फिल्म में धोनी के रांची की सड़कों से भारत के सफलतम कप्तान बनने तक के सफर को बहुत अच्छी तरह से बयां किया गया है. फॉक्स स्टार स्टूडियो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह ने एक बयान में कहा, एम.एस.धोनी- द अनटोल्ड स्टोरी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई (भारतीय सिनेमा में) करने वाली बायोपिक बन गई है. इस बात से पता चलता है कि लोगों में माही (धोनी) के प्रति कितना प्यार है और उन्होंने किस तरह इस फिल्म को अपनाया और प्रचारित किया. उन्होंने कहा, हम उनके प्रशंसकों, क्रिकेट प्रेमियों और फिल्म पसंद करने वालों से मिल रहे उत्साह से काफी खुश हैं.■

सुपरस्टार्स के फ्लॉप किड्स

प्रवीण कुमार

feedback@chauthiduniya.com

बॉलीवुड ने हमें एक से बढ़कर एक सुपरस्टार दिए हैं. अभिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, राज कपूर, राज कुमार, दिलीप कुमार, धर्मेन्द्र, अनिल कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर सहित अनेक स्टार बीते जमाने की शान रह चुके हैं. जिन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी है. इनमें से कुछ सितारें जहां अब इस दुनिया में नहीं रहे तो कुछ अब भी बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाए हुए हैं. लेकिन बात जब सुपरस्टार किड्स की जाए तो ये किड्स अपने स्टारडम का फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाएं. देखा जाए तो बॉलीवुड में सुपरस्टार्स किड्स लगभग सुपरफ्लॉप साबित हुए हैं. बॉलीवुड में फ्लॉप किड्स की कमी नहीं है. ईशा देओल, तनीशा मुखर्जी, फरदीन खान, उदय चोपड़ा, तुषार कपूर, सोहा अली खान, सुमन अध्यन, अभिषेक बच्चन आदि सितारे ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई ना कोई स्टार या सुपरस्टार रहा है पर इनके बच्चे फिल्मों में सुपरफ्लॉप रहें है.

हाल ही में इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया, हर्षवर्धन कपूर! जिन्होंने फिल्म *मिर्जिया* से डेब्यू किया है.

अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर ने फिल्म *मिर्जिया* से काफी धमाकेदार पारी शुरु करने की सोची थी. लेकिन अफसोस फिल्म ना दर्शकों को पसंद आई, ना ही बॉक्स ऑफिस पर कोई धमाका कर पाई. खैर, सिर्फ हर्षवर्धन कपूर ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड में और भी कई सुपरस्टार किड्स हैं, जिनकी धमाकेदार डेब्यू की उम्मीद की गई थी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उन्हें पहली हार से ही सामना करना पड़ा. अब यह तो समय ही बताएगा कि आगे चलकर हर्षवर्धन कपूर हिट होते है या फ्लॉप?■

अक्षय का 30 दिन में 100 करोड़ का दांव

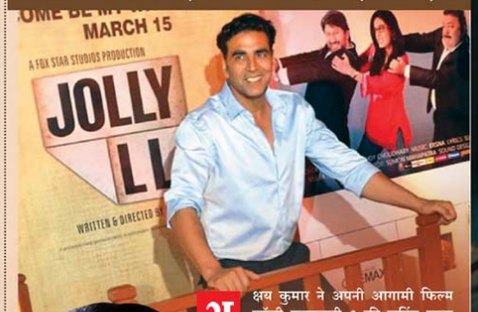

अक्षय कुमार ने अपनी आगामी फिल्म जॉली एलएलबी 2 की शूटिंग ख़त्म कर ली है वह भी मात्र 30 दिनों में. जी हां, कोई शक नहीं कि अक्षय कुमार एक साल में तीन-चार फिल्में दे देते हैं. बहरहाल, 30 दिनों में शूटिंग ख़त्म करना भी कोई छोटी बात नहीं. अक्षय कुमार ने इस बात के लिए फिल्म के निर्देशक को क्रेडिट दिया है. उन्होंने कहा कि, सुभाष कपूर ने स्क्रिप्ट पर इतने अच्छे से काम किया था कि फिल्म बिल्कुल शेड्यूल पर ख़त्म हो पाई. अब अक्षय अपनी अगली फिल्म *टॉयलेट एक प्रेम कथा* की शूटिंग शुरु करेंगे, जबकि जनवरी अंत से नीरज पांडे की क्रैक की.■

क्या है काजोल की ख़ूबसूरती का राज़?

"काजोल जीरो फिगर पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वे अपने वजन को इतना भी नहीं बढ़ने देती कि वह बोझ लगे. इसलिए वे डाइट का ध्यान रखने के साथ-साथ प्रतिदिन करीब डेढ़ घंटा एक्ससाइज करती हैं."

शादी के इतने सालों बाद और दो बच्चों की मां होने के बाद भी अभिनेत्री काजोल आज भी खूबसूरत नज़र आती हैं. उनके फिट रहने और खूबसूरत त्वचा का राज काजोल का हमेशा हंसते रहना और नियमित एक्ससाइज करना है. आइए जानते हैं काजोल ब्यूटी टिप्स

काजोल कभी भी डार्क मैकअप नहीं करती. उन्हें पर्दे पर और बिना पर्दे के हमेशा सामान्य और हल्के मेकअप में ही देखा जाता है. इसके पीछे उनका मानना है कि हाई मैकअप से चेहरे की अंदरूनी चमक खो जाती है.

काजोल की आंखें बहुत सुंदर है. उनकी आंखों का रंग और शेप काफी अलग है. वह अपनी आंखों पर डार्क शेड के काजल को लगाती है ताकि उनकी आंखें चेहरे पर लाउड लगें.

काजोल जीरो फिगर पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वे अपने वजन को इतना भी नहीं बढ़ने देती कि वह बोझ लगे. इसलिए वे डाइट का ध्यान रखने के साथ-साथ प्रतिदिन करीब डेढ़ घंटा एक्ससाइज करती हैं.

काजोल सोने में कोई कोताही नहीं बरतती. उनका मानना है कि सुंदर दिखना है तो नींद लेना बहुत जरूरी है. दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद लें. इससे आपका शारीरिक रूप के अलावा मानसिक रूप से भी फिट रहते हैं. काजोल पानी पीने पर विशेष ध्यान देती हैं. वे कहती हैं कि पानी पीने से शरीर हाईड्रेट रहता है और त्वचा ग्लो करती है.■

फ्लैश बैक

यश चोपड़ा

पर्दे पर रोमांस को दिए नए मायने

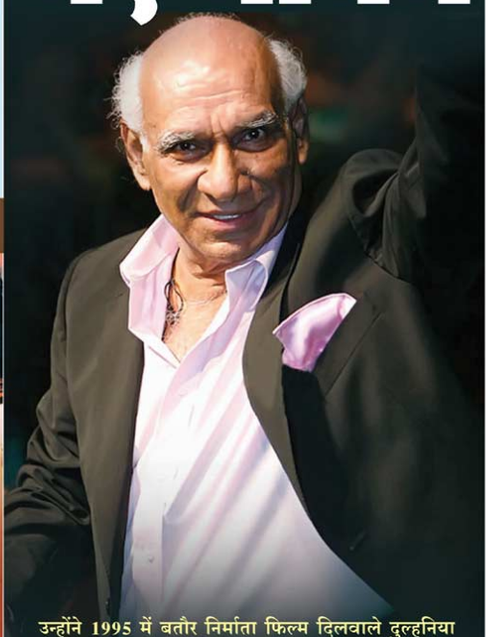

उन्होंने 1995 में बतौर निर्माता फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में दांव लगाया. शाहरुख और काजोल के अभिनय से सजी यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म मानी जाती है. इसके बाद 1997 में उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है का निर्देशन किया.

यश चोपड़ा को हिन्दी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है. दीवार, कभी कभी, डर, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है, वीर-जारा जैसी अनेकों बेहतरीन और रोमांटिक फिल्में बनाने वाले यश चोपड़ा ने पर्दे पर रोमांस और प्यार को नए मायने दिए हैं.

यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर, 1932 को लाहौर में हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है. आजादी के बाद वह भारत आ गए. उनके बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा बॉलीवुड के जाने-माने निर्माता निर्देशक थे. बड़े भाई की प्रेरणा पर ही उन्होंने भी फिल्मों में हाथ आजमाया और आज यश चोपड़ा का परिवार बॉलीवुड के प्रतिष्ठित बैनरों में से एक है. उनके बेटे आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा भी फिल्मों से ही जुड़े हुए हैं. यश चोपड़ा ने अपने भाई के साथ सह निर्देशक के तौर पर काम करना शुरू किया. अपने भाई बी.आर चोपड़ा के बैनर तले उन्होंने लगातार पांच फिल्में निर्देशित की.

हालांकि 80 के दशक की शुरूआत में यश चोपड़ा को असफलता का कड़वा स्वाद भी चखना पड़ा पर 1989 में आई चांदनी ने उन्हें दुबारा एक सफल और हिट निर्देशक बना डाला. 1991 में आई वो लम्हे भी इसी दौर की एक सुपरहिट फिल्म थी. इसके बाद उन्होंने 1995 में बतौर निर्माता फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में दांव लगाया. शाहरुख और काजोल के अभिनय से सजी यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म मानी जाती है. इसके बाद 1997 में उन्होंने फिल्म दिल तो पागल है का निर्देशन किया. कुछ सालों तक वह निर्देशन से दूर रहे और फिर लौटे 2004 की सुपरहिट फिल्म वीर-जारा को लेकर. इस फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया. फिल्म में प्यार की परिभाषा की ऐसी व्याख्या की गई कि यश चोपड़ा को लोगों ने सही अर्थों में किंग ऑफ रोमांस कहना शुरू कर दिया. फिल्म निर्माता यश चोपड़ा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च ऑफिसियर डी ला लेजन पुरस्कार प्रदान किया गया. स्विस सरकार ने उन्हें स्विस एंबेसडरस अवार्ड 2010 से सम्मानित किया है. अपनी मृत्यु से लगभग एक माह पूर्व अपने जन्मदिन के दिन शाहरुख खान को दिए एक इंटरव्यू में यश चोपड़ा ने कहा था कि जब तक है जान उनके द्वारा निर्देशित अंतिम फिल्म होगी. इसके बाद वे रिटायर हो जाएंगे और परिवार को ज्यादा समय देंगे. यश चोपड़ा की प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्मस आज बॉलीवुड की सबसे नामी और प्रतिष्ठित फिल्म बैनर है.■

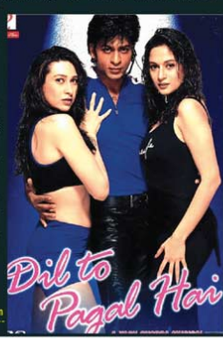

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com